RNI NO. 45823/1986 REGISTRATION NO. DL(DS)-02/MP/2022-23-24, DL(ND)-11/6042/2024-25-26; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2024-26; FARIDABAD/46/2023-25 www.indiatodayhindi.com

एक्सक्लूसिव बातचीतः ''मोदी 3.0 में टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलाव हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होंगे'' —निर्मला सीतारमण

8 मई, 2024 50 रुपए

इंडिया टुडे

अर्थशास्त्र मोदी का

कामयाबी और नाकामियां

देश की अर्थव्यवस्था एक अहम चुनावी मामला. उसी के आईने में कुछ प्रमुख आर्थिक पैमानों पर मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का आकलन

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित, एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित, कुल पन्नों की संख्या 68 (आवरण सहित) वर्ष 38; अंक: 23

अल्ट्राटेक
सीमेंट
इंजीनियर की पसंद
देश का नं.1 सीमेंट

ADITYA BIRLA
CEMENT

बनेगा तो बढ़ेगा इंडिया

अपनों के लिए समय बढ़ जाता है,
जब किसी शहर में एक नई मेट्रो लाइन बन जाती है।

गाँव के बच्चे भी चाँद पे पहुँचने का सपना देख पाते हैं,
जब नए रोड के साथ साइंस गाँव तक पहुँच जाता है।

और देश की सुरक्षा कर रहे हमारे जवानों का हौसला और भी बढ़ जाता है,
जब सरहद पे एक मज़बूत पुल बन जाता है।

अल्ट्राटेक में हम मानते हैं कि किसी भी मेट्रो, पुल या सड़क का महत्व
उसकी विशालता से नहीं, बल्कि लोगों की ज़िन्दगी में उसके प्रभाव से होता है।

क्योंकि, जब भी देश में कुछ बनता है तो उससे लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती हैं।

यही विश्वास **अल्ट्राटेक** में हमें प्रेरित करता है,
देश के निर्माण में सहयोग देते रहने के लिए।

'अल्ट्राटेक, देश का नं.1 सीमेंट' - क्लेम के विवरण के लिए ultratechcement.com पर विज़िट करें

प्रधान संपादक की कलम से

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक पहचान बतानी हो तो लोग आम तौर पर व्यक्तित्व के संदर्भ में ही बात करते हैं. करिश्माई शख्सियत सरीखे पहलू जो तमाम दूसरी चीजों पर हावी हैं. लेकिन शासन व्यवस्था अपनी तरह के व्यक्तित्व गढ़ती है, जो किसी नेता का सच्चा पैमाना होते हैं. फरवरी में *इंडिया टुडे* के छमाही 'देश का मिज़ाज सर्वे' से पता चला कि आर्थिक वृद्धि के अलावा बेरोजगारी और महंगाई दो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भारत की जनता सबसे ज्यादा फिक्रमंद है. इन दिनों जब सात चरणों के आम चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, बहुतेरा राजनैतिक विमर्श आजीविका से जुड़े इन दो मुद्दों के इर्द-गिर्द केंद्रित है. तीसरा कार्यकाल पाने के लिए मोदी ने भविष्य की दूरदृष्टि यानी 2047 तक देश को पूरी तरह विकसित राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य सामने रखा है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 'मोदी की गारंटी' नारे को चुनाव प्रचार की अपनी टेक और मुख्य मंत्र के तौर पर अपना लिया है. वह अर्थव्यवस्था को संभालने के प्रधानमंत्री के 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को नतीजे देने की उनकी क्षमता के प्रमाण के तौर पर पेश कर रही है. वहीं विपक्ष की आलोचनाओं में बेरोजगारी और महंगाई सबसे अव्वल और उनके अभियान के वादों का मूलमंत्र हैं.

बयानों और लफ्फाजियों की रिपोर्ट भर देने के बजाए हमने आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज का तथ्यात्मक आकलन करने का फैसला किया. इसे मोदीनॉमिक्स यानी मोदी का अर्थशास्त्र कहा जाता है. विशेषज्ञों की राय में इसका लुब्बोलुबाब राजकोषीय समझदारी और निवेश आधारित वृद्धि है, जिसमें लक्ष्यबद्ध और टेक्नोलॉजी के जरिए जनकल्याणवाद के जोरदार मसालों का तड़का लगा है. यहीं मोदी की राजकीय शख्सियत के प्रमुख पहलू उभरते हैं. तत्काल तुष्टि के प्रलोभन से बचते हुए उनकी दूरदृष्टि का झुकाव निर्णायक तौर पर लंबे वक्त की तरफ दिखता है. कड़वी गोली निगलने की यह क्षमता हमने कोविड के झटके के दौरान और बाद में भी देखी. भारत की अर्थव्यवस्था उस वक्त भी न केवल टिकी रही बल्कि और धूमधाम से उबरकर आई जब दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही थीं. वित्त वर्ष 2024 में देश की जीडीपी के शानदार 7.6 फीसद की दर से बढ़ने का अनुमान है, जिसने उसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया. यह इत्तेफाकन नहीं हुआ. देश इस राह पर सीधे-सीधे मोदी के उन सोचे-समझे (और कठिन) फैसलों की बदौलत चल सका जिसमें उन्होंने महामारी से लड़ते वक्त फिजूलखर्ची के बजाए आर्थिक तौर पर अनुदार या रूढ़िवादी होना चुना. उन्होंने दहशत से पैदा वह गलती नहीं की जो पश्चिमी देशों ने भारी-भरकम प्रोत्साहन पैकेज लाकर की थी.

27 अप्रैल, 2022

ऊपरी सुधार के बजाए बुनियाद को सुरक्षित करने में इस यकीन की बदौलत ही मोदी ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया. रेलवे पर पूंजीगत खर्च 2014 से हर साल तिगुना होता गया, जिसके नतीजतन हैरतअंगेज 25,871 किमी नई पटरियां बिछाई गईं, जबकि 37,000 किमी से ज्यादा का विद्युतीकरण किया गया. ऐसे प्रभावशाली आंकड़े आपको चौतरफा दिखते हैं, चाहे वह राजमार्ग हों, शिपिंग या हवाई रास्ते. बुनियादी ढांचे पर यह जोर इस गहरे आंतरिक विश्वास से आता है कि इससे नौकरियां मिलती हैं और आर्थिक वृद्धि भी तेज होती है. अलबत्ता जीडीपी के आंकड़े सम्मानजनक होते हुए भी हरेक विश्लेषण अंग्रेजी के 'के' अक्षर के आकार की वृद्धि की तरफ इशारा कर रहा है: अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, गरीबों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, और ग्रामीण मजदूरी में भी गिरावट. सरकारी आंकड़े कोविड के बाद बेरोजगारी के आंकड़ों में गिरावट दिखा रहे हैं, वहीं इन आंकड़ों की गहराई में जाने पर बारीकियां सामने आती हैं. काम में लगे सभी लोगों में 57 फीसद स्वरोजगार कर रहे हैं. कई नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जो असुरक्षित भी हैं और बेरोजगारी का संकेत भी. करीब 21.8 फीसद कैजुअल लेबर हैं. भारत के कार्यबल का महज 20.9 फीसद औपचारिक नौकरियों के दायरे में आता है.

इस पैटर्न पर ज्यों ही ध्यान गया और आलोचनाएं होने लगीं, खासकर महामारी के बाद, तो मोदी ने दुश्वारियां कम करने और एक बड़ी आबादी को गरीबी के मुंह में जाने से बचाने के लिए जनकल्याण के उपायों पर जोर दिया. मसलन, मुफ्त अनाज योजना, जिसके दायरे में 81 करोड़ गरीब-गुरबे हैं. मगर यह इस बात का भी सबूत है कि पिरामिड के तल पर हालात कितने खौफनाक हैं. आम लोगों के हाथों में अतिरिक्त धन की कमी से मांग कम हो जाती है, उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नहीं रह जाता, और इसलिए निवेशकों में जोखिम लेने की भूख मंद पड़ जाती है. कॉर्पोरेट टैक्स में कटौतियों के बावजूद निजी निवेश नहीं बढ़ पाने से आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं. यही भारतीय अर्थव्यवस्था की विकट पहेली है और सरकार की परेशानी भी.

साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश एयर इंडिया के बाद धीमा पड़ा है, और मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के 15 फीसद पर ठहरी हुई है. उधर, वित्त वर्ष 2022-23 के साथ खत्म पांच वर्षों की अवधि में कृषि की वृद्धि दर 4 फीसद के औसत पर सुस्त बनी रही, और वित्त वर्ष 2023-24 में गिरकर 1.8 फीसद पर आ गई. मौसम के डावांडोल मिजाज की वजह से अगले साल भी एक फीसद से कम वृद्धि का अनुमान है, जिससे जीडीपी पर गहरा प्रतिकूल असर बने रहने का अंदेशा है. भूराजनैतिक तनावों की वजह से बाहरी माहौल भी अनुकूल नहीं रहा, और भूमंडलीकरण के उलटने के रुझानों का मतलब यह है कि निर्यात पर्याप्त जोश से नहीं बढ़ रहे हैं और 'चाइना प्लस वन' रणनीति की तरफ दुनिया के रुख का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं. इसके अलावा समझदार राजकोषीय प्रबंधन और जीएसटी के जाल के बढ़ते फैलाव से अर्थव्यवस्था के औपचारिक बनने की गति बढ़ी है और सरकारी राजस्व में इजाफा हुआ है. अलबत्ता सरकार को उत्साह और विश्वास बनाए रखना चाहिए क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य का दृष्टिकोण ज्यादातर मामलों में सकारात्मक दिख रहा है.

इस अंक में हम मोदीनॉमिक्स की कामयाबियों और चूकों का समग्र नक्शा पेश कर रहे हैं, जो हमारे सारे ब्यूरो ने मिलकर संजोया है, ताकि मतदाता तमाम हो-हल्ले और हुल्लड़ के बीच से मतलब की बात समझकर फैसला कर सकें.

हालांकि अंतिम जज तो आखिरकार लोकतंत्र ही है.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.com

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन और कार्यकारी प्रधान संपादक: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: सौरभ द्विवेदी
डिप्टी एडिटर: मोहम्मद वक़ास
सीनियर एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, प्रतीक्षा
एसोसिएट एडिटर: पवन वर्मा
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुमित सिंह
वरिष्ठ विशेष संवाददाता: हिमांशु शेखर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), पुष्यमित्र (पटना), आनंद चौधरी (जयपुर), देवेश तिवारी (रायपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: चंद्रदीप कुमार, राजवंत रावत
मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
डिप्टी विजुअल रिसर्च एडिटर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
सीनियर एसोसिएट पब्लिशर (इंपैक्ट):
सुपर्णा कुमार
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ ऐंड ईस्ट), जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: सैयद नवीद (चेन्नै)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 38; अंक: 23; 2-8 मई 2024; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, ई-मेल: wecare@intoday.com
फोन/व्हाट्सऐप: +91 8597 778778 (सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक)
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-69193355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

जनादेश 2024
गांधीनगर: घरेलू मैदान में शाह पेज 6

हैदराबाद: घिर गए ओवैसी पेज 10

भीतर

मैसूरु: बहुमत तलाशते 'महाराजा' पेज 11

फुरसत
सवाल-जवाब/चेतन भगत: अब जीने के कायदों पर किताब पेज 68

चंद्रदीप कुमार

आवरण कथा

अर्थशास्त्र मोदी का

कामयाबी और नाकामियां

अर्थव्यवस्था की स्थिति एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है. ऐसे में प्रमुख आर्थिक मापदंडों पर मोदी सरकार के कामकाज का आकलन.

46
खास बातचीत
निर्मला सीतारमण

54 **उत्तर प्रदेश**
धमक दिखाने उतरा मुलायम का परिवार
आम चुनाव में भाग्य आजमा रहे अखिलेश यादव समेत मुलायम परिवार के पांच सदस्य. कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ को फिर से जीतने की चुनौती.

आवरण: नीलांजन दास

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों के विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

पतंजलि®

केश कान्ति
एडवांस

टूटना मना है!

30 जड़ी-बूटियों की शक्ति

से बालों को मिले सम्पूर्ण पोषण

बालों का टूटना रोके • नये बाल उगाये
• डैमेज्ड बालों को रिपेयर करे • बालों को असमय सफेद होने से बचाये
• स्कैल्प को डैंड्रफ फ्री बनाये

जनादेश 2024 | गांधीनगर

घरेलू मैदान में शाह

दूसरे कार्यकाल के लिए गांधीनगर से चुनाव लड़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री विशाल जनादेश पाने की गरज से विकास और गुजराती गौरव के नारे पर भरोसा कर रहे हैं. मगर नौकरियों और क्षत्रिय विवाद से जीत का अंतर कम होने का अंदेशा

जुमाना शाह गांधीनगर में

गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में पहली बार 5,57,000 से ज्यादा वोटों के जबरदस्त अंतर से जीत दर्ज की थी और इस बार दूसरे कार्यकाल के लिए अपना परचा दाखिल करने से ठीक दो दिन पहले वे उन 30 वोटरों से मिलने गए जिन्हें पन्ना प्रमुख बनाया गया है. पन्ना मतदाता सूची का वह पन्ना है जिस पर दर्ज वोटरों का समर्थन जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक प्रमुख या प्रभारी नियुक्त किया है. अगले दिन गहन चुनाव अभियान के बीच एक करीबी के घर पर पत्नी सोनल के साथ पारंपरिक गुजराती भोजन के लिए आए शाह बताते हैं, ''सत्ताइस मतदाताओं ने पुष्टि की कि वे मतदान के दिन 10.30 बजे से पहले अपना वोट (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी जी के पक्ष में देंगे. बाकी तीन का बाहर जाने का कार्यक्रम है, मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे कार्यक्रम बदलें और बाद में बाहर जाएं.''

उसी दिन 18 अप्रैल को 59 वर्षीय शाह ने मिनी ट्रक पर बनाए गए अस्थायी रथ पर सवार होकर चिलचिलाती धूप में अपने नेता की

मजबूत पकड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (बीच में) 18 अप्रैल को गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान. उनके साथ हैं गुजरात प्रदेश भाजपा प्रमुख सी.आर. पाटील (बाएं) और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

एक झलक पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे समर्थकों की तरफ हाथ हिलाया. 10 घंटे के अपने रोड शो के खत्म होने पर वेजलपुर की सभा में उन्होंने कहा, ''अपने हाथ उठाकर संकल्प लें कि 7 मई को सुबह 10.30 बजे से पहले कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) को वोट देंगे,'' और एक साथ सारे हाथ ऊपर उठ गए. उन्होंने आगे कहा, ''अब मैं निश्चिंत होकर देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव अभियान के लिए जाऊंगा और यहां वोट के दिन ही लौटूंगा.''

गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में बीस लाख से ज्यादा मतदाता हैं और शाह का दावा है कि उनकी टीम तकरीबन हरेक घर में कम से कम एक बार जा चुकी है. हरेक ब्योरे पर बारीकी से ध्यान देना, हजारों समर्पित पैदल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, और साथ ही प्रधानमंत्री पद के लिए आपड़ो मानस (अपना आदमी/ गुजराती) को वोट देने की चुनावी अपील शाह के आत्मविश्वास की कुंजी हैं—इस कदर कि 19 अप्रैल को अपना परचा दाखिल करने से पहले उन्होंने मात्र एक दिन रैलियां और रोड शो करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिताया.

गांधीनगर भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, जहां से पार्टी के दिग्गज नेता एल.के. आडवाणी लंबे समय तक सांसद रहे और 2019 में शाह ने ही उनकी जगह ली. पार्टी के पितृपुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 1996 में लखनऊ के अलावा गांधीनगर से भी चुनाव लड़ा था, पर दोनों सीटें जीतने के बाद लखनऊ की ही नुमाइंदगी करते रहने का फैसला किया. भाजपा के वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) में राजनीति का ककहरा सीखने के बाद शाह तब प्रमुखता से उभरे जब 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आडवाणी का चुनाव प्रबंधक बनाया गया. लेकिन शाह को एक खास फायदा हासिल है जो उनके पूर्ववर्ती के पास नहीं था—वे स्थानीय हैं. शाह का पैतृक गांव मनसा गांधीनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आता है. वे पहली बार 1997 में तत्कालीन सरखेज सीट से गुजरात विधानसभा में पहुंचे और 2012 के परिसीमन में इस सीट के खत्म होने तक इसकी नुमाइंदगी की. बाद में वे नारणपुरा से चुनकर राज्य विधानसभा में आए और यहां भी उनका मकान है. वेजलपुर की रैली में उन्होंने याद दिलाया, ''एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में मैं नारणपुरा की दीवारों पर कमल का चिह्न पेंट किया करता था.''

गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सात विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिनमें से चार—नारणपुरा, वेजलपुर, घाटलोदिया और साबरमती—मुख्य रूप से शहरी हैं और अहमदाबाद जिले में आते हैं. बाकी तीन—गांधीनगर उत्तर, कलोल और साणंद—में कई गांव हैं और उनका भी तेजी से शहरीकरण हो रहा है. गांधीनगर दरअसल भाजपा के विकास के नारे की एक मिसाल है, जहां बुनियादी ढांचे की कई बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं और जो देश भर के किसी भी दूसरे शहरी केंद्र के मुकाबले बेजोड़ है. इनमें मोदी की दो दुलारी योजनाएं भी शामिल हैं—एक, जीआइएफटी या गिफ्ट सिटी, जो भारत का पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, और दूसरा मोटेरा में सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम मोदी के नाम पर रखा गया है. असल में वेजलपुर के अपने भाषण में शाह ने ऐलान किया कि गांधीनगर में 2036 के ग्रीष्म ओलंपिक की मेजबानी 'मोदी की गारंटी' है, बावजूद इसके कि भारत को दुनिया के इस सबसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी के लिए जर्मनी, इटली, कनाडा, चीन और दक्षिण कोरिया सरीखे देशों से मुकाबला करना पड़ रहा है.

इस स्पोर्ट्स एन्क्लेव के सामने साबरमती मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब में विशाल गलियारों का निर्माण चल रहा है. गुजरात का टर्मिनल या अंतिम बुलेट ट्रेन स्टेशन इसी हब में है. जापान की शिंकानसेन पर आधारित मुंबई-अहमदाबाद हाइ स्पीड रेल (एमएएसएसआर) परियोजना पर करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इससे दोनों टर्मिनल हब के बीच यात्रा का समय 5-7 घंटे से घटकर मात्र दो घंटे से कुछ ज्यादा रह जाएगा. करीब 30 किमी दूर साणंद को ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहीं पर अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से भारत में पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ला रही है, जिससे वर्ष 2025 तक 20,000 नौकरियां पैदा होने

बेधड़क लहराता भगवा

भाजपा ने 1989 के बाद से गांधीनगर सीट कभी नहीं हारी है. पार्टी के दिग्गज एल.के. आडवाणी ने यहां से छह बार जीत दर्ज की, यहां तक कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में यहां से जीत दर्ज की और फिर इसे छोड़कर लखनऊ सीट अपने पास रखी

आंकड़े वोट प्रतिशत के हैं

की उम्मीद है. उधर, गिफ्ट सिटी में 550 से ज्यादा संस्थाओं ने काम करना शुरू कर दिया है और वे 26,000 से ज्यादा नौकरियों की पेशकश कर रही हैं.

मगर गिफ्ट सिटी से सटे शाहपुर गांव में 65 वर्षीय किसान गणेश वाघेला नौकरियों के मामले में बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करते हैं. ग्राम पंचायत दफ्तर के बाहर बैठे वाघेला अफसोस के साथ कहते हैं, ''स्थानीय लोग बेरोजगार हैं जबकि गिफ्ट सिटी में बाहरी लोगों को नौकरियां मिल गई हैं. यहां तक कि पढ़े-लिखे नौजवानों को भी 10,000-20,000 रुपए महीने कमाई वाली अस्थाई, ब्लू कॉलर नौकरियां ही मिल पाती हैं.'' यह बताते हुए कि उनका गांव फिर भी भाजपा को ही वोट देगा, वाघेला कहते हैं कि सरकार को नौकरियों और महंगाई के मामले में तेजी से कदम उठाने चाहिए. हालांकि, दूसरी जगहों पर भी इसी तरह की भावनाएं सुनाई देती हैं, पर शाह जोर देकर कहते हैं कि गांधीनगर को तो छोड़ ही दें, देश में कहीं भी नौकरियों की कमी नहीं है. उन्होंने *इंडिया टुडे* से कहा, ''सरकार ने कई सारे आइटीआइ (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) स्थापित किए हैं. स्थानीय युवाओं को उद्योग विशेष के हुनर से लैस करने के लिए एक मिनी आइटीआइ साणंद में भी बनाया है... काम करने के इच्छुक लोगों के लिए काम के बहुत सारे अवसर हैं.'' (देखें शाह के साथ बातचीत).

गांधीनगर में मजबूत मुकाबला नहीं होने की धारणा से भी भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा है. 62 वर्षीय वास्तुकार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) की सचिव सोनल पटेल इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं. कांग्रेस पहले अभिनेता राजेश खन्ना (1996 का उपचुनाव) और पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन (1999) सरीखे नामी-गिरामी उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर भाजपा के इस गढ़ को बेधने की नाकाम कोशिशें कर चुकी है. 2019 में उसके उम्मीदवार और जमीन से जुड़े नेता सी.जे. चावड़ा, जिन्होंने शाह के 8,94,624 वोटों के मुकाबले 3,37,610 वोट हासिल किए थे, पिछले साल पाला बदलकर भाजपा में चले गए और साथ ही हो रहा विजापुर का विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं.

भाजपा के मूल हिंदुत्व के मुद्दे का

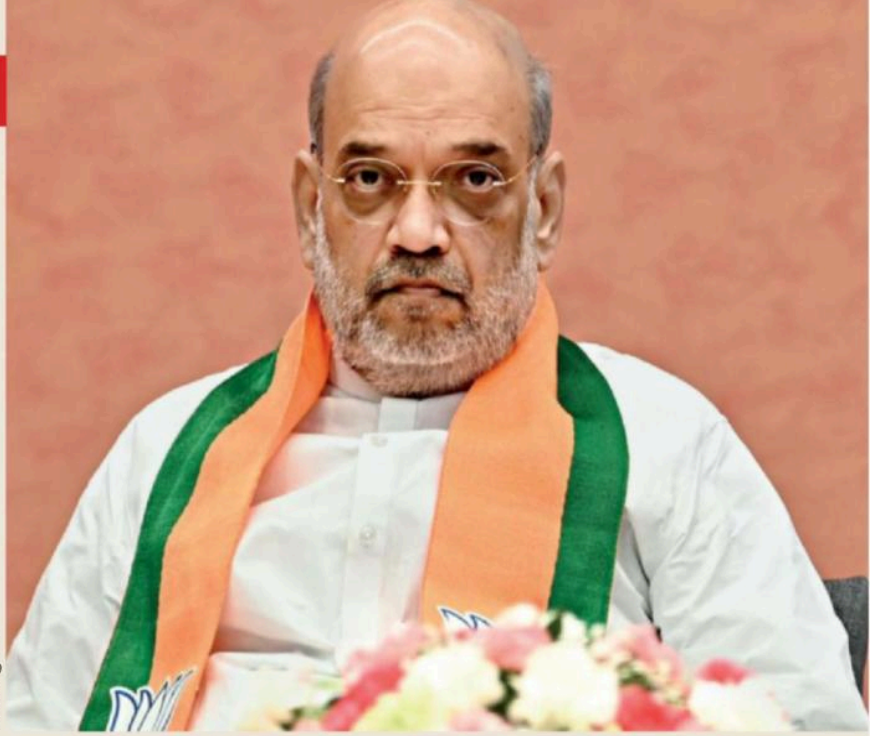

चंद्रदीप कुमार

"काम करने के इच्छुक लोगों के लिए काफी नौकरियां हैं"

गांधीनगर में रोड शो और रैलियों के थकान भरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ा-सा वक्त निकाला और सीनियर एसोसिएट एडिटर जुमाना शाह के साथ खुलकर बातचीत की. बेरोजगारी को गैर-मुद्दा कहकर खरिज करते हुए और विरोध कर रहे क्षत्रियों को मनाने की भाजपा नेतृत्व की क्षमता में भरोसा जताते हुए शाह ने दावा किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बातचीत के अंशः

प्र. गांधीनगर में मुख्य मुद्दे क्या हैं?

यहां तो कोई मुद्दा बचा ही नहीं है. अकेला एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है. गांधीनगर अत्यधिक विकसित निर्वाचन क्षेत्र है. यहां बुलेट ट्रेन (प्रस्तावित मुंबई-अहमदाबाद हाइ स्पीड रेल गलियारा) और मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम (नरेंद्र मोदी स्टेडियम) और गिफ्ट सिटी (भारत का पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) है. हमने यहां सरकार की सारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं. यहां का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां चौबीसों घंटे बिजली न मिलती हो. एक भी घर ऐसा नहीं है जहां एलपीजी कनेक्शन या पीने का पानी या राशन कार्ड न हो. सभी योजनाएं यहां हर हकदार व्यक्ति तक पहुंची हैं.

● क्षत्रियों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा और दरअसल पूरे राज्य में फैल गया है इसका भाजपा पर कैसा असर पड़ेगा?

हम समुदाय से बातचीत कर रहे हैं... वे हमारे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे भाजपा के खिलाफ वोट नहीं देंगे. बातचीत चल रही है और जल्द ही समाधान निकलेगा.

● उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने पर आधा दर्जन सीटों पर भाजपा का विरोध हुआ था. इससे पार्टी की संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा?

कार्यकर्ताओं में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर कोई समझता है कि 2047 तक

विकसित भारत बनाने का मोदीजी का संकल्प पूरा करना निजी मुद्दों से कहीं ज्यादा जरूरी और अहम है. सभी परेशानियां हल की गई हैं. हमने गुजरात में सभी सीटें 5,00,000 के अंतर से जीतने का लक्ष्य तय किया है और हम इसे हासिल करेंगे.

● पढ़े-लिखे नौजवानों में काफी बेरोजगारी और महंगाई कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं.

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बेरोजगारी समस्या है. साणंद और दूसरी जगहों के उद्योगों ने खाली पदों के विज्ञापन के लिए बोर्ड लगाएं हैं. अगर युवा नौकरियां चाहते हैं, तो ऐसे उद्योग हैं जो नौकरियां देना चाहते हैं. कमाई के कई अवसर हैं... मैंने डेटा निकलवाया है कि अहमदाबाद में 22,000 डिलिवरी पर्सन हैं. क्या ये नौकरियां नहीं हैं?

● मगर युवा नौकरियों में स्थिरता और सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं. केवल गिग नौकरियां नहीं.

काम करने के इच्छुक लोगों के लिए नौकरियों के काफी अवसर हैं.

● आपने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि 2036 के ग्रीष्म ओलंपिक गांधीनगर में आयोजित किए जाएंगे. लेकिन जब कई भारतीय शहरों में ओलंपिक खेलों के आयोजन की क्षमता है, तो गांधीनगर ही क्यों?

क्योंकि ओलंपिक के आयोजन के लिए विस्तृत बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है और इसमें से काफी कुछ अहमदाबाद-गांधीनगर में मौजूद है. सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है. इसके चारों तरफ दूसरे बुनियादी ढांचों के विकास के लिए जमीन मौजूद है... जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए मददगार है.

● आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक दिन प्रचार किया. उम्मीदवार के तौर पर यह आपके लिए कैसे कारगर होगा?

मैं यहां पला-बढ़ा हूं, यह मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं. मैं 20 साल विधायक रहा हूं. मैं यहां दीवारों पर कमल (भाजपा का चुनाव चिन्ह) के चित्र बनाया करता था और पोस्टर चिपकाया करता था. मैं यहां केवल मोदीजी का संदेश देने आया हूं...कि उनके हाथ मजबूत करें. हमारा डबल-इंजन का नेतृत्व और पन्ना समितियां (पार्टी कार्यकर्ता जिन्हें समर्थन जुटाने के लिए मतदाता सूचियों का एक-एक पन्ना सौंपा गया है) पक्का करेंगी कि सभी वोटर मतदान के दिन 10:30 बजे तक अपने वोट डाल दें.

मुकाबला करना पटेल के लिए खासी चुनौती है, जिनका आरोप है कि राम मंदिर के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाना और भाषणों में भगवान राम का नाम लेना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. मगर कांग्रेस की उम्मीदवार शाह के कथित फायदे को खारिज करते हुए दावा करती हैं कि इस निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता विरोधी भावना साफ महसूस की जा सकती है. लेउवा पाटीदार समुदाय से आने वाली पटेल का कहना है कि 2015-17 के आरक्षण आंदोलन के दौरान पाटीदार युवाओं की मौत को लेकर न्याय की मांग गांधीनगर में अब भी गूंज रही है, जहां इस समुदाय के 15 फीसद मतदाता हैं.

के मतदाताओं में क्षत्रिय 15 फीसद हैं, और ऐसे में राज्य के नेता स्वीकार करते हैं कि इस विवाद से शाह की जीत का अंतर कम हो सकता है, खासकर जब समुदाय के आधे वोट पार्टी के हाथ से जा सकते हैं. रांदेसान गांव में भाजपा के स्थानीय नेता राजेंद्र सिंह वाघेला कहते हैं, ''पारंपरिक तौर पर हम एकमुश्त भाजपा को वोट देते थे, पर इस बार क्षत्रियों का मुद्दा छाया हुआ है. हम देखेंगे कि समुदाय क्या तय करता है.'' अलबत्ता शाह को यकीन है कि मतदान के दिन से पहले समाधान निकल आएगा.

अपनी झोली में क्षत्रिय वोटों का छींका टूटकर गिरने की संभावना के

“भाजपा का आत्मविश्वास गायब हो गया है. इसे सभी समुदायों का बिना शर्त समर्थन हासिल नहीं है, जिनके साथ इसने अब तक गलत किया है”

सोनल पटेल, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सचिव और पार्टी की गांधीनगर से प्रत्याशी

महिला मतदाताओं में बेचैनी का आरोप लगाते हुए पटेल कहती हैं, ''जब हमारी महिला प्रचारक गांवों में घर-घर जाती हैं, महिलाएं सरकार के प्रति अपना असंतोष जाहिर करती हैं, लेकिन खुलकर बोलने से डरती हैं.'' उन्हें कम से कम इतना भरोसा तो है ही कि क्षत्रिय महिलाएं इस बार भाजपा के खिलाफ वोट देंगी.

पारंपरिक तौर पर योद्धा जाति क्षत्रिय समुदाय के लोग केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला का तीव्र विरोध कर रहे हैं. इसकी वजह रूपाला का वह विवादास्पद बयान है जिसमें उन्होंने क्षत्रिय शाही परिवारों के सदस्यों के ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ घुलने-मिलने और उनके साथ अपनी बेटियों की शादी तक कर देने की बात कही थी. यह विरोध शुरू में सौराष्ट्र तक ही सीमित था, पर रूपाला को राजकोट के अपने उम्मीदवार के तौर पर बदलने से भाजपा के इनकार से दूसरी जगहों पर भी विरोध होने लगा. गांधीनगर

अलावा सोनल पटेल दलितों (15 फीसद) और मुसलमानों (10 फीसद) के समर्थन पर भरोसा करके चल रही हैं, देश की सबसे बड़ी मुस्लिम बस्तियों में से एक जुहापुरा इसी निर्वाचन क्षेत्र में आती है. कभी यह उस सरखेज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी जिसकी नुमाइंदगी शाह ने 15 साल की. अपनी लंबे वक्त से चली आ रही रणनीति को बरकरार रखते हुए भाजपा ने मुसलमानों के बीच पहुंचने की न्यूनतम कोशिश की है. अलबत्ता उसने हाल के सक्रिय ग्रामीण प्रचार अभियान के जरिए महिला मतदाताओं के बीच कांग्रेस उम्मीदवार के 'लैंगिक फायदे' को बेअसर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की पत्नी और पटेल की नामराशि सोनल शाह को मैदान में उतारा है. जीत पाना तो खैर बहुत मुश्किल है, सवाल यह है कि कांग्रेस गांधीनगर में कोई ठोस लाभ भी हासिल कर पाती है या नहीं. ■

घिर गए ओवैसी

असदुद्दीन ओवैसी और उनकी एआइएमआइएम अपने गढ़ हैदराबाद में दबाव महसूस कर रहे हैं

अमरनाथ के. मेनन

जंग की तैयार एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी 19 अप्रैल को हैदराबाद में लोकसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के बाद

एएनआइ

चार दशकों से हैदराबाद ओवैसी परिवार और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआइएमआइएम) का गढ़ बना हुआ है. इस दौरान हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के साथ पार्टी ने सात सीटें जीतकर विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. खासकर पुराने शहर के मुस्लिम बहुल इलाकों में. इनमें से एक नामपल्ली तो हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बाहर पड़ता है. हालांकि, इस लोकसभा क्षेत्र के भीतर गोशामहल विधानसभा सीट से पार्टी को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है. भाजपा के मुस्लिम विरोधी विवादास्पद नेता टी. राजा सिंह (जिनके खिलाफ करीब 105 आपराधिक मामले दर्ज हैं) ने गोशामहल सीट से 2014 में अपने चुनावी पदार्पण के बाद से तीन बार जीत दर्ज की है.

2014 के बाद से, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी का अपने पारंपरिक गढ़ में वोट शेयर कम हो गया है. नवंबर-दिसंबर 2023 के पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी दो तय सीटों नामपल्ली और याकूतपुरा में हारते-हारते बची. याकूतपुरा सीट तो वह बमुश्किल 878 वोटों से जीत सकी. तो क्या एआइएमआइएम पकड़ खो रही है? ऐसे वक्त में जब फायरब्रान्ड पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का ख्वाब देख रहे हैं, उसको लेकर मुसलमानों के बीच ही राय बंटी हुई है. भले ही विधानसभा चुनावों में एआइएमआइएम का वोट शेयर कम हुआ है, पर उसके सुप्रीमो ने 2014 और 2019 में 50 फीसद से अधिक वोट लेकर हैदराबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की. दोनों बार भाजपा के भगवंत राव उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे.

इस बार भगवा खेमे ने महिला प्रत्याशी और अस्पताल मालिक कोम्पेला माधवी लता को उतारा है. पार्टी में शामिल होने और मार्च में चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही उन्होंने अपनी राह पकड़ ली थी और वे राव को मिलने वाले तकरीबन 2,30,000 वोटों को अपने पाले में मजबूत करने के साथ नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए सहानुभूति रखने वाले 1,00,000 अन्य वोटों को भी लुभाने की कोशिश कर रही हैं. लता ने पहले ही दांव चल दिया. उन्होंने शुरुआत में ही ऐलान किया, ''मैं यहां पीएम मोदी के मिशन को पूरा करने आई हूं...उन्होंने मुझे किसी की पतंग को काटने के लिए भेजा है.'' पतंग एआइएमआइएम का चुनाव चिह्न है. शिक्षाविद् गद्दाम श्रीनिवास यादव (बीआरएस) और जिला कांग्रेस अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह जंग के अन्य प्रत्याशी हैं.

2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एआइएमआइएम पक्की मानी जाने वाली अपनी दो सीटें बड़ी मुश्किल से जीत पाई थी

हालांकि 17 अप्रैल को पुराने शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान लता उस समय आलोचनाओं के घेरे में आ गईं जब सिद्दीयंबर बाजार मस्जिद पर निशाना साधकर हाथ से तीर चलाने का इशारा करने का उनका वीडिया वायरल हो गया. इस पर आक्रोश के बाद लता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगने को मजबूर होना पड़ा. दूसरी ओर, ओवैसी उस आक्रोश से हासिल किए जा सकने वाले हर लाभ को उठा लेने को प्रतिबद्ध थे और उन्होंने यह भी हैरानी जताई कि आखिर चुनाव आयोग ने उस मामले को लेकर आंखें बंद क्यों कर रखी हैं. उन्होंने सवाल किया, ''हैदराबाद के लोगों ने भाजपा के इरादों को देखा...क्या यही 'विकसित भारत' है जिसकी बात भाजपा कर रही है? चुनाव अपनी जगह है. जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि

तेलंगाना और हैदराबाद की शांति...यहां कायम भाईचारा जिसे वे (भाजपा) खत्म करना चाहते हैं.'' एक शिकायत के बाद, हैदराबाद पुलिस ने लता के खिलाफ केस दर्ज किया है.

एआइएमआइएम के इस बार दबाव में होने के पीछे विश्लेषक कई फैक्टर बताते हैं. पहला यह कि पूर्व में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार और ये दोनों

मजबूत किला

विधानसभा चुनाव में पार्टी की लोकप्रियता घटने के बावजूद हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी का गढ़ बनी हुई है

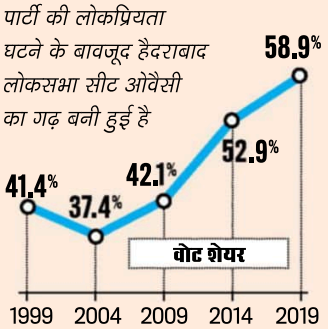

एक दूसरे का खामोशी से समर्थन करते थे. बीआरएस की चुनावी संभावनाएं अब ढलान पर हैं. दूसरी बात मुस्लिम असंतोष है; वे पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, मगर उनमें यह भी एहसास है कि एआइएमआइएम अपने सारे वादों को पूरा नहीं कर रही है. फिर, धारणा का भी मसला है.

एआइएमआइएम कई वजहों के हलकान है. भले ही यह मुस्लिम पहचान पर आधारित पार्टी है, फिर भी इसे 'भारतीय मुसलमानों की पार्टी' के तौर पर व्यापक स्वीकृति और राजनैतिक वैधता हासिल करना अभी बाकी है. भारत की आबादी का 14 फीसद (2011 जनगणना के अनुसार) मुस्लिम समुदाय है, मगर यह देशभर में बिखरा हुआ है, इसलिए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कोई अखिल भारतीय मुस्लिम पार्टी अव्यावहारिक है.

फिर भी, उनके जैसा कोई अन्य नेता नहीं है जिसने लगातार मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मुद्दों और चिंताओं को उठाया हो. यह इकलौती पार्टी है (मुस्लिम लीग या आइयूएमएल को छोड़कर) जो मुस्लिम युवाओं की बढ़ती सियासी आकांक्षाओं को जगह देती है. हालांकि, उनके गढ़ हैदराबाद में, विधायकों और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम समेत स्थानीय निकायों के उसके प्रतिनिधियों ने समुदाय के लिए क्या किया है, इसको लेकर धारणा खराब हुई है. लोगों का मानना है कि उन्होंने पर्याप्त कामकाज नहीं किया है, खासकर पुराने शहर के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए. वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अफसर जहां का कहना है, ''सिंगल मदर्स की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, मादक पदार्थों और शराब के अत्यधिक सेवन और दुरुपयोग के बढ़ते मामले, आजीविका की चिंता, यह सब गरीब मुसलमानों को चुनावी राजनीति से दूर कर रही हैं.''

राष्ट्रीय स्तर पर एआइएमआइएम के 'महत्व' को नकारा नहीं जा सकता, खासकर अधिक मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी कम-से-कम ऐसी सात सीटें हार गई, जहां एआइएमआइएम उम्मीदवारों को हार के अंतर से अधिक वोट मिले. यही वजह है कि विपक्षी दलों ने एआइएमआइएम को 'भाजपा की बी टीम' बताया है, और शायद यही कारण है कि ओवैसी को इंडिया गठबंधन से बाहर रखा गया है.

ओवैसी की ताकत अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर मुखरता है. उनका कहना है कि भाजपा को अल्पसंख्यकों से केवल नफरत है, और पार्टी अपने घोषणापत्र में 'अल्पसंख्यक' शब्द का जिक्र करने से भी बचती है. नाराज ओवैसी कहते हैं, ''बस 17 अप्रैल को विभिन्न समाचार पत्रों ने भाजपा का विज्ञापन देख लें. जब वे कारोबार शुरू करने के लिए सरकारी ऋण या मदद की बात करते हैं तो वे केवल एससी/एसटी और ओबीसी के लिए वैसा कहते हैं. मुस्लिम तो भूल जाइए, भाजपा को तो अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र करना भी गवारा नहीं.''

मगर इससे उनके अपने विधायकों की निष्क्रियता के आरोपों से छूट नहीं मिल जाती. हैदराबाद बीते कई वर्षों से ओवैसी के पक्ष में रहा है, मगर अगर असंतोष के स्वर तेज होते हैं तो यह एआइएमआइएम प्रमुख के लिए चिंता की बात होगी. ■

मैसूरु

बहुमत तलाशते 'महाराजा'

भाजपा ने मैसूरु के पूर्व शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है जो सिद्धारमैया का गृहनगर है

अजय सुकुमारन

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मैसूरू को 23वें स्थान पर रखा गया था. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय साल 2014 से सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित करता है. कर्नाटक के इस 'महलों के शहर' के लिए रैंकिंग की यह पायदान बेहद तेज गिरावट थी क्योंकि सर्वेक्षण के पहले संस्करण में उसे देश का सबसे स्वच्छ शहर माना गया था. यह शहर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने को उत्सुक है और 600 साल से अधिक पुराने मैसूरू शाही परिवार के प्रतीकात्मक प्रमुख यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार भी इसकी मिसाल नजर आर रहे हैं. शहर में महाराजा कॉलेज के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मेगा रैली के एक दिन बाद 15 अप्रैल को पूर्व शाही परिवार के 32 वर्षीय वंशज यदुवीर को आयोजन स्थल की सफाई करते नगर निगम कार्यकर्ताओं का हाथ बंटाते देखा गया. मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक यदुवीर को मई 2015 में वाडियार परिवार का 27वां संरक्षक नियुक्त किया गया था.

हालांकि यदुवीर के लिए वह स्वच्छता अभियान साफ-सफाई को लेकर मैसूरू की खोई हुई चमक को वापस लाने की कोशिश से कहीं बढ़कर है. इसे शाही वंशज की ओर से उन विरोधियों को गलत साबित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है जो दावा करते हैं कि 'महाराजा' आम पहुंच से बाहर रहने वाले शख्स हैं क्योंकि वे 'महल में रहते हैं.' वहीं, इन आम चुनावों में मैसूरू-कोडागु लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार यदुवीर को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाना

जनता के बीच
चामुंडेश्वरी में प्रचार के दौरान यदुवीर कृष्णदत्ता चामराज वाडियार

मधुसूदन एस.आर.

जरूरी है जो जनता तक पहुंच सके और उनका प्रतिनिधित्व कर सके. 20 अप्रैल को मैसूरू शहर के बाहरी इलाके के गांवों में ऊपर से खुले वाहन के जरिए अपने प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार ने कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की. उन्होंने कहा, ''मेरे पूर्वज भी महल में पैदा हुए और पले-बढ़े, फिर भी उन्होंने लोगों के बीच काम किया. मैं भी उन्हीं सिद्धांतों का पालन करूंगा.'' उन्होंने कहा कि मैसूरू के पूर्ववर्ती शासकों ने इस इलाके में स्वर्ण युग की शुरुआत की थी, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए स्वर्ण युग का आगाज कर रहे हैं. हम सभी को उनका समर्थन करना है.

मैसूरू-कोडागु संसदीय सीट पर 2014 से भाजपा की मजबूत पकड़ है. पिछले दोनों चुनावों में पार्टी के मौजूदा सांसद प्रताप सिंह ने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी को 2014 में 31,000 तो 2019 में 1.38 लाख से अधिक वोटों से हराया था. हालांकि, इस बार भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र में यदुवीर के रूप में एक नया चेहरा लेकर आई है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, यदुवीर को मैसूरू से चुनावी मैदान में उतारना मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों में पूर्व शाही परिवार के सदस्यों के प्रति सम्मान है.

32 वर्षीय यदुवीर अपने परिवार से राजनीति में किस्मत आजमाने वाले पहले शख्स नहीं हैं. उनसे पहले उनके दादा श्रीकांत दत्ता नरसिंहराजा वाडियार मैसूरू से चार बार सांसद रहे थे. इस सीट पर 26 अप्रैल को लोकसभा 2024 के लिए दूसरे चरण में मतदान है और यदुवीर के खिलाफ कांग्रेस के एम. लक्ष्मण मैदान में हैं. लक्ष्मण अपनी पार्टी के प्रवक्ता और इलाके का स्थानीय चेहरा हैं. हालांकि वाडियार वंशज को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पार पानी होगी. मैसूरू दिग्गज कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया का गृहनगर है और यह दो लोकसभा क्षेत्रों मैसूरू-कोडागु और चामराजनगर में फैला हुआ है. सिद्धारमैया ने लक्ष्मण और चामराजनगर से उम्मीदवार सुनील बोस के पीछे अपनी सारी ताकत झोंक दी है. मैसूरू-कोडागु उम्मीदवार ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो मुख्यमंत्री ने 3 अप्रैल को एक रैली में कहा,

सिद्धारमैया ने मैसूरू-कोडागु में कांग्रेस प्रत्याशी एम. लक्ष्मण के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. उनका कहना है, ''अगर लक्ष्मण जीतते हैं तो वह मेरे जीतने सरीखा होगा''

''अगर आप सिद्धारैमया की विश्वसनीयता बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मण को जिताना होगा. अगर लक्ष्मण जीतते हैं तो वह मेरे जीतने सरीखा होगा.''

कांग्रेस जहां अपनी कल्याणकारी वादों और मैसूरू में सिद्धारमैया की लोकप्रियता पर भरोसा कर रही है, वहीं वह समान रूप से जाति कार्ड भी खेल रही है. दरअसल, लक्ष्मण प्रभावशाली वोक्कालिगा समुदाय से हैं जिसे कर्नाटक में दूसरा सबसे बड़ा जाति समूह माना जाता है. इस बीच, विरासत और विकास, यदुवीर के दो चुनावी मुद्दे हैं और उनका कहना है कि ये मैसूरू की मुख्य चिंताएं हैं. उन्होंने *इंडिया टुडे* से कहा, ''हम अपनी विरासत और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस निर्वाचन क्षेत्र का प्राकृतिक विकास करना चाहते हैं तथा आगे बढ़ना चाहते हैं. हमारे गांव के वातावरण और पर्यावरण को भी संरक्षण की जरूरत है, मगर हमें शहरी केंद्रों को भी सभी सुविधाओं और विकास की आवश्यकता है. इसलिए हमें वह दोनों काम करने की जरूरत है और अपनी प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने के साथ-साथ आधुनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने की जरूरत है.''

राजनैतिक विश्लेषक मुजफ्फर असादी का कहना है कि विजेता का फैसला करने में एक अहम कारक यह होगा कि महिलाएं किस तरह मतदान करती हैं जो कांग्रेस की गारंटियों की लाभार्थी हैं. यह बताते हुए कि दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है, असादी कहते हैं, ''यह एक नजदीकी लड़ाई होने वाली है.'' ■

समर्थकों के दिल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से उनके समर्थकों का उत्साह और बढ़ गया है

एएनआइ

आप की अग्निपरीक्षा का वक्त

अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के रूप में अपने शीर्ष नेतृत्व की गैरमौजूदगी में आम आदमी पार्टी सांगठनिक स्तर पर खुद को किस तरह से तैयार कर रही

हिमांशु शेखर

गए मंगलवार यानी 16 अप्रैल को दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपनी संकल्प सभाओं की शुरुआत की. ठिकाना था राष्ट्रीय राजधानी के आंबेडकर नगर की जोशी कॉलोनी. पास की ही बस्ती मदनगीर में फोटो कॉपी की दुकान चलाने वाले 37 वर्षीय सुभाष कुमार भी उसमें शामिल होने आए थे. इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से ही वे अरविंद केजरीवाल से जुड़े हैं. उन्हीं के शब्दों में, ''कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद जब मैंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते सुना, तभी से उनका प्रशंसक हो गया. आम आदमी पार्टी बनने पर उसके कार्यक्रमों में भी जाने लगा. पूरा समय तो पार्टी को नहीं दे पाया लेकिन रोजी-रोटी चलाते हुए साथ जुड़ा रहा. जिस केजरीवाल ने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डालने से सबको समझ आ रहा है कि यह भाजपा की साजिश है.'' इसी तरह की बातें सभा में मौजूद और भी कई लोगों ने कहीं.

तो क्या केजरीवाल और आप के पीछे के कार्यकर्ताओं की

फौज अब भी जस की तस बरकरार है? थोड़ा ठहरें. सरकारी सेवा से रिटायर एक बुजुर्ग देर तक इधर-उधर की बात करने के बाद खुलते हैं, ''आप की सभाओं में अब अपेक्षाकृत कम लोग आ रहे हैं. कुछ दिन पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर पार्टी के धरने में कितने कम लोग आए थे. एक दौर था कि जंतर मंतर रोड एक छोर से दूसरे छोर तक पैक रहता था.'' ऐसा क्यों? वे जवाब देते हैं, ''आप के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों में अंत में भले कोई सचाई न निकले पर बहुत-से कार्यकर्ताओं-समर्थकों के मन में संदेह पैदा हो गया है. यही कि जिनके पीछे वे दिन-रात लगे हुए थे, वे भी औरों जैसे ही निकले!'' इस बुजुर्ग का दावा था कि कई लोग व्यक्तिगत उम्मीद में आप से जुड़े थे. ऐसे लोग भी निराशा में साथ छोड़ रहे हैं.

आंबेडकर नगर की इस सभा में और 16 अप्रैल को ही दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए विरोध प्रदर्शन में आप कार्यकर्ताओं से बात करने पर एक बात गौर करने लायक मिली. यही कि विरोध-प्रदर्शनों में आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है. हालांकि, पार्टी के नेता इससे इनकार करते हैं. उनका तर्क है कि वर्किंग डे और गर्मी की वजह से कभी-कभी किसी कार्यक्रम में लोग थोड़ी कम संख्या में आते हैं और ऐसा हर पार्टी के साथ होता है.

आप के शीर्ष नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले से संबंधित मामले में अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं. केजरीवाल और सिसौदिया की जोड़ी पुरानी है. वे दोनों कबीर संस्था बनाकर सूचना का अधिकार को लेकर काम करते थे. इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वैसे तो कई और बड़े लोग थे लेकिन व्यावहारिक तौर पर नेतृत्व केजरीवाल-सिसौदिया ही कर रहे थे. हाल तक आप के एक और वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में थे. केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्हें जमानत मिली है. इसी तरह से पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं.

शराब घोटाले के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की योजना आम आदमी पार्टी को ही अभियुक्त बनाने की है. ईडी का दावा है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के लिए किया गया, इसलिए उसे पार्टी को अभियुक्त बनाने की छूट मिलनी चाहिए. ईडी का कहना है कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के तहत कंपनी की जो परिभाषा है, उसके आधार पर आप को एक कंपनी माना जा सकता है और अभियुक्त बनाया जा सकता है. हालांकि, आप के वकील अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को खारिज करते हैं कि किसी राजनैतिक दल को कंपनी मानने का कोई प्रावधान कानून में है. अगर अदालत ईडी को एक पार्टी के तौर पर आप को अभियुक्त बनाने की छूट दे देती है तो आप का सांगठनिक संकट बढ़ जाएगा. केजरीवाल-सिसौदिया की जोड़ी के एक साथ जेल में होने की वजह से आप के लिए न सिर्फ दिल्ली सरकार चलाना एक चुनौती है बल्कि पार्टी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करते हुए खुद को मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती है.

दोनों शीर्ष नेताओं की गैरमौजूदगी में उनकी सांगठनिक जिम्मेदारियां कौन निभा रहा है? पार्टी नेता इसका सीधा जवाब देने से बचते हैं. अलग-अलग नेताओं से बातचीत में एक बात समझ में आती है कि पहले तो असमंजस-ऊहापोह था पर अनुभवी नेता संजय सिंह के बाहर आने के बाद हालात काफी हद तक संभले हैं. केजरीवाल-सिसौदिया की अनुपस्थिति में अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज संजय सिंह के साथ दिखते हैं. केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी हैं पर वे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखतीं. उनकी भूमिका खुद को पीछे रखकर काम करने की ज्यादा है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पार्टी दिल्ली से बाहर अपनी संभावनाएं मजबूत करने को इस्तेमाल कर रही है. मान की सभाएं उन लोकसभा क्षेत्रों में हो रही हैं, जहां आप के उम्मीदवार अच्छे मुकाबले की स्थिति में हैं. राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वे न सिर्फ दिल्ली में संगठन को एकजुट रखने में जुटे हैं बल्कि प्रदेश के बाहर भी पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत बनाने का काम करते हैं. हाल में वे केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल गए थे.

पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसके शीर्ष नेता केजरीवाल चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे. ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रख पाना मुश्किल होगा. केजरीवाल को अदालत से राहत न मिली तो फिर चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति क्या होगी? पाठक कहते हैं, ''हर चीज की स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय में लिखी जा रही है. ऐसे में कोई एजेंडा बनाना मुश्किल है. यह इस पर निर्भर करता है कि भाजपा आगे क्या करती है.''

तो क्या पार्टी भाजपा की चालों को देखते हुए अपनी रणनीति बनाएगी? चुनाव के लिए अपनी कोई तैयारी नहीं? आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय बताते हैं, ''हमने 'जेल

किसके कंधे पर क्या जिम्मा

भगवंत मान,
मुख्यमंत्री, पंजाब
पंजाब के अलावा दिल्ली के बाहर की चुनावी जिम्मेदारी. मान देश भर में उन सीटों पर सभाएं कर रहे हैं, जहां आप के उम्मीदवार मुकाबले की स्थिति में हैं.

सुनीता केजरीवाल,
मुख्यमंत्री की पत्नी
रणनीतिक निर्णय में प्रमुख भूमिका लेकिन पर्दे के पीछे से. गुजरात के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल.

संजय सिंह,
राज्यसभा सांसद
अभी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का सबसे अहम चेहरा. राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते नियमित तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल का बचाव करना और भाजपा पर आक्रामक रहना. इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ समन्वय की जिम्मेदारी.

अतिशी,
मंत्री, दिल्ली सरकार
मुख्य रूप से दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी. पार्टी के घोषणापत्र और नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका. पार्टी का प्रमुख महिला चेहरा.

सौरभ भारद्वाज,
मंत्री, दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी के साथ-साथ संगठन में भी प्रमुख निर्णयों में शामिल. नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और उप-राज्यपाल के खिलाफ आक्रामक तेवर बनाए हुए.

गोपाल राय,
पार्टी के दिल्ली संयोजक
दिल्ली में प्रचार अभियान को नेतृत्व देने से लेकर विभिन्न रणनीतियों के निर्माण में भूमिका.

संदीप पाठक, *संगठन के राष्ट्रीय महासचिव*
दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी संगठन को एकजुट और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की जिम्मेदारी.

बुलंद इरादे: आम आदमी पार्टी 'जेल का जवाब वोट से' नामक संकल्प सभाएं करके समर्थक जुटाने की कोशिश कर रही है

एएनआइ

का जवाब वोट से संकल्प सभा' की शुरुआत की है. हर लोकसभा क्षेत्र में हम 40 ऐसी सभाएं करेंगे. इसमें पार्टी के सभी विधायक लगेंगे. सभाओं में हमारे नेता और कार्यकर्ता जेल का जवाब वोट से देने का संकल्प लेंगे.'' यह अभियान 23 मई तक चलेगा. 16 अप्रैल को इसकी शुरुआत संजय सिंह ने आंबेडकर नगर से और गोपाल राय ने विश्वास नगर से की.

हालांकि, इन सभाओं को लेकर भी एक राजनीति चल रही है. आप इस बार का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है. इसके तहत दिल्ली की चार लोकसभा सीटें आप को और तीन कांग्रेस को मिली हैं. आप इन सभाओं का आयोजन उन्हीं संसदीय क्षेत्रों में कर रही है, जहां उसके उम्मीदवार मैदान में हैं. जिन संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उन इलाकों के आप विधायकों को भी आप की चार सीटों के अलग-अलग क्षेत्रों में सभा करने की जिम्मेदारी दी गई है. मसलन, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी से आप विधायक ऋतुराज को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है. यहां से आप के उम्मीदवार सही राम पहलवान हैं. इस रणनीति से स्पष्ट है कि इन सभाओं के माध्यम से आप अपने संगठन को मजबूत करते हुए अधिक से अधिक वोट बटोरने की कोशिश कर रही है.

पार्टी के एक नेता कहते हैं कि संगठन के लिहाज से देखें तो आप में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से कार्यकर्ता आए थे. एक ऐसे समय में जब आप नेतृत्व के मामले में संकट की स्थिति में दिख रही है तो भाजपा से आए कार्यकर्ताओं को अपने साथ बरकरार रखना एक चुनौती है. वे कहते हैं कि राम मंदिर से लेकर हिंदुत्व के तमाम मुद्दों पर आप का रुख एक तरफ हिंदू वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने की रणनीति का हिस्सा है तो दूसरी तरफ भाजपा पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ताओं को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश भी है.

केजरीवाल की गिरफ्तारी से तकरीबन तीन हफ्ते पहले 4 मार्च को जब दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने 2024-25 के लिए तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया तो पता चला कि इसकी केंद्रीय थीम 'राम राज्य' रखी गई है. आप अब इसे और आगे बढ़ा रही है. 17 अप्रैल यानी ठीक रामनवमी के दिन आप ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो कैंपेन वेबसाइट लॉन्च किया उसका नाम 'आप का राम राज्य' रखा. इस वेबसाइट को खोलने पर होम पेज पर ही लिखा आता है—क्या है आपका राम राज्य. इसके नीचे लिखा है, ''दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, क्या है आप की राम राज्य की संकल्पना.'' यह लिंक एक वीडियो पर ले जाता है जिसमें केजरीवाल राम राज्य के बारे में बताते हैं. इसके अलावा वेबसाइट में यह जानकारी दी गई है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री अपने नौ वर्षों के कार्यकाल में क्या-क्या किया है और विभिन्न विषयों पर पार्टी का क्या विजन है और उसके चुनावी वादे क्या हैं. हालांकि, राम और हनुमान को लेकर आप का यह प्रेम नया नहीं है. बल्कि केजरीवाल कई मौकों पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाते रहे हैं और उन्होंने पूरी दिल्ली में इसी साल जनवरी में सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया था.

क्या दिल्ली में होने वाली तकरीबन 200 संकल्प सभाएं और पार्टी की अन्य गतिविधियां केजरीवाल-सिसौदिया की गैरमौजूदगी में आप को संगठित रख पाएंगी? इसके जवाब में कुछ साल पहले आप से अलग हुए एक नेता बताते हैं, ''संजय सिंह का जेल से बाहर आना पार्टी के लिए अच्छा रहा. उनकी गैरमौजूदगी में अगर सुनीता केजरीवाल को नेता बनाने की कोशिश होती तो दिक्कतें आतीं. आप में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या है जिनकी ज्यादा दिलचस्पी दिल्ली प्रदेश की राजनीति में है क्योंकि उनके छोटे-मोटे कारोबार हैं. अगर कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद आप लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सीटें जीतने या अच्छा वोट लाने में कामयाब नहीं होती है, तब संगठन के स्तर पर ऐसी स्थिति आ सकती है कि पार्टी में भगदड़ देखी जाए.''■

An IMPACT Presentation

SOUTH INDIA

EMERGING AS A HUB OF EDUCATIONAL EXCELLENCE

With a rich historical legacy of renowned institutions, South India has long been synonymous with academic excellence. Its vibrant metropolises boast a plethora of esteemed universities and research centres, premier medical institutions dot the region, nurturing talent across diverse fields. Moreover, the emergence of technology parks and start-up incubators has catalysed innovation and entrepreneurship, transforming the academic landscape. South India is also witnessing a surge in educational opportunities in emerging fields such as biotechnology, nanotechnology, and renewable energy. The higher education institutions of South India are not only contributing to the intellectual capital of the region but the entire country. South India pre-eminence as a hub of higher education is a testament to its commitment to academic excellence, research prowess, and fostering an environment conducive to innovation and learning.

SATHYABAMA
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)
CATEGORY - 1 UNIVERSITY BY UGC
ACCREDITED WITH GRADE
A++
NAAC
RANKED
51
Among
India's Top 100 Universities
for Seven Consecutive Years
NIRF RANKING 2023
For Details, Contact:
+91 99400 58263 | 99401 68007 | 99400 69538
Toll-Free Number: 1800 425 1770
ENGINEERING | ARCHITECTURE | MANAGEMENT | ARTS & SCIENCE
LAW | DENTAL | PHARMACY | NURSING | PHYSIOTHERAPY
www.sathyabama.ac.in
SathyabamaOfficial
SathyabamaSIST
sathyabama.official
@sathyabamaofficial

SOUTH INDIA A BEACON OF HIGHER EDUCATION EXCELLENCE

South India, renowned for its rich cultural heritage and diverse traditions, has emerged as a prominent hub of higher education excellence in the last several decades, with a special focus on technical and professional education. The reasons for this are manifold.

Since ancient times, Southern India has been a centre of education. This legacy has now been carried on to the present. Add to that external factors like excellent connectivity, a peaceful socio-cultural milieu and English as the prevalent medium of studies and you have all the makings of a thriving education hub.

Educational institutions in the region pride themselves on excellent standards of education and good placement records. South India's spend on higher education has been the highest. With high literacy rates, the region also enjoys some of the best Gross Enrolment Ration (GER) and Pupil-Teacher Ratio in India. Cities like Chennai, Coimbatore, Bengaluru, Mysuru and Hyderabad are major educational hubs and both public and private universities offer excellent courses and attract meritorious students.

Among the southern states, Tamil Nadu shines prominently as a hub for advanced learning, attracting students from across the nation. As an education hub, Tamil Nadu has always attracted students for the quality of education especially in the engineering and technical streams with a proven record in academics, a special focus on inclusive education and outstanding results in job placements across engineering colleges and universities providing good education quality. One of the most literate states in India, Tamil Nadu consistently leads in the NIRF rankings of the top 100 colleges in India and offers degrees in coveted disciplines like Medical, Engineering, Management, Law, Architecture and Mass Communications.

According to the recently released All India Survey on Higher Education by the Ministry of Education, Government of India, Tamil Nadu's GER (the number of students enrolled in higher education as a percentage of the eligible population aged 18 to 23 years) was 47 per cent. According to the report, GER is "a key indicator of the level of participation in higher education within a given population. Higher GER values indicate greater enrolment in higher education among the specified age group". For comparison, the all-India average GER was 28.4 per cent in the 2021-22 period. Tamil Nadu has consistently maintained the highest GER among the larger Indian states.

As an education hub, Tamil Nadu has always attracted students for the quality of education especially in the engineering and technical streams with a proven record in academics, a special focus on inclusive education and outstanding results in job placements across engineering colleges and universities providing good education quality.

SATHYABAMA
INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)
CATEGORY - 1 UNIVERSITY BY UGC

ACCREDITED WITH GRADE A++ NAAC

RESEARCH FACILITY @ SATHYABAMA

- Materials Synthesis and Characterization
- Battery Fabrication and Testing
- CCSEA Approved Preclinical & Translational Research
- Bio Imaging and Cellular Architecture
- 3D Organoid Printing
- FACS - Multiomics Research Platform
- Artificial Intelligence, Drones & Robotics, Metaverse Studio
- Vector Borne Disease Research
- Bioenergy and Wastewater Remediation
- Impact of Climate Change on Marine Organisms
- Multiband Satellite Remote Sensing
- Additive Manufacturing
- Fish Breeding and Aquatic Animal Husbandry
- Biofermentation and Downstreaming
- Environmental Trace Elements Assessment
- Open Ocean Exposure Facility

For admissions, contact: +91 99400 58263 | +91 99401 68007 | +91 99400 69538
To know more information, visit our website at www.sathyabama.ac.in

ENGINEERING | ARCHITECTURE | MANAGEMENT | ARTS & SCIENCE
LAW | DENTAL | PHARMACY | NURSING | PHYSIOTHERAPY

अर्थशास्त्र मोदी का कामयाबी और नाकामियां

देश की अर्थव्यवस्था एक अहम चुनावी मामला. उसी के आईने में कुछ प्रमुख आर्थिक पैमानों पर मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का आकलन

राज चेंगप्पा और एम.जी. अरुण

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

प्रतिष्ठित लेखक सैमुअल बटलर ने 1903 छपे अपने उपन्यास *द वे ऑफ ऑल फ्लेश* में लिखते हैं, 'खुद ही अपनी पीठ थपथपाने या गुण गान करने का लाभ यह है कि उसे पूरे वजन के साथ बिल्कुल माकूल मौके पर फिट किया जा सकता है.' इस फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दस साल के आर्थिक एजेंडे की तुलना मनमोहन सिंह के कार्यकाल से करने के लिए संसद में श्वेत-पत्र पेश करते वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ''दशक भर में ही हम (मनमोहन सिंह के कार्यकाल में) फ्रेजाइल फाइव (लड़खड़ते पांच) से शीर्ष पांच की लीग में पहुंच गए.'' यह सही है कि जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में मनमोहन सिंह के बाद सत्ता संभाली थी तब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब वह 37 खरब डॉलर (308 लाख करोड़ रुपए) की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. फिर, कोविड-19 महामारी के दौरान एकदम गर्त में पहुंची देश की अर्थव्यवस्था में मोदी सरकार वित्त वर्ष 2024 में 7.6 फीसद की प्रभावी वृद्धि के साथ जान फूंकने में कामयाब हुई है. इससे हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं. ये उपलब्धियां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में युद्धघोष और केंद्र में लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल करने के खातिर मूलमंत्र बन गई हैं. प्रधानमंत्री प्रचार रैलियों में खुद के नाम पर 'मोदी की गारंटी' की बात करते हैं, और आजादी के सौ साल पूरे होने पर 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का अपना नजरिया पेश करते हैं. यही नहीं, वे अगले तीन साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तात्कालिक वादा भी करते हैं. इस तरह वे बताते हैं कि उनकी सरकार और उन्हें बतौर प्रधानमंत्री लगातार तीसरा कार्यकाल मिला तो अर्थव्यवस्था में तेजी से गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों के जीवन में व्यापक सुधार होगा.

बटलर की अपनी प्रशंसा खुद करने वाली टिप्पणी दूसरों की लानत-मलामत करने के मामले में भी सही बैठती है. भाजपा के अपने आर्थिक गुणगान से मुकाबला करने के लिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मनमोहन सरकार के आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड की आलोचना के जवाब में न सिर्फ फौरन 'काला पत्र' जारी किया, बल्कि मोदी सरकार की 'नाकामियों' की फेहरिस्त भी बना डाली, जिसमें ''भारी बेरोजगारी दर, नोटबंदी तथा जीएसटी जैसी आर्थिक तबाही लाने वाले कदमों से अमीर-गरीब के बीच खाई चौड़ी हुई और लाखों किसानों तथा दिहाड़ी मजदूरों के भविष्य को तबाह कर दिया है.'' लेकिन भाजपा का अपना प्रशंसा-गान

जारी है, तो कांग्रेस ने भी मोदी सरकार की नाकामियों को अपने चुनाव अभियान का बदस्तूर हिस्सा बना लिया है. राहुल गांधी ने इसे ''दस साल अन्याय काल के खिलाफ न्याय की लड़ाई'' कहा है, और बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गैर-बराबरी की आर्थिकी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और उन्हें पार्टी के प्रमुख आर्थिक मुद्दे बना डाला है.

आर्थिक, खासकर रोजगार तथा नौकरियों का अभाव, महंगाई और समान तथा बराबरी वाले विकास का मुद्दा दरअसल 2024 के चुनाव में बेहद अहम बनकर उभरा है. यहां तक कि जनमत सर्वेक्षणों में भी ये मुद्दे वोटरों की सबसे बड़ी चिंता की तरह दर्ज किए गए हैं. देश में चुनाव अमूमन कई मसलों पर जीते-हारे जाते हैं, जिनमें भावनात्मक अपील, जन-धारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा,

देश में चुनाव कई मुद्दों पर जीते और हारे जाते हैं, जिनमें भावनात्मक अपील, जन-धारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनैतिक स्थिरता, परिवार और जाति के आग्रह वगैरह होते हैं, लेकिन आर्थिक मुद्दे सब पर भारी पड़ते हैं

कामयाब | जीडीपी

शानदार वापसी

महामारी और युद्धों के बावजूद 7 फीसद से अधिक की जीडीपी वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, हालांकि इस गति को बरकरार रख पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है

दरअसल, यूपीए-दो सरकार के आखिर के दो साल में नीतिगत पंगुता के कारण निवेश और पूंजी दोनों बाहर चले गए थे. शायद यही वजह है कि ज्यादा वृद्धि, अधिक निवेश और अधिक रोजगार के एनडीए के नैरेटिव—संक्षेप में कहें तो अच्छे दिन—ने मतदाताओं को उससे जोड़ा और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई. मगर निजी निवेश लाने के लिए सुधारों और कॉर्पोरेट करों में कमी के बावजूद मोदी सरकार के शुरुआती वर्षों में वृद्धि नरम ही रही. सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोविड-19 महामारी ने एक और झटका दिया और वित्त वर्ष 21 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि औंधे मुंह गिरकर ऋणात्मक-23.9 फीसद पर पहुंच गई और पूरे वर्ष के लिए यह ऋणात्मक 5.53 फीसद रही.

इसकी वापसी धीमी थी. उपभोक्ता से जुड़ी सेवाएं जैसे यात्रा, रिटेल, हॉस्पिटेलिटी और पर्यटन आखिर में पटरी पर लौटे. भारत में अर्थव्यवस्था की बहाली हुई, मगर सरकार के ज्यादा पूंजी खर्च के दम पर. वित्त वर्ष 22 में वृद्धि फिर 9 फीसद पर पहुंच गई, वैसे इसका कारण कम आधार रहा. वित्त वर्ष 23 ने इस बहाली की बेहतर तस्वीर पेश की और जीडीपी में 7.2 फीसद की वृद्धि हुई. केंद्र का 'भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र' दावा करता है कि वित्त वर्ष 05 और वित्त वर्ष 14 के बीच प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी जहां 3,889 डॉलर (3.2 लाख रुपए) था, वहीं वित्त वर्ष 15 और 23 के बीच यह 6,016 डॉलर (4.99 लाख रुपए) रहा. मुंबई के अर्थशास्त्री यह कहते हुए इसे खारिज करते हैं कि इन अवधियों के बीच तुलना नहीं हो सकती ''क्योंकि (जीडीपी आंकड़ों की गणना के) आधार वर्ष बदल गए हैं और पिछली शृंखलाएं अब अप्रासंगिक हैं. इसलिए उनमें त्रुटि की गुंजाइश है.''

इलस्ट्रेशनः राज वर्मा

"लगातार दो वर्षों तक 7 फीसद से ज्यादा की वृद्धि अच्छा रिकॉर्ड और शुभ संकेत है, मगर अभी तक की वृद्धि सरकारी निवेश के दम पर हुई है. अगले दो वर्षों में यह इसी गति से बरकरार नहीं रह सकती. निजी निवेश लाना ही होगा"

अजित रानाडे, कुलपति, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ऐंड इकोनॉमिक्स

सरकार के नवीनतम अनुमान वित्त वर्ष 24 में जीडीपी वृद्धि 7.6 फीसद रहने की बात कहते हैं. वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि वृद्धि सरकार की उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकती है और पूरे वित्त वर्ष 25 में यह बरकरार रह सकती है. भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वर ने दो अध्याय के 'द इंडियन इकोनॉमी-ए रिव्यू' की भूमिका में कुछ इसी तरह की बात कही है, ''अगर वित्त वर्ष 25 के

राजनैतिक स्थिरता, परिवार और जाति संबंधी आग्रह वगैरह होते हैं, लेकिन आर्थिक मुद्दे सब पर भारी पड़ते हैं और कई मौकों पर नतीजे भी तय करते हैं. मसलन, इमरजेंसी की हार के बाद इंदिरा गांधी 1980 में प्याज की बढ़ती कीमतों को मुख्य एजेंडा बनाकर जनता पार्टी की सरकार को हराकर सत्ता में वापस आ गई थीं. हाल के दौर में, 2009 में अर्थव्यवस्था में

रसातल और उसके बाद

कोविड ने भारत की वृद्धि की दास्तान को पटरी से उतार दिया था, मगर भारत ने फिर ऊंचाई की राह पकड़ ली

जीडीपी वार्षिक वृद्धि दर (%)

*अनुमानित

स्रोतः सीएमआइई इकोनॉमिक आउटलुक

अनुमान सही साबित होते हैं तो महामारी के बाद यह चौथा साल होगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7 फीसद से ज्यादा की दर से बढ़ेगी जो इसकी मजबूती और संभावनाओं को दर्शाएगी.''

अर्थशास्त्री उपलब्धियों की तारीफ करते हैं, पर कहते हैं कि अभी काफी कुछ करने की जरूरत है. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ऐंड इकोनॉमिक्स के कुलपति अजित रानाडे कहते हैं, ''मंदी और युद्ध की चुनौतियों के बावजूद लगातार दो वर्ष तक 7 फीसद से ज्यादा वृद्धि अच्छा रिकॉर्ड और शुभ संकेत है. अभी तक की वृद्धि सरकारी निवेश के दम पर हुई है. अगले दो वर्ष में यह इसी गति से बरकरार नहीं रह सकती. सरकारी निवेश की जगह निजी निवेश लाना ही होगा.'' बाहरी कारक भी चुनौती पेश कर रहे हैं, खासकर यूक्रेन और पश्चिम एशिया के युद्ध और लाल सागर में बाधाएं. *–एम.जी. अरुण*

नाकाम 'के' आकार ग्रोथ

लाभ में असमानता

जहां संगठित क्षेत्र आगे बढ़ा, वहीं असंगठित क्षेत्र पीछे बना हुआ है, नतीजतन अंग्रेजी के अक्षर 'के' आकार की वृद्धि हुई

अब यह स्पष्ट है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अकेला भारत ही उम्मीद की किरण है. वैसे, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोविड के बाद देश की वृद्धि अंग्रेजी के 'के' अक्षर की तरह हुई है–जहां समाज के संपन्न वर्ग के अधिक खर्च के कारण महंगे सामान की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं आमजन के बाजार के सामान की मांग उससे कम रही है. हालांकि सरकार इस विचार को खारिज करती है, साथ ही कुछ विशेषज्ञ भी.

"असंगठित क्षेत्र महामारी के पहले के कारोबार वाली स्थिति में अब भी नहीं पहुंच पाया है और लगातार ढलान पर है. इसलिए रोजगार की कमी बरकरार है, और इसका आमदनी तथा ग्रामीण मांग पर असर पड़ रहा है"

सुनील कुमार सिन्हा, सीनियर डायरेक्टर, इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च

मगर, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में यह विभाजन जाहिर होता है. यह सूचकांक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों को मापता है. वित्त वर्ष 14 में यह 3.3 फीसद था जो वित्त वर्ष 24 में (जनवरी तक) बढ़कर 5.5 फीसद हो गया. इसमें इजाफा मुख्य रूप से सरकार के खर्च करने से बुनियादी ढांचे, इस्पात और सीमेंट में वृद्धि के कारण हुआ. मगर उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल (खाद्य, परिधान, ग्रोसरी आदि) में बढ़ोतरी कम हुई है या घटी है. ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, परिधान, टिकाऊ उपभोक्ता सामान के प्रीमियम उत्पादों की श्रेणियां ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि आमजन के उत्पाद, जो एक ज्यादा बड़ा बाजार है, या तो स्थिर हैं या फिर उनकी वृद्धि घट रही है. ऑटो सेक्टर की बिक्री में भी यह रुझान दिखता है जहां हैचबैक जैसी कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री में 42 फीसद की गिरावट देखी गई, वहीं दूसरी तरफ 20 लाख रुपए से कम की एसयूवी की बिक्री में 25 फीसद से अधिक की उछाल आई है.

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च में सीनियर डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा इसके लिए कोविड के बाद औपचारिक क्षेत्र में हुई स्वस्थ बहाली को जिम्मेदार मानते हैं जिसे नोटबंदी, जीएसटी लागू होने और फिर महामारी के लगातार झटके लगे थे. मगर, दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र ऐसी बहाली नहीं कर पाया. इस रेटिंग एजेंसी के एक विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी जगत, जो उच्च आय श्रेणी में शीर्ष 50 फीसद का प्रतिनिधि है, में पिछले दो साल में वेतन भत्ते 10 फीसद से अधिक बढ़े हैं–वित्त वर्ष 22 में 11.6 फीसद तो वित्त वर्ष 23 में 10.7 फीसद. मगर कम आय श्रेणी वाले कृषि ग्रामीण मजदूरों और शहरी क्षेत्रों के कुशल कामगारों की मजदूरी में या तो कोई वृद्धि नहीं हुई या घट गई. शहरी क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी वित्त वर्ष 22 में 3 फीसद घटी, जबकि वित्त वर्ष 23 में 0.55 फीसद की कमी आई. कृषि आय जो ग्रामीण मजदूरी का आईना होती है, वित्त वर्ष 22 में 3.4 फीसद घटी और वित्त वर्ष 23 में महज एक फीसद बढ़ी है. भारतीय अर्थव्यवस्था में इस दोहरेपन से असमानता बढ़ेगी और निकट भविष्य में टिकाऊ वृद्धि में बाधा पहुंचेगी. *–सोनल खेत्रपाल*

दुनिया अलग-अलग

शहरी और ग्रामीण इलाकों में वास्तविक वेतन वृद्धि

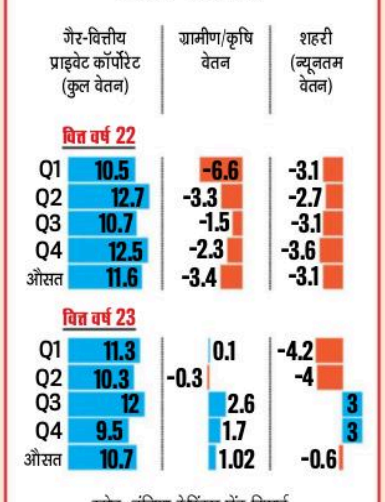

स्रोतः इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च

ग्राफिक्सः तन्मय चक्रवर्ती

चंद्रदीप कुमार

तूफान पर काबू

महामारी और दूसरे मुल्कों में युद्ध की स्थिति से कीमतों में वृद्धि से नीतिगत उपायों और रेपो दर में बढ़ोतरी से निबटना पड़ा

नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ऊंची कीमतें 2014 से ही परेशानी का सबब बनी हुई हैं. इसके दूसरे कार्यकाल में महामारी और यूक्रेन तथा पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग से हालात और बदतर हुए हैं.

आरबीआइ और केंद्र सरकार के कई उपायों से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) महंगाई 2014-15 और 2022-23 के बीच औसतन 5 फीसद पर टिकी रही. अप्रैल 2020 में महंगाई बढ़कर 7.2 फीसद और अक्तूबर में 7.6 फीसद हो गई, जो आरबीआइ की 6 फीसद सीमा से काफी ऊपर थी. आरबीआइ पर खपत को बढ़ावा देने के लिए महामारी के दौरान ब्याज दरों को कम रखने का दबाव था, मगर मई, 2022 से यह अनिवार्यता खत्म हो गई. आरबीआइ ने रेपो दर (जिस पर वह वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है) में 2.5 फीसद अंक—मई, 2022 में 4 फीसद से फरवरी 2023 में 6.5 फीसद—की वृद्धि की. महंगाई दर घटने के बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया. इस बीच केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम किया, गेहूं निर्यात रोक दिया, चावल निर्यात पर शुल्क लगाया, प्याज और दालों के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा. वैश्विक बाजारों में मंदी और जंग की आशंका के कारण ईंधन महंगाई काबू में रखा गया है, और इनपुट लागत कम होने से मूल महंगाई (जिसमें खाद्य वस्तुओं और ईंधन शामिल नहीं होता) कम हो गई है, पर खाद्य महंगाई चिंता का विषय है. क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डी.के. जोशी कहते हैं, ''खाने-पीने की चीजों का सीपीआइ में करीब 45 फीसद भार होता है. कृषि का प्रदर्शन खराब रहा है.'' औसत सालाना महंगाई दर वित्त वर्ष 04-वित्त वर्ष 14 के बीच 8.2 फीसद से घटकर वित्त वर्ष 14 और वित्त वर्ष 23 के बीच 5 फीसद रह गई. फरवरी में सीपीआइ महंगाई 5.09 फीसद थी जो लगातार छठे माह आरबीआइ के 2-6 फीसद दर की सहनशील सीमा के भीतर थी. वहीं, आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 अप्रैल की समीक्षा में ब्याज दरों में और कटौती से मना कर दिया. *—एम.जी. अरुण*

"खाने-पीने की चीजों की महंगाई समस्या है. सीपीआइ में खाने-पीने की चीजों का भार 45 फीसद होता है. कृषि का प्रदर्शन खराब रहा है"

—डी.के. जोशी,
मुख्य अर्थशास्त्री, क्रिसिल

कीमतों का पैटर्न

मोदी के कार्यकाल में सालाना महंगाई औसतन 5 फीसद रही

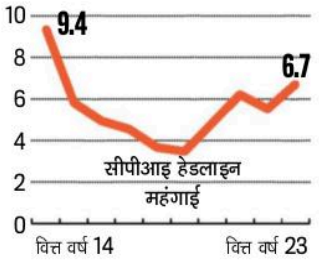

सालाना महंगाई उस साल के दौरान मासिक महंगाई दर का औसत होता है

स्रोतः सीएमआइई इकोनॉमिक आउटलुक

अब तक की सबसे अधिक औसत जीडीपी वृद्धि दर्ज होने के बाद मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचे थे. उस जीत में उनकी सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) जैसे व्यापक कल्याणकारी योजनाओं का भी योगदान था. मोदी ने भी ''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'' के नारे के सहारे तीसरे कार्यकाल के लिए अपना दावा पेश किया है, जो विकास, समावेशी योजनाओं और भरोसे पर आधारित है.

'मनमोहन आर्थिकी' अधिकार-आधारित अर्थशास्त्र पर केंद्रित थी जो लोगों, खासकर कमजोर वर्गों के अधिकारों को पुख्ता करने की दिशा में काम करता थी. 'मोदी आर्थिकी' का फोकस भारी निवेश आधारित विकास और कल्याण योजनाओं के साथ राजकोषीय संतुलन पर है

अर्थव्यवस्था और उसकी प्रगति तथा नाकामियों के दावे और प्रति-दावे सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन दोनों के प्रचार अभियानों में बुलंद हो रहे हैं. ऐसे में *इंडिया टुडे* ने इन बयानबाजियों से दूर रहकर मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड का प्रमुख मापदंडों पर वास्तविक मूल्यांकन करने की कोशिश की. प्रधानमंत्री के दोनों कार्यकाल के दौरान कामयाबियां और नाकामियां दोनों का अगले पन्नों में ब्यौरे दिए

प्रमोद राघवः

पीएम मोदी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर ला रहे अभूतपूर्व बदलाव

ऐसी दुनिया में जहां लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, प्रमोद राघव ईमानदारी और दयालुता के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं। और अपने नेक कार्यों के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। बिजनेस की बेहतरीन समझ और उनकी दयालुता, एक विकसित और समावेशी भारत के निर्माण के विचार को दर्शाती है।

''निस्वार्थकदम'' के प्रमुख के रूप में, प्रमोद एक ऐसे मिशन का नेतृत्व करते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी संस्कृति और एकता के प्रतीक राम मंदिर के मूल्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। सहानुभूति की मजबूत भावना और दूसरों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर, उन्होंने जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए निस्वार्थकदम के साथ अपनी यात्रा शुरू की।

हाशिए में रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखकर, प्रमोद ने प्रत्येक नागरिक के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प किया। समय के साथ, उनका लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने का है। आखिर प्रधानमंत्री का ''सबका साथ, सबका विकास'' विजन भी तो इन ही मूल्यों पर जोर देता है।

शिक्षा में अहम योगदान

अपने मिलनसार व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले प्रमोद का प्रमुख योगदान देश की शिक्षा में है। जो भारत के युवाओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने के पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा के समालखा शहर जैसे वंचित इलाकों में स्कूलों का निर्माण करके और राजस्थान में वैदिक कन्या गुरुकुल शुरू करके, उन्होंने ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे।

इसके अलावा, प्रमोद स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसी मुद्दों की बेहतरी को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। पीएम मोदी के स्टार्ट अप इंडिया और मुद्रा योजना से प्रभावित होकर उन्होंने महिलाओं के लिए स्व-रोजगार का समर्थन करने जैसी पहल को प्राथमिकता देते हैं। इस माध्यम से, प्रमोद न केवल नौकरी के अवसर पैदा करते हैं बल्कि महिलाओं को भी सशक्त बनाते हैं।

कोविड-19 महामारी जैसे संकट के दौरान प्रमोद के परोपकारी प्रयास, समाज की सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। NGO और सरकार के साथ काम करके, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि मदद उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

पर्यावरण की सुरक्षा हमारा संकल्प

इसके अलावा, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाकर और हानिकारक उत्पादों के खिलाफ आवाज बुलंद करके, प्रमोद पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। पेड़ों के साथ सेल्फी लेने और प्लास्टिक को न कहने जैसी पहल के साथ, वह पर्यावरण-अनुकूल आदतों को बढ़ावा देते हैं, जो बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

मुनाफा के साथ-साथ समाज में हो बेहतरी

अपने व्यवसाय में, प्रमोद मुनाफा कमाने के साथ-साथ समाज की बेहतरी के लिए भी कठिन परिश्रम करते हैं। वह लोगों को नौकरियां प्रदान कर और पर्यावरण की देखभाल करके, पीएम मोदी के ''Ease of Doing Business'' और ''Ease of Living'' के लक्ष्य का पालन करते हैं।

इसके बारे में वह बताते हैं, ''अपनी व्यावसायिक परियोजनाओं में, हम पैसा कमाने के साथ-साथ समाज की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं हमारे काम के जरिए समाज में अच्छा परिवर्तन आये और उससे पर्यावरण का भी भला हो। हम मुनाफा कमाने के साथ-साथ लगातार समाज की मदद करने के मौके भी तलाशते हैं।''

दरअसल, उनका लक्ष्य भारत की वृद्धि और विकास के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप निस्वार्थकदम के प्रयासों को आगे बढाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, प्रमोद राघव समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जोर-शोर से जुटे हुए हैं, जो एक उज्जवल भविष्य की ओर भारत के मार्ग को प्रशस्त करता है।

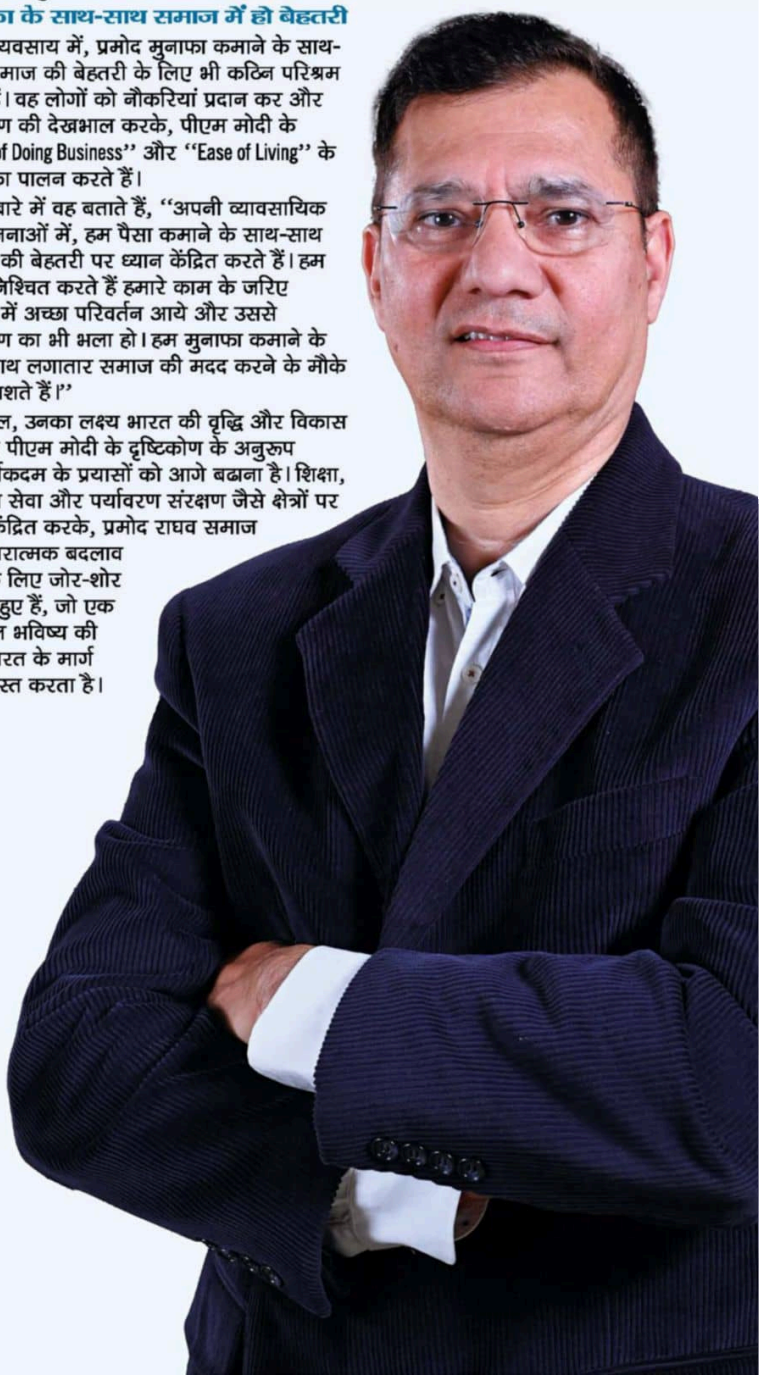

नाकाम बेरोजगारी

कहां हैं नौकरियां?

रोजगार दर में बढ़ोतरी स्व-रोजगार के कारण हुई है, जिसमें बिना मेहनताने की मजदूरी भी शामिल

आफताब आलम सिद्दीकी

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने 2014 के चुनाव में युवाओं को एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था. सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने की कोशिश में प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी दर बीते छह वर्ष में सबसे कम है.

बेरोजगारी दर से श्रम बल में 15 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगारों का फीसद पता चलता है और सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, यह दर 2017-18 के 6 फीसद से घटकर 2022-2023 में 3.2 फीसद हो गई है. मगर एमडीआइ गुड़गांव में एजंक्ट प्रोफेसर और श्रम अर्थशास्त्री के.आर. श्याम सुंदर बताते हैं, ''जमीनी हकीकत खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों में वृद्धि का संकेत देती है. यानी स्व-रोजगार श्रमिक, ठेका मजदूर, निश्चित रोजगार के मजदूर वगैरह.''

कार्यरत या काम की तलाश में 58 फीसद लोगों में से 57.3 फीसद स्व-रोजगार वाले हैं. अधिकांश लोग घरेलू उद्यमों में बिना वेतन के काम कर रहे (18.3 फीसद) या छोटे-मोटे कारोबार कर रहे (39 फीसद) हैं, जैसे रेहड़ी-पटरी वाले या चाय/पान की दुकान चलाने वाले. ये काम रोजगार गुणवत्ता सूचकांक में निचले पायदान पर आते हैं. बाकी 21.8 फीसद अनियमित श्रमिक हैं. नियमित वेतनभोगी नौकरियां सिर्फ 20.9 फीसद हैं.

आत्मनिर्भरता की कसक

भारत की अधिकांश कामकाजी आबादी किसी तरह के स्व-रोजगार में जुटी है

स्रोतः सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण; लोगों के लिए सामान्य स्थिति में डेटा, 2022-23 का मतलब जुलाई 2022-जून 2023 की अवधि से है और इसी तह अन्य वर्षों के लिए

सुंदर कहते हैं, ''देश में हर साल 1.2 करोड़ लोग कार्यबल में शामिल होते हैं, पर वेतनभोगी नौकरियां बढ़ती आबादी के साथ नहीं बढ़ रहीं, जिससे स्व-रोजगार में वृद्धि हो रही है.'' वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 2020-21 में 21.1 फीसद से घटकर 2022-23 में 20.9 फीसद हो गई है. इसी अवधि में स्व-रोजगार श्रमिक 55.6 फीसद से बढ़कर 57.3 फीसद हो गए हैं. मानव विकास संस्थान (आइएचडी) और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की हाल में जारी 'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024' में असंगठित क्षेत्र की समस्या और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों की कमी को भी उजागर किया गया है.

> **''जमीनी हकीकत खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों में वृद्धि का संकेत करती हैं, जिनमें स्व-रोजगार श्रमिक, ठेका श्रमिक, निश्चित रोजगार श्रमिक शामिल हैं. सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि उसने बड़े स्तर की बेरोजगारी की समस्या को दूर किया''**
>
> **के.आर. श्याम सुंदर** एडजंक्ट प्रोफेसर, एमडीआइ गुड़गांव

विशेषज्ञों का कहना है कि खपत वृद्धि के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करनी होंगी. खपत बढ़ने से कंपनियों की क्षमता उपयोग में सुधार होगा और वे ज्यादा निवेश करेंगी. दिक्कत यह कि खपत में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है.

सरकार के लिए आगे का रास्ता राष्ट्रीय रोजगार नीति हो सकती है, जिसका जिक्र आइएलओ संधि में किया गया है, जिस पर भारत 1961 में दस्तखत कर चुका है. ***–सोनल खेत्रपाल***

गए और विश्लेषण किया गया है.

मोदी सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और अब केंद्र के आलोचक माने जाने वाले सुभाष चंद्र गर्ग कहते हैं, ''मोदी सरकार के तहत देश की आर्थिक प्रगति के बारे में सच्चाई सिर्फ काले या सफेद में ही नहीं है, इसमें कई धूसर इलाके हैं.'' गर्ग का मानना है कि अर्थव्यवस्था पर दूरगामी असर के लिए किसी भी प्रधानमंत्री को भारत जैसे विकासशील देश में नेतृत्व के मुख्य एजेंडे में तीन मुख्य बिंदु होने चाहिए. एक, तेज आर्थिक विकास के लिए सरकार और कारोबार के साथ-साथ घरेलू और विदेशी निवेशकों के साथ संबंधों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था की संरचना को बदलना चाहिए. दूसरे, समान और समावेशी विकास के लिए गरीबों में संसाधनों का पुनर्वितरण होना चाहिए. और तीसरी है टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखकर तेजी से तकनीकी बदलावों के सहारे विकास की दिशा में आगे बढ़ने की नेता की काबिलियत.

इसके अलावा, विशेषज्ञों के मुताबिक, हर प्रधानमंत्री आर्थिक नीति के संबंध में अपना नजरिया, अपनी विचारधारा और प्रतिबद्धता लेकर आता है, जिससे तुलना करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए, 'मनमोहनॉमिक्स' या

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी-9, सेक्टर-10, नोएडा 201301 (भारत)

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक्लेटर में भरें
मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक.....
को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये
की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के
चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.
नाम..... पता.....
..... शहर..... राज्य..... पिन.....
मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमोंसे संपर्क भी कर सकते हैं

कॉल और Whatsapp के लिए +91 8597778778
ईमेल भेजें wecare@intoday.com
लॉग ऑन करें subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

'मनमोहन आर्थिकी' अधिकार-आधारित अर्थशास्त्र पर केंद्रित थी जो लोगों, खासकर कमजोर वर्गों के अधिकारों को पुख्ता करने की दिशा में काम करता थी. 'मोदीनॉमिक्स' या 'मोदी आर्थिकी' का फोकस भारी निवेश आधारित विकास और कल्याण योजनाओं के साथ राजकोषीय संतुलन पर है. इसमें इस बात पर भी जोर है कि टेक्नोलॉजी की मदद से लाभार्थियों को बिचौलियों के बजाए सीधे नकदी हस्तांतरण हो सके, ताकि डिलिवरी कारगर और भ्रष्टाचार से मुक्त हो. मोदी के हर काम और योजनाओं में एक स्पष्ट सोच-समझ होती है, जो बड़े गेमप्लान का हिस्सा होती है. यह पहले जाहिर नहीं होता है लेकिन उसके सभी हिस्सों के जुड़ जाने के बाद खुलता है.

जनवरी में *इंडिया टुडे* के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने अपने नजरिए के इसी 'क्रमवार

जेएएम या जैम त्रिकोण से बैंक की सुविधा से वंचित 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले. इसके बाद उन खातों में सीधे नकदी हस्तांतरण का लाभ पहुंचा और भारत डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया में अगुआ बन गया

उजागर' होने की बात की थी. उन्होंने मिसाल के तौर पर डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया था, जिसकी पहल उनकी सरकार ने की. अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने जन धन योजना के जरिए बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंक खाते खुलवाने का बड़ा अभियान चलाया था, जिसमें 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले. उसके बाद उन्होंने सरकारी कल्याण योजनाओं की मद में सभी नकद हस्तांतरण के लिए सीधे इन लाभार्थी खातों को आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से जोड़ दिया. इसे जैम या जेएएम या जन धन, आधार और मोबाइल त्रिकोण कहा जाता है. यह गेम-चेंजर साबित हुआ. इन खातों में फिलहाल 2.32 लाख करोड़ रुपए जमा राशि बताई जाती है. देश डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक अगुआ के रूप में उभरा. पिछले साल ई-लेन-देन की संख्या बढ़कर 13.4 करोड़ की हो गई, जो सभी वैश्विक डिजिटल भुगतानों का 46 फीसद था.

कामयाब | विनिवेश

बढ़ गया मनोबल

एअर इंडिया की बिक्री और एलआइसी का शेयर बाजार में प्रवेश भारत के निजीकरण लक्ष्यों के लिए संभावना भरी राह का संकेत है

एपी

नाकाम | संपत्ति मुद्रीकरण

सुस्त पटरी पर

संपत्ति की सीधी बिक्री या निजीकरण की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद सरकार अपने संपत्ति मुद्रीकरण के लक्ष्य को पूरा करने से चूक रही, और इनके अमल में बाधाओं का सामना कर रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली तो उन्होंने जो बड़े वादे किए उनमें से एक वादा 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' का था. उस समय यह उम्मीद की गई थी कि सरकार कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों का नियंत्रण छोड़ेगी और सीधे इक्विटी बिक्री के जरिए इन्हें निजी क्षेत्र को दे देगी या फिर उनके परिचालन और प्रबंधन में अधिक निजी भागीदारी लाएगी जिससे कि उनको अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाया जा सके. वैसे, पहले कार्यकाल में सरकार इस मोर्चे पर कुछ खास हासिल नहीं कर सकी क्योंकि उसने अपनी ज्यादातर ऊर्जा विपक्ष की ओर से खुद पर लगाए गए 'सूट बूट की सरकार' के आरोप का जवाब देने के लिए ग्रामीण गरीबों की कल्याण योजनाओं में खर्च की.

अगस्त 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की जिसके तहत

सरकार की विनिवेश योजनाओं में भाग्य साथ नहीं दे रहा था. मगर दो बड़ी घटनाओं ने उसके लिए उम्मीदों के दरवाजे खोल दिए. अक्तूबर 2021 में टाटा समूह ने एअर इंडिया के अधिग्रहण के लिए सबसे ऊंची बोली लगाते हुए एअरलाइन के उद्यम मूल्य के रूप में 18,000 करोड़ रुपए की पेशकश की. मई 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) देश के शेयर बाजारों में 21,000 करोड़ रुपए के अब तक के सबसे बड़े आइपीओ के साथ आगे आया.

टाटा ने एअर इंडिया के 15,300 करोड़ रुपए के ऋण का अधिग्रहण किया जबकि शेष 2,700 करोड़ रुपए सरकार को नकद के रूप में दिए जाने थे. यह सौदा ऐसे समय हुआ जब महामारी से दुर्बल ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं फिर से खुल गई थीं. एअर इंडिया का 31 मार्च 2020 तक कुल संचित घाटा 70,820 करोड़ रुपए का था. उसका ऋण उस साल 31 अगस्त तक 61,562 करोड़ रुपए था. मैकिंजी ऐंड कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार अंबर दुबे ने नवंबर 2023 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा, ''एअर इंडिया का निजीकरण गेमचेंजर है. हमारे यहां दो मुख्य कंपनियां हैं—एअर इंडिया और इंडिगो—जिनकी घरेलू हवाई यातायात में 85 फीसद से अधिक की हिस्सेदारी है और जिनके पास भरपूर पूंजी है.'' घरेलू हवाई यातायात सालाना आधार पर 4.7 फीसद बढ़कर जनवरी 2024 में 1.3 करोड़ यात्री हो गया. जून 2023 में एअर इंडिया ने करीब 70 अरब डॉलर (5.8 लाख करोड़ रुपए) में 470 नए विमान खरीदने के लिए एअरबस और बोइंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए.

18,000 करोड़ रु.
की विजयी बोली लगाई टाटा समूह ने एअर इंडिया खरीदने के लिए

61,562 करोड़ रु.
कर्ज था एअर इंडिया पर 31 अगस्त, 2020 तक

21,000 करोड़ रु.
का था एलआइसी का इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (आइपीओ)

5.75 लाख करोड़ रु.
था एलआइसी का मार्केट कैप 17 जनवरी 2024 तक, जब यह कुछ वक्त के लिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे मूल्यवान उद्यम बन गई

शेयर बाजार में एलआइसी

एलआइसी में कई साल से विनिवेश में हो रही देरी के बाद केंद्र ने आइपीओ के जरिए इस दिग्गज बीमा कंपनी में 3.5 फीसद हिस्सा बेच दिया. उसका आइपीओ 21,000 करोड़ रुपए का था. एलआइसी 45.5 लाख करोड़ रुपए की कुल परिसंपत्तियों का प्रबंधन करती है और उसके पास 27.5 करोड़ व्यक्तिगत पॉलिसियां हैं. शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के दो साल से भी कम समय में 17 जनवरी को एलआइसी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे ज्यादा मूल्यवान उद्यम बन गई जिसका बाजार पूंजीकरण 5.75 लाख करोड़ रुपए था. उस दिन एलआइसी के शेयर पहली बार उसकी सूचीबद्धता कीमत 904 रुपए को पार कर गए.

हालांकि अन्य बड़ी विनिवेश योजनाओं जैसे आइडीबीआइ बैंक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अभी विनिवेश का इंतजार है. विश्लेषकों का अनुमान है कि सरकार वित्त वर्ष 24 में अपने 61,000 करोड़ के लक्ष्य से चूक जाएगी और यह 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए कम रह सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, ''इनके अमल में चुनौतियां हैं. सरकार एलआइसी से आगे नहीं बढ़ सकी. अब तक छोटे-मोटे सभी विनिवेश पहले ही किए जा चुके हैं.'' ■

निजी क्षेत्र को प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं 15 से 30 साल या अधिक अवधि के लिए परिचालन के लिए दी जानी थीं. परिसंपत्ति मुद्रीकरण, जहां सरकार नियंत्रित संपत्तियां लंबी अवधि में परिचालन के लिए निजी कंपनियों को अग्रिम शुल्क लेकर दी जाती हैं, वह जाहिर तौर पर राजस्व का आसान तरीका था और इसे सीधे संपत्ति बिक्री या निजीकरण के मुकाबले ज्यादा आसान माना गया. विचार यह था कि इसके जरिए अगले चार साल (वित्त वर्ष 22 से 25 के बीच) 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाए जाएं जिससे कि सरकार की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा योजनाओं को धन मिल सके, उसका बढ़ता घाटा कम हो सके और निजी निवेश फिर से बहाल हो सके. इसके लिए सड़क, रेलवे, बिजली ट्रांसमिशन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, वेयरहाउसिंग, माइनिंग, विमानन और बंदरगाहों समेत 14 क्षेत्रों की पहचान की गई. नीति आयोग के मुताबिक, वित्त वर्ष 22 में 28,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों के जरिए धन जुटाया गया और वित्त वर्ष 23 के दौरान 1.6 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 26,000 करोड़ रुपए ही हासिल किए जा सके. बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस कहते हैं, ''कई मामलों में लगता है कि ठीक से विचार नहीं किया गया कि मुद्रीकरण की प्रक्रिया पर अमल किस तरह होगा. कई परियोजनाओं में कई एजेंसियां शामिल हैं जिनका आपस में टकराव है. इसलिए यह दिक्कत दूर करना आसान काम नहीं है.''

हाल में एक मीडिया रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया गया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 में संपत्ति मुद्रीकरण से 28,968 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 40,314 करोड़ रुपए जुटाए हैं. अधिकारी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कुल संपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम एक लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है. पर समग्र लक्ष्य हासिल करने के लिए रफ्तार सबसे जरूरी है.

—एम.जी. अरुण

> **''(मुद्रीकरण के लिए निर्धारित) कई परियोजनाओं में विभिन्न एजेंसियां शामिल हैं जिसका आपस में टकराव है. इस दिक्कत को दूर करना आसान नहीं होगा''**
> **मदन सबनवीस,**
> मुख्य अर्थशास्त्री, बैंक ऑफ बड़ौदा

6 लाख करोड़ रु.
से अधिक जुटाने का लक्ष्य है अगले चार साल में केंद्र की इन्फ्रा संपत्तियों को बेचकर

1.14 लाख करोड़ रु.
मूल्य की संपत्ति का मुद्रीकरण हुआ वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 के दौरान, कुल लक्ष्य का 19 फीसद

14
क्षेत्रों की पहचान की गई है मोनेटाइजेशन के लिए, जिनमें सड़क, रेलवे, बिजली ट्रांसमिशन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, विमानन और बंदरगाह शामिल हैं

शांत अविष्कारों से लेकर नवीनतम पर्यावरण मित्रण वाली एयर कंडीशनिंग प्रौद्योगिकियों का अन्वेषण

सततता और ऊर्जा दक्षता के महत्वपूर्ण होने के युग में, एयर कंडीशनिंग उद्योग ने पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने वाली नवीनतम तकनीकों के विकास में कड़ी मेहनत की है। इस लेख के पहले भाग में हम आधुनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के सततता पहलुओं में गहराई से जाएंगे, जबकि बाकी के भाग में हाल ही में उभरी हुई कटिंग एज तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

एयर कंडीशनिंग में उभरती हुई तकनीकें

जब हम आधुनिक एयर कंडीशनिंग के तकनीकी पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो स्पष्ट है कि नवाचार उद्योग को आगे बढ़ा रहा है। इस तरह की एक प्रगति स्मार्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के विकास है। ये इकाइयाँ उन्नत सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके प्रदर्शन को अनुकूलित करने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, और उपयोगकर्ता की सुविधा को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। स्मार्टफोन ऐप्स के माध्यम से दूरस्थ नियंत्रण, स्मार्ट होम सिस्टम के साथ आवाज़ नियंत्रण सुगमता, और एडैप्टिव तापमान नियंत्रण के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, हमारी एसी इकाइयों के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहे हैं।

एयर कंडीशनिंग तकनीक में एक और संभावनापूर्ण नवाचार वायु शोधन प्रणाली के कार्यान्वयन है। जैसा कि इंडोर वायु गुणवत्ता एक बढ़ती हुई चिंता बनती जा रही है, कई हैं, कई निर्माताओं ने एचईपीए फ़िल्टर, सक्रिय कार्बन फ़िल्टर और यूवी-सी प्रकाश संक्रमण की तरह उन्नत फ़िल्ट्रेशन तकनीकों को अपने एसी इकाइयों में शामिल किया है। ये सुविधाएं न केवल सुखद तापमान सुनिश्चित करती हैं, बल्कि प्रदूषक, एलर्जी कारक और रोगाणुओं को हटा कर घर के अंदर की हवा को साफ़ और स्वस्थ बनाती हैं।

थर्मल ड्राइवन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो शीतलन प्रक्रिया को बिजली के बजाय गर्मी के स्रोतों का उपयोग करते हैं, उन्हें भी लोकप्रियता मिल रही है। ये सिस्टम अवशोषण या निष्पेक्ष ठंडक के उपकरणों पर निर्भर करते हैं और अपशिष्ट गर्मी या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, जैसे कि सौर या भू-तापीय शक्ति, का उपयोग करके कुशल और पर्यावरण अनुकूल शीतलन प्रदान कर सकते हैं।

अंत में, सामग्री विज्ञान में प्रगति ने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग के लिए फेज़ चेंज मटेरियल (PCMs) के विकास की ओर ले गईहै। फेज चेंज मटेरियल (PCMs) तापीय ऊर्जा को संग्रहित और रिहा कर सकते हैं, जो घर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और एसी यूनिट पर कामदेना को कम करते हैं। PCMs को निर्माण सामग्रियों में शामिल करके या एसी सिस्टम में उनका एकीकरण करके, ऊर्जा उपभोग को और कम किया जा सकता है, जो एक हरियाली और अधिक सतत शीतलन समाधान की ओर योगदान करता है।

निष्कर्ष, एयर कंडीशनिंग उद्योग ने सततता और तकनीक में काफी प्रगति की है, जिसमें पर्यावरण अनुकूल नवाचार सेक्टर को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जब हम पर्यावरणीय मुद्दों को जारी रखते हैं, तो एयर कंडीशनिंग में इन प्रगतियों को अंगीकार करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक अधिक सतत और सुखद भविष्य सुनिश्चित कर सकें।

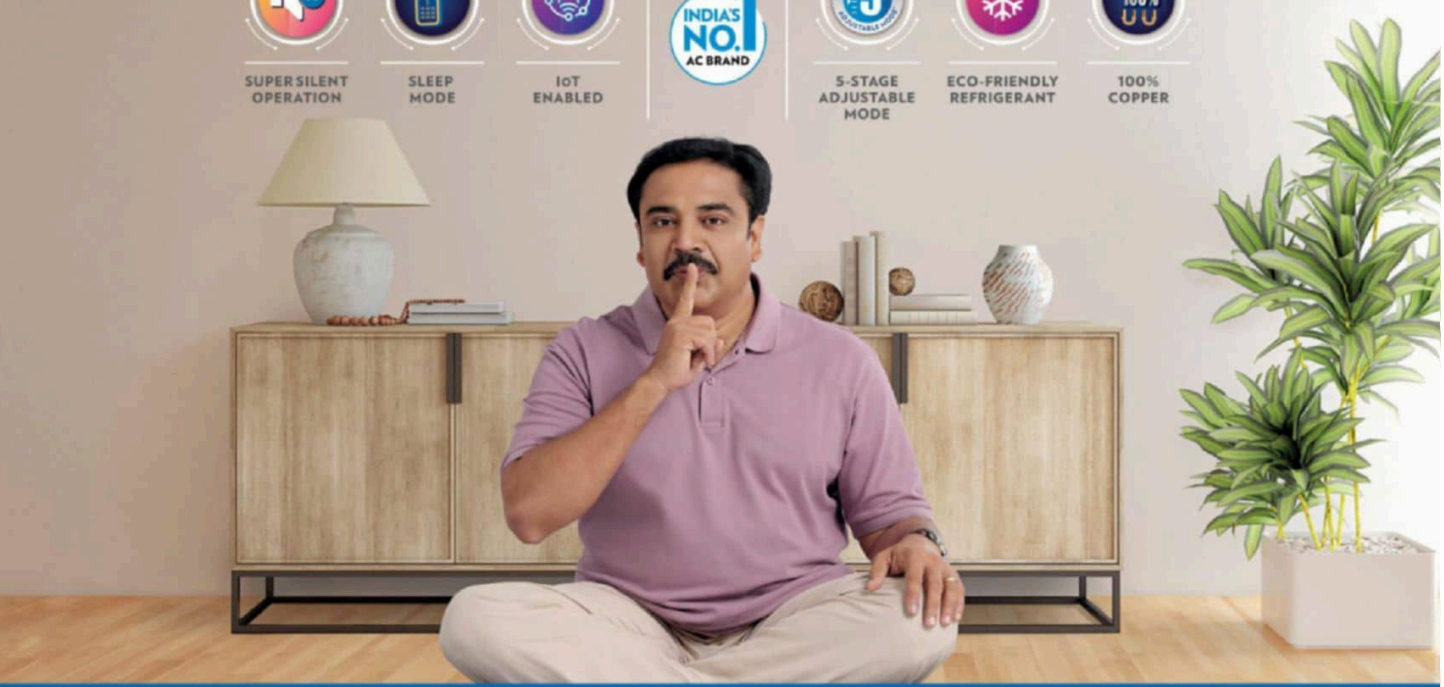

A TATA Product
VOLTAS
Shor Kam, Kaam Zyada.
Presenting
VOLTAS SMARTAIR™
Super Silent AC with Sleep Mode.
Presenting the all-new Voltas SmartAir Inverter AC that arrives with super silent operation. Its unique sleep mode adjusts the temperature to put you at ease when you sleep, along with extra comfort and extra savings with a 5-stage adjustable mode. Now, live smart with an IoT-enabled interface, straight from the house of India's No.1 AC brand.
SUPER SILENT OPERATION
SLEEP MODE
IoT ENABLED
INDIA'S NO.1 AC BRAND
5-STAGE ADJUSTABLE MODE
ECO-FRIENDLY REFRIGERANT
100% COPPER
UP TO 15% CASHBACK
FIXED EMI OF ₹1888
ZERO DOWN PAYMENT & LOW TENURE SCHEMES
LONG TERM EMI
UP TO ₹1000 CASHBACK ON UPI
LIFETIME WARRANTY ON INVERTER COMPRESSOR
5 YEARS WARRANTY ON PCB
Voltas 24x7 Customer Service - 1860 599 4555, 9650694555.
For product registration SMS <WTA> to 9289525321
Buy only genuine Voltas stabilizers.
Visit us at www.voltas.com
To locate your nearest store, log on to: www.Voltas.com/apps/store-locator
Follow us at: My Voltas My Voltas My Voltas Voltas Limited My Voltas
Buy online at: www.voltas.com
Powered by
Pine Labs Paytm amazon pay AMERICAN EXPRESS DBS FEDERAL BANK HDFC BANK kotak onecard SBI card YES BANK HSBC ICICI Bank TVS CREDIT
Corporate Head Office: Voltas Limited, Voltas House A, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Chinchpokli, Mumbai-400033, Phone: 022-66656666. Also available in all leading Retail Outlets.
*Terms & Conditions apply. Voltas Smart Air AC delivers a Super Silent Operation at 28dBA noise level as tested under standard lab conditions. The IOT Technology is powered by Voltas Smart Mobile App which can be operated through Voice Control through smart voice interface devices. Voltas Adjustable mode can deliver cooling at multiple tonnage capacities, as selected by the user on the AC remote, hence optimizing power consumption. Features available in select models only. For more details on E-waste (Management and Handling), Warranty, Product Features and Offers (Valid on Selected Products Only), please visit www.voltas.com.

मनीष अग्निहोत्री

बुलंदियों पर

मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र को गर्त से निकालकर नई बुलंदियों पर पहुंचाया. यह बात उत्साहित करते आंकड़ों और वैश्विक रैंकिंग में वृद्धि से साफ नजर आती है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही बुनियादी ढांचे, खासकर सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र को लेकर अपनी सरकार के विजन को जता दिया था. वर्षों तक इन अहम क्षेत्रों के उपेक्षित रहने के कारण बने कम निवेश चक्र को सरकार तोड़ना चाहती थी. अब एक दशक बाद देश के पास 2,500 किमी लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) है जिस पर माल का परिवहन पारंपरिक रेल नेटवर्क की तुलना में दोगुनी गति से होता है. वहीं वंदे भारत ट्रेनें हैं जो यात्रियों को ज्यादा तेज और आरामदेह यात्रा की सुविधा देती हैं.

रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2014 से हर साल तीन गुना बढ़ा है. 10 वर्षों में रेलवे पर कुल पूंजीगत व्यय में 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल हैं. 2014 के बाद से 7.8 किमी प्रतिदिन की दर से लगभग 26,000 किमी नई पटरियां बिछी हैं. फिलहाल करीब 60,814 किमी ट्रैक या 90 फीसद अधिक ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण हो गया है (बीते 10 वर्षों में यह 40,000 किमी से अधिक रहा).

कायापलट

बुनिदायी ढांचे में ऐसा विकास पहले कभी नहीं देखा गया था

रेलवे ट्रैक बिछाया गया (किमी)

2004 - 2014: 14,985

2014-2023: 25,871

विद्युतीकरण हुआ (रूट किमी)

2004 - 2014: 5,188

2014-2023: 37000+

सड़क (किमी)

राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई

2014: 91,287 (31,300 करोड़ रु.)

2024: 146,000 (2.8 लाख करोड़ रु.)

सरकारी निवेश ()

बंदरगाह और शिपिंग

800 एमएमटी सालाना कार्गो का प्रबंधन, 2013 के स्तर से **43%** की वृद्धि

22 वां स्थान भारत का अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में, 2014 के **44** वें स्थान से काफी बेहतर

स्रोतः भारत सरकार

2014 से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अगुआई में राजमार्ग क्षेत्र अपनी निर्माण गति को लेकर सुर्खियों में रहा है, जिसकी रफ्तार अब प्रतिदिन 30 किमी है. पिछले दशक में देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 91,287 किमी से बढ़कर 1.46 लाख किमी हो गया है और सरकार का निवेश भी करीब 10 गुना बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपए (2024-25) पर पहुंच गया है. कुछ प्रमुख राजमार्ग गलियारों में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, हिमाचल प्रदेश की अटल सुरंग और बदले नाम के साथ जम्मू-कश्मीर को जोड़ने वाली एस.पी. मुखर्जी सुरंग शामिल हैं और सभी में पूरे वर्ष हर मौसम में कनेक्टिविटी की सुविधा है.

बंदरगाहों और शिपिंग की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है. बंदरगाहों के विकास पर केंद्रित महत्वाकांक्षी सागरमाला परियोजना के तहत मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के साथ अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध हुई है. नतीजा, बंदरगाहों पर संभालने जाने वाले (लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन आदि) माल की कुल मात्रा 2013 की तुलना में 43 फीसद बढ़कर अब 800 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के पार पहुंच गई है. इस अवधि में वार्षिक क्षमता दोगुनी होकर 1,617 एमएमटी हो गई.

यही नहीं, उपयोग में आ रहे अंतर्देशीय जलमार्गों की संख्या 2013 में आठ की तुलना में बढ़कर 24 पर हो गई है, और वहां संभाले जाने वाले माल की वार्षिक मात्रा भी 6.9 एमएमटी से बढ़कर 126.2 एमएमटी हो गई है, जो 1,731 फीसद की भारी वृद्धि है. अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत अब 22वें स्थान पर है, जबकि 2014 में यह 44वें स्थान पर था.

इस बीच, नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) यानी देश के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के लिए सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे मुख्य क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश की व्यापक योजना में 2019 से 2025 के बीच करीब 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं. 2019 में लॉन्च एनआइपी के तहत 109 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 9,288 परियोजनाएं चल रही हैं. *—अभिषेक जी. दस्तीदार*

उम्मीद से कहीं कम

मोदी सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र जीडीपी के करीब 14 फीसद की दर से ही आगे बढ़ा है

यूपीए शासनकाल में नई मैन्युफैक्चरिंग नीति जैसे प्रयासों के बावजूद जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी औसतन करीब 16 फीसद थी. विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक, 2014-22 में यह आंकड़ा 14 फीसद के आसपास पहुंच गया. केंद्रीय पेट्रोलियम, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मानें तो 2023 में, करीब 2.73 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देने वाले मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 17 फीसद थी, जिसे सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना जैसे उपायों के माध्यम से 2025 तक 25 फीसद पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. मगर, पूर्व आरबीआइ गवर्नर रघुराम राजन जैसे आलोचकों का कहना है कि इस योजना से केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारी सब्सिडी मिली है.

विनिर्माण क्षेत्र कई चुनौतियों से जूझता है. मसलन, नियमों में स्पष्टता न होना, लॉजिस्टिक की उच्च लागत, वित्त की कमी, नवाचार और कौशल का अभाव आदि. फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरपर्सन नौशाद फोर्ब्स कहते हैं, ''कारोबार में सहूलत की बात करें तो एक दशक पहले की तुलना में स्थितियां ज्यादा नहीं बदली हैं.'' चाहे सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी के नए प्रकटीकरण दिशानिर्देश हों या निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए कंपनी कानून के पालन संबंधी अर्हताएं, विनियम से जुड़े गतिरोध डरावने साबित हो सकते हैं. पीएलआइ योजना कुछ विशेष क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने में कारगर रही है. पर इसमें असली परीक्षा यह होती है कि सब्सिडी बंद होने के बाद कंपनियां कैसे चल पाएंगी.

—एम.जी. अरुण

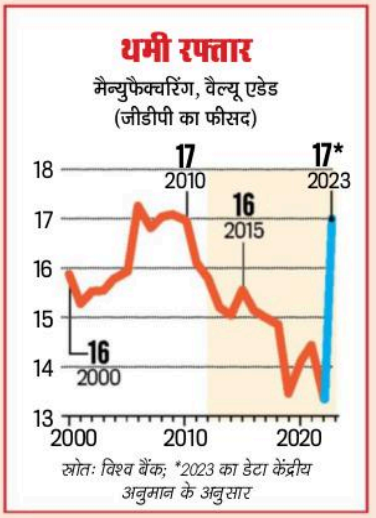

मंदार देवधर

'नीतिगत लकवा' से ग्रस्त मनमोहन सिंह सरकार के बाद 2014 में जब मोदी ने सत्ता संभाली, तो लोगों की उम्मीद यही थी कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था में फौरन जान डालकर लाखों रोजगार और नौकरियां पैदा करेगी, जिसकी देश को सख्त जरूरत थी. उनसे यह भी उम्मीद की गई थी कि वे तेज आर्थिक विकास की राह प्रशस्त करने के लिए कई सुधार लाएंगे. उनसे वह भी करने की उम्मीद थी, जिसे वे कहते, ''अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार.'' अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने खासकर सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर की कई परियोजनाओं और खासकर वित्तीय क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की. गरीबों और जरूरतमंदों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक कल्याणकारी उपाय भी शुरू किए गए, जिनमें शौचालय, सस्ता गैस कनेक्शन और घर मुहैया कराना शामिल है.

वित्तीय क्षेत्र में मोदी के दो प्रमुख संरचना संबंधी बदलाव मार्के के साबित हुए. एक, उन्होंने देश भर में कारोबारी सहूलत पैदा करने के लिए ऐतिहासिक माल और सेवा कर (जीएसटी) को आगे बढ़ाया. दूसरे, बड़े पैमाने पर एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां) या डूबत कर्ज के संकट से जूझ रहे बैंकों की मदद करने के उपायों में एक इन्सॉल्वेंसी ऐंड बैंकिंग कोड (ईबीसी) लाया गया, क्योंकि एनपीए बढ़कर 10.2 लाख करोड़ रुपए हो गया था. हालांकि, उन्होंने 2016 में काले धन से निजात पाने के लिए नोटबंदी का चौंकाने वाला फैसला भी किया, जिससे उच्च मूल्य वाली मुद्रा रातोरात अवैध करार दे दी गई. यह काफी विवादास्पद साबित हुआ और अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया. आखिर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने अगस्त 2018 में खुलासा किया कि कुल 15.3 लाख करोड़ रुपए की अवैध करार दी गई मुद्रा का 99.3 फीसद बैंकिंग

हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती की गई, मगर निजी निवेश उम्मीद से काफी कम बना रहा. यह मोदी सरकार के लिए दुखती रग जैसा हो गया. इसके अलावा, श्रमिकों के हाथ में अपने रोजमर्रा की जरूरतें किसी तरह पूरी करने के अलावा अधिक पैसा नहीं होने से खपत में भारी गिरावट आई है

कामयाब | राजकोषीय घाटा

संतुलन की कोशिश

महामारी के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ने के बावजूद केंद्र ने इसकी भरपाई नहीं की और वह बजट से इतर धन में कटौती और राजस्व बढ़ाने के लक्ष्य पर मजबूती से टिका रहा

अब कोविड के बाद जब चीजें फिर से अपनी गति पर हैं तो देश के राजकोषीय संतुलन को बनाए रखना जरूरी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को तब उचित ही तारीफ मिली जब महामारी के दौरान उन्होंने हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाया या राजकोषीय प्रबंधन के कठोर उपाय नहीं किए. उससे राजकोषीय घाटा बढ़कर दशक के उच्चतम स्तर पर भले ही पहुंच गया. राजकोषीय घाटा जीडीपी के फीसद में सरकार के राजस्व और खर्च के बीच अंतर होता है जो यह संकेत भी देता है कि सरकार किस स्तर तक उधार ले रही है. वित्त वर्ष 2021 में यह 9.3 फीसद, वित्त वर्ष 2022 में 6.71 फीसद और वित्त वर्ष 2023 में 6.4 फीसद था जो पिछले दशक के 4 से 4.5 फीसद के दायरे से काफी ज्यादा था. बीमार अर्थव्यवस्था की मदद के लिए ऊंचे राजकोषीय असंतुलन को अपनाने की प्रवृत्ति थी. इसके लिए राजकोषीय घाटे की मुद्रा के जरिए भरपाई की जाती थी, जैसे नोटों की छपाई और कृत्रिम रूप से मांग बढ़ाकर. सबसे निडर कदम यह था कि ऐसा न करके महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था की मदद की जाए.

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के लिए लक्ष्य यह है कि घाटे के आंकड़ों को कम करके वित्त वर्ष 26 तक 4.50 फीसद से नीचे लाया जाए. कोविड के बाद राज्यों

इलस्ट्रेशनः राज वर्मा

प्रणाली में वापस आ गया है. इससे काला धन मिटाने का तर्क बेमानी होता लगा. हालांकि लोगों ने काले धन को मिटाने के व्यापक हित में आई कठिनाइयों को झेल लिया. इसके ठीक विपरीत, गरीबों के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं बहुत सफल साबित हुईं, यहां तक कि वे जाति-धर्म से परे लाभार्थियों का एक पूरा वोट बैंक बनाने में कामयाब हुए. इस लाभार्थी वर्ग ने उनकी 2019 में दोबारा चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी. वे मध्यम वर्ग के घर खरीदारों को बेईमान डेवलपर्स से बचाने के लिए 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए-रेरा) ले आए, जिससे इस क्षेत्र में विकास हुआ और इसे कामयाब पहल माना गया.

उनका दूसरा कार्यकाल राजनैतिक और आर्थिक मोर्चे पर बड़े पैमाने पर सुधारों के साथ शुरू हुआ. गद्दी संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर उनकी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का संशोधन संसद के दोनों सदनों में पारित करवा लिया. आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री ने कारोबारी घरानों को बड़ी रियायत दी. उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 35 फीसद से घटाकर 25 फीसद और नई उत्पादन इकाइयों के लिए 25 फीसद से 15

नाकाम | निजी निवेश

मंद गति

टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए व्यापक निजी निवेश की जरूरत है

उपभोग, सरकारी खर्च और निर्यात के साथ-साथ निजी निवेश वृद्धि के अहम अवयव होते हैं. 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद, शुरु में निजी निवेश बढ़ा, पर जल्द ही धीमा पड़ गया. सीएमआइई के डेटा बताते हैं कि 2013-14 में निजी क्षेत्र में पूरी हुई निवेश परियोजनाओं का कुल मूल्य 2.2 लाख करोड़ रुपए था जो 2016-17 में बढ़कर 3.9 लाख करोड़ रुपए हो गया.

सरकार ने निजी निवेश बढ़ाने के लिए अपने दूसरे कार्यकाल में दो अहम सुधारों की घोषणा की. एक थी सितंबर 2019 में मूल कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करने की. छूट न लेने वाली कंपनियों के लिए इसे 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद किया गया. छूट लेने वाली कंपनियों के लिए 35 फीसद से कम करके 25 फीसद किया गया. नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए 25 फीसद के कर को घटाकर 15 फीसद पर रखा गया. दूसरी घोषणा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीम थी ताकी घरेलू कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रेरित हों. 1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रारंभिक

मोदी ने कोविड महामारी के भारी झटके से निबटने के लिए फिजूलखर्ची के बजाए राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने का फैसला किया, हालांकि वह बेहद अलोकप्रिय कदम था. लेकिन बाद में अर्थव्यवस्था को उसका फायदा मिला

घाटे पर नियंत्रण की जंग

बजट अनुमान में वित्त वर्ष 25 के लिए राजकोषीय घाटा 5.1 फीसद है. इसे वित्त वर्ष 26 तक 4.5 फीसद तक लाने का लक्ष्य है

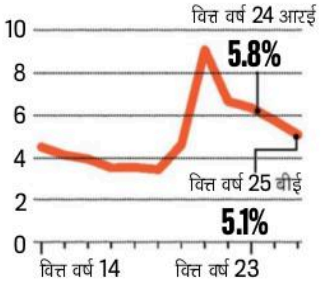

स्रोतः बजट दस्तावेज, भाषण | रॉयटर्स, 1 फरवरी, 2024

को अधिक उधार लेने की इजाजत दी गई, मगर यह शर्त जोड़ दी गई कि वे राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करेंगे. वित्त वर्ष 21 का तूफान उस समय आया जब भारत 2017 में एन.के. सिंह के नेतृत्व वाली कमेटी के सुझाए रास्ते को अपना रहा था. समिति ने राजकोषीय घाटे को कम करके ढाई फीसद तक लाने की सिफारिश की थी. महामारी ने योजना को गड़बड़ा दिया मगर सुधारों को पटरी पर लाने के इरादे मजबूत रहे. 2020 में अपने बजट भाषण में सीतारमण ने अतिरिक्त बजट संसाधनों (ईबीआर) पर एक बयान दिया और इसे घटाने की प्रतिबद्धता जताई. ईबीआर सरकार के लिए अपने खर्च की खातिर वित्त जुटाने का एक रास्ता होता है जिसमें सरकारी संस्थान राजकोष की तरफ से धन उधार लेते हैं जिससे कि ऋण को राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया जाए. केंद्र ने राज्यों में इस तरह की बजट से इतर फंडिंग को हतोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 22 में दिशानिर्देश जारी किए. सीतारमण ने इस तरह के ऋण के भुगतान के लिए अपने बजट में प्रावधान किए. राज्यों के पास वित्त वर्ष 27 तक का समय है. तब तक उनको बजट से इतर उधारी को चुकाकर अपने खातों को दुरुस्त करना है.

राजस्व की बात करें तो 2016 में लागू हुई जीएसटी प्रणाली ने अप्रत्यक्ष कराधान को बदल दिया. 2020-21 से भारत नई आयकर व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष करों में सुधार कर रहा है. अगर ज्यादा राजस्व जुटाने की योजनाएं सफल रहीं तो राजकोषीय घाटा और कम हो जाएगा. *–अनिलेश एस. महाजन*

फीसद कर दिया. इसके साथ ही, मोदी सरकार ने कई प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के विनिवेश पर जोर दिया. इनमें घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एअरलाइन एअर इंडिया भी शामिल है, जिसे 18,000 करोड़ रुपए में टाटा घराने को बेच दिया. सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के शेयरों को भी लोगों के लिए खोला गया, जिसकी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 21,000 करोड़ रुपए थी. एक अन्य वादे में सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख संपत्तियों का निजी क्षेत्र में बिक्री या मॉनेटाइजेशन शामिल था, जिसका अनुमानित आंकड़ा 6 लाख करोड़ रुपए था.

हालांकि, कोविड महामारी मोदी की बड़े सुधारों की योजनाओं के लिए झटका साबित होती. प्रधानमंत्री को श्रेय देना होगा कि वे अडिग रहे और उन्होंने अर्थव्यवस्था को महामारी की गर्त से परिव्यय के साथ मई 2020 में 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए घोषित पीएलआइ योजनाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा थीं.

हालांकि, पूंजी खर्च में व्यापक प्रोत्साहन के जरिए सरकारी परियोजनाओं में सतत बढ़ोतरी के बावजूद निजी निवेश काफी पीछे है. वर्ष 2019-20 में निजी क्षेत्र में पूरी हुई परियोजनाओं का मूल्य 3.27 करोड़ लाख करोड़ रुपए था जो 2020-21 में घटकर 1.2 लाख करोड़ रुपए रह गया. 2021-22 में इसमें फिर वृद्धि हुई और यह 2.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, मगर 2022-23 में गिरकर 2.6 लाख करोड़ रुपए रह गया. कुछ क्षेत्रों में धीमा उपभोग, महंगाई का जोखिम, क्षमता का कम इस्तेमाल और वैश्विक अनिश्चितताओं को इस गिरावट का कारण बताया गया.

सरकारी क्षेत्र का पूंजी खर्च (जिसमें केंद्र सरकार का पूंजी खर्च, स्थायी संपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों को अनुदान और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के निवेश संसाधन शामिल हैं) वित्त वर्ष 15 में 5.6 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया. केपीएमजी, इंडिया ग्लोबल में सह प्रमुख और सीओओ नीरज बंसल कहते हैं, ''बजट 2024 इस सरकार की आर्थिक नीतियों को जारी रखता है जिसमें पूंजी परिव्यय के खर्च, हरित वृद्धि, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के जरिए अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में धारदार नजरिया अपनाया गया है.'' विशेषज्ञ कहते हैं कि निजी निवेश में थोड़ी गति आई है, खासकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र में, पर यह अभी भी व्यापक नहीं है. अगर देश को 7 फीसद या इससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करनी है तो निजी क्षेत्र को और ज्यादा आक्रामक तरीके से निवेश करने की जरूरत होगी. *–एम. जी. अरुण*

उतार-चढ़ाव

भारत सरकार का पूंजीगत व्यय 20 साल के उच्चतम स्तर पर है, मगर इसके निजी पूंजीगत व्यय ने अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी

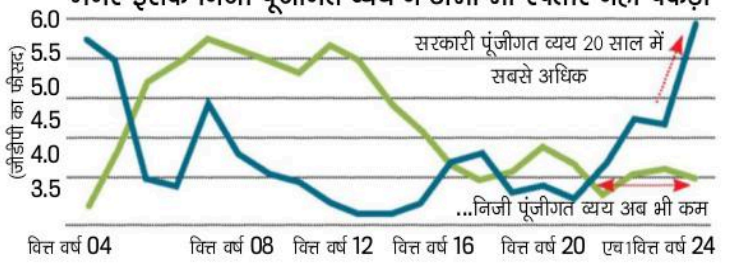

स्रोतः सीएमआइई, बुवामा रिसर्च

कामयाब | हरित ऊर्जा

खिलते सूरज से बढ़ी खिलखिलाहट

एनडीए सरकार के बेहतरीन प्रयासों का ही नतीजा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में एकदम नगण्य स्थिति से इस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना

एएफपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते समय कुछ बड़ी घोषणाएं की थीं, उसमें से एक यह भी थी कि एक दशक में देश की सौर ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट और समग्र नवीकरणीय-आधारित ऊर्जा को 175 गीगावॉट तक बढ़ाना है. अब 2024 आ चुका है, और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की रिपोर्ट बताती है कि स्थापित सौर क्षमता अब करीब 74 गीगावॉट (जो 2014 में करीब 2.6 गीगावॉट थी) है, जबकि समग्र नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में आंकड़ा 191 गीगावॉट (2014 में 76 गीगावॉट) पर पहुंच चुका है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कहते हैं, ''अब, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन चुका है.'' साथ ही वे जोड़ते हैं कि देश ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 फीसद गैर-जीवाश्म ईंधन से हासिल करने की वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है. इसमें दो राय नहीं कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयासों से कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर देश की निर्भरता घटी है.

आज भारत अपने बलबूते सालाना 10-12 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है. भारत में बिजली पारेषण के बुनियादी ढांचे, खासकर अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आइएसटीएस) का विस्तार पूरी कुशलता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण की क्षमता बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है. राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों ने भी यह यात्रा मजबूती से आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है. सरकार ने ऊर्जा भंडारण के साथ हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की अनुमति देकर 'मजबूत और सक्षम' ऊर्जा संबंधी निविदाओं में नवाचार किया है. आर्थिक रूप से उचित लेकिन वित्तीय लिहाज से कमजोर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन के लिए अंतरिम बजट में घोषित वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना देश में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी. ऊर्जा भंडारण, सोलर मॉड्यूल और ई-मोबिलिटी के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की बदौलत भारत में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए उचित माहौल मिलने की उम्मीद है. भारत ने 2030 तक 500 गीगावॉट हरित ऊर्जा उत्पादन का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर रखा है, इसलिए तीव्र गति से काम करने वाली परियोजनाएं पहली प्राथमिकता बनी हुई हैं.

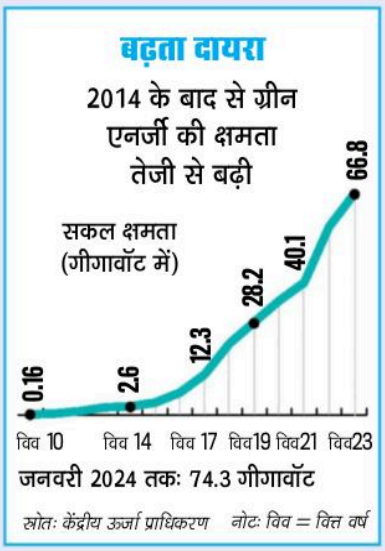

देश की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी रिन्यू के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा कहते हैं, ''निजी क्षेत्र को जरूरी पूंजी जुटाने और परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने की अपनी क्षमता को मजबूत करना होगा. भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में तेजी और श्रम बल का कौशल विकास भी इस दिशा में अहम साबित होगा.'' सिन्हा के साथी मानते हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के निर्माताओं के लिए कम कराधान और लेवी के तौर पर सरकारी समर्थन भी बेहद जरूरी है.

–अनिलेश एस. महाजन

देश के शेयर बाजारों में उत्साह का माहौल है. इस साल अप्रैल में सेंसेक्स 75,000 अंक को पार कर गया. भारत को निवेश के लिए बेहतर माना जाने लगा, जिससे भारतीय शेयरों में विदेशी धन के प्रवाह में मदद मिल रही है

बाहर निकालने के लिए फिजूलखर्ची के बजाए राजकोषीय संतुलन बनाए रखने का फैसला किया. उन्होंने अन्य बातों के अलावा, देश भर में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी निवेश करने पर जोर लगाया. रेल, सड़क और समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स में तेजी लाने के लिए पांच वर्षों में नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 2020 में 100 लाख करोड़ रुपए देने का वादा किया.

लगता है कि प्रधानमंत्री के अडिग रवैए और आश्वासन का फल मिला है, क्योंकि अर्थव्यवस्था ने मजबूती से वापसी की है, यहां तक कि विश्व नेताओं ने भी उसकी मजबूत जीडीपी वृद्धि की सराहना की है. हालांकि, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2013 में 6.4 फीसद के उच्च स्तर पर था, लेकिन उसका संतुलन कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक

आखिर कब लहलहाएगी फसल

नए कृषि कानून रद्द हो गए. क्षमता से अब भी काफी कम किसानों की आय बढ़ाने की खातिर उसके बाद भंडारण क्षमता के विस्तार और सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण पर खास ध्यान दिया जा रहा

राष्ट्रीय राजधानी में किसान संगठनों के करीब साल भर तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद नवंबर 2021 में कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों से जुड़े नए कानूनों को वापस ले लिया गया. इसके साथ ही कृषि क्षेत्र को कॉर्पोरेट निवेश के लिए खोलने की योजना भी ठप हो गई. केंद्र अब कृषि क्षेत्र के उपयुक्त ईको सिस्टम बनाने के लिए देशभर में सहकारी समितियों और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठनों) के नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. लेकिन इसमें काफी समय लगने के आसार हैं. इस बीच कुछ आंकड़े माथे पर बल डालते हैं—करीब 42 फीसद आबादी अपनी जीविका के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भर है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का सालाना योगदान करीब 17 फीसद है, और वार्षिक वृद्धि औसतन मात्र 4 फीसद ही है.

कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1.26 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो 2013-14 के आवंटन (27,700 करोड़ रुपए) की तुलना में करीब पांच गुना है. इन सबके बावजूद, 2023-24 में कृषि क्षेत्र के महज 1.8 फीसद की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023 में 4 फीसद की तुलना में भारी गिरावट को दर्शाता है. फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके अपने लक्ष्य का स्तर और बढ़ा दिया था. तब खेती-किसानी से जुड़े प्रति परिवार की औसत मासिक आय 8,059 रुपए थी. दिसंबर 2022 में संसद में पेश एक रिपोर्ट में बताया गया कि औसत मासिक आय सिर्फ 10,218 रुपए पर पहुंची है. वास्तविक आय दोगुनी करने के लिए कृषि उपज की कीमतों में 10 फीसद से अधिक दर से वृद्धि जरूरी थी लेकिन ये केवल 2.5 फीसद तक ही बढ़ पाईं. कृषि आय बढ़ाने के लिए संरचनात्मक स्तर पर बदलाव की जरूरत है, केवल एमएसपी बढ़ाने से ही काम नहीं चलने वाला. देश में भंडारण क्षमता की कमी और उत्पादकों और निजी प्रोसेसर्स के बीच पर्याप्त तालमेल का अभाव भी इसमें बाधा है.

एनडीए सरकार ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण पर खास जोर दिया ताकि संचालन में अधिक पारदर्शिता के साथ उन्हें विकेंद्रीकृत भंडारण से जोड़ा जा सके. वित्त वर्ष 2024 में इसके लिए 968 करोड़ रुपए दिए गए. 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक-निगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडबकल्यूआर) के इस्तेमाल का रोडमैप तैयार किया, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस क्षेत्र में दाखिल हो सकें और किसानों को (इन रसीदों के आधार पर) वित्तपोषण की सुविधा मिल सके.

रसीद आधारित व्यापार क्षमता के साथ भंडारण न केवल बर्बादी रोकने में मददगार है, बल्कि किसानों को फसलों में विविधता लाने के लिए प्रेरित भी करता है. यही नहीं, इससे बाजार में अवसर तलाशने में भी मदद मिलती है. जनवरी 2019 से ही कृषि-आधारित उत्पादों से जुड़े अनुबंधों के पालन में ई-एनडब्ल्यूआर का इस्तेमाल अनिवार्य हो चुका है.

—अनिलेश एस. महाजन

उठ नहीं रहा ग्राफ

कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में जीवीए (मूल कीमतों पर, % में) ऊपर नहीं उठा है

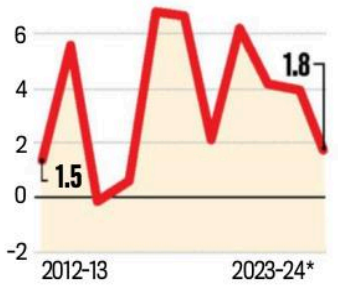

जीवीएः ग्रॉस वैल्यू ऐडेड
**पूर्वानुमान*
स्रोतः सांख्यिकी और कार्य. क्रिया. मंत्रालय

"किसानों को उनकी उपज की लाभकारी कीमत मिलनी ही चाहिए. कोऑपरेटिव इकाइयों को मजबूत करने के साथ आढ़त बाजारों का डिजिटलीकरण ही आगे का रास्ता दिखता है"

अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

प्रभजोत गिल

स्पष्ट उपाय था. हरित या स्वच्छ ऊर्जा पहल के लिए भी बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसने देश और विदेश में बड़े कॉर्पोरेट और शीर्ष निवेशकों का ध्यान खींचा. देश के शेयर बाजारों में भी उत्साह का माहौल है. इस साल अप्रैल में सेंसेक्स 75,000 अंक को पार कर गया. भारत को निवेश के लिए बेहतर माना जाने लगा, जिससे भारतीय शेयरों में विदेशी धन के प्रवाह में मदद मिल रही है.

इन उम्मीद की किरणों पर कुछ काले बादल भी हैं. एअर इंडिया और एलआइसी को छोड़कर, सरकार की पूर्ण संपत्ति बिक्री या निजीकरण की महत्वाकांक्षी योजनाएं बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं. इसी तरह कृषि सुधार की महत्वाकांक्षा को भी किसानों के साल भर के विरोध के सामने दफन करना पड़ा. इसलिए, मोदी के दो कार्यकालों में कृषि

कृषि क्षेत्र मोदी सरकार के रिकॉर्ड में बड़ा धब्बा बना हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग का भी वही हाल है. निर्यात कुछ बढ़े हैं, मगर कुल क्षमता से प्रदर्शन काफी पीछे है

विकास दर 4 फीसद पर स्थिर रही है और वित्त वर्ष 24 में फिसलकर 1.4 फीसद पर आ गिरी है. जाहिर है, किसान नीतिगत बदलाव से स्पष्ट रूप से नाराज हैं. श्रम सुधार भी अधर में हैं क्योंकि 2019-20 में पारित केंद्रीय कानून रुका हुआ है. उत्पादन क्षेत्र के लिए अहम भूमि सुधार प्रक्रिया भी अधूरी है. मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान पारित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को जल्द ही समाप्त हो जाने दिया गया.

जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान को 15 फीसद से से बढ़ाकर 25 फीसद करने और रोजगार सृजन का वादा सपना बनकर ही रह गया है. कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स इन्फ्रा में पिछड़ने के कारण, चीन की जगह वैकल्पिक वैश्विक आपूर्ति शृंखला बनने की इच्छा अधूरी है. हालांकि पिछले दो वर्षों में निर्यात में वृद्धि हुई है, फिर भी प्रदर्शन क्षमता से काफी कम है.

देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2020 में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना या पीएलआइ स्कीम का ऐलान किया था और 1.97 लाख रुपए के आवंटन के साथ उसका विस्तार 14 सेक्टरों में किया. मकसद यह था कि मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनाए जाएं और पांच साल में करीब साठ लाख नौकरियां पैदा की जाएं.

कामयाब | डिजिटल भुगतान

पूरी दुनिया में अगुआ

यूपीआइ आने के बाद वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2023 के बीच कुल डिजिटल भुगतान में 550 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई. इसके साथ ही इस मायने में भारत दूसरे देशों के लिए एक मॉडल बन गया

फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी को एक्स पर बड़ी घोषणा की, ''गणतंत्र दिवस के मौके पर एक भव्य समारोह के दौरान प्रतिष्ठित एफिल टावर पर यूपीआइ को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया.'' अब पेरिस स्थित इस ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचने वाले भारतीय पर्यटक टिकट खरीदने के लिए अपनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे. यह भारतीय पेमेंट गेटवे के यूरोपीय बाजार में दाखिल होने का प्रतीक है.

2016 में लॉन्च यूपीआइ खासकर उसी वर्ष नोटबंदी के बाद नकदीरहित अर्थव्यवस्था और डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की बुनियाद बनकर उभरा है. इसमें किसी व्यक्ति के कई बैंक खाते एक ही ऐप से संचालित हो सकते हैं. यह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर भी खास अहमियत रखता है क्योंकि कई देश विदेशी भुगतान के लिए अमेरिका-नियंत्रित स्विफ्ट पर

ई-पेमेंट का बढ़ता दबदबा

*वित्त वर्ष 24 के आंकड़े दिसंबर 2023 तक के

स्रोतः आरबीआइ/एनपीसीआइ/डिजिधन

इलस्ट्रेशनः राज वर्मा

अपनी निर्भरता घटाने के रास्ते तलाश रहे हैं. खासकर जब स्विफ्ट को रूस के खिलाफ 'हथियार' के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है.

यूपीआइ सिंगापुर, भूटान, यूएई, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस सहित कई पड़ोसी अर्थव्यवस्थाओं में पहले ही दाखिल हो चुका है. यूपीआइ को संचालित करने वाले नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) के मुताबिक, 2023 में 182.25 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 117.6 अरब यूपीआइ लेनदेन हुए. अगर 2022 से इसकी तुलना करें तो यह आंकड़ा मात्रा के मामले में 59 फीसद और मूल्य के मामले में 45 फीसद अधिक है. हालांकि, भारत

"इंडिया स्टैक और पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने लेनदेन की सहूलत को तो बढ़ाया ही है, विभिन्न सेवाओं को समाज में दूरदराज तक ले जाने के रास्ते खोल दिए हैं"

आदित्य मलिक, सदस्य, बीओजी, काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग

में नकदी के इस्तेमाल का रुझान बरकरार है—इसका प्रचलन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 फीसद है, जो नोटबंदी के तुरंत बाद महज 8.7 फीसद रह गया था.

भारतीय रिजर्व बैंक अब दो क्रांतिकारी पहलकदमियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. ये हैं ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल रुपया और आधार से जुड़ी भुगतान सेवा (एईपीएस). वित्तीय समावेशन पक्का करने का साधन बना एईपीएस आधार प्रमाणीकरण के जरिए पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) पर ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं की सुविधा देता है. अब जबकि डिजिटल भुगतान को लेकर सारी नजरें वैश्विक मंच पर टिकी हैं, मोदी सरकार यह पक्का करने में भी लगी है कि ग्रामीण क्षेत्र पीछे न छूट जाएं. *—अनिलेश एस. महाजन*

नाकाम नोटबंदी

कौन-से काले धन पर चोट?

नोटबंदी ने बेशक भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में तो केंद्रीय भूमिका निभाई पर वह कालेधन पर रोक लगाने के अपने असली मकसद में तो पूरी तरह नाकाम रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में मददगार बनी नोटबंदी का जब ऐलान किया था तब इसका मकसद था, काले धन पर अंकुश लगाना. पर वह उसमें पूरी तरह नाकाम रही है.

पीएम मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को देर शाम प्रसारित अपने संबोधन में कहा कि 500 रुपए और 1,000 रुपए के सभी करेंसी नोट आधी रात के बाद वैधानिक मुद्रा नहीं रहेंगे. पूरे देश के लोग हक्का-बक्का रह गए. नोटबंदी के कारण प्रचलन में मौजूद मुद्रा का 86 फीसद हिस्सा चलन से बाहर हो गया. सरकार ने दावा किया था कि इसके तीन व्यापक उद्देश्य हैं: काले धन पर वार और भ्रष्टाचार तथा आतंक के खिलाफ जंग. फिर बाद में अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को एक अन्य लक्ष्य के तौर पर जोड़ा गया. विश्व बैंक ने 2007 में अनुमान लगाया कि भारत की परोक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 23 फीसद है, और इसी वजह से काले धन पर वार की जरूरत पर जोर दिया गया.

कैश तो अब भी किंग

नोटबंदी के समय जितनी करेंसी चलन में थी, आज उसके दुगुना हो गई है

(आंकड़ा लाख करोड़ रुपए में)

स्रोत: सीईआइसीडेटा.कॉम

"नकदी और कालेधन को लेकर सरकार का अनुमान और समीकरण पूरी तरह से गलत था. नकदी तो कालेधन का एक नितांत छोटा-सा चेहरा है"

सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व वित्त सचिव

इस कदम से आम आदमी तो हैरान-परेशान हुआ ही, व्यापक आर्थिक गतिरोध भी पैदा हुआ. वैसे, सचाई यही है कि यूपीआइ के आने से अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण में तेजी आई पर इससे प्रचलन में मौजूद मुद्रा की मात्रा में कोई कमी नहीं आई. अगस्त 2018 में रिजर्व बैंक ने खुलासा किया था कि नोटबंदी के कारण चलन से बाहर हुई मुद्रा का 99.3 फीसद यानी कुल 15.3 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग प्रणाली में लौट आए. यानी या तो सरकार ने काले धन की मात्रा का गलत अनुमान लगाया था या अधिकांश बेहिसाब धन बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया. *—एम.जी. अरुण*

कामयाब | माल और सेवा कर

अच्छी पहल है, कार्य प्रगति पर है...

परोक्ष करों की दिशा में सबसे बड़े सुधार जीएसटी ने एक बेहद जटिल और बिखरी हुई प्रणाली की जगह ली. टैक्स ढांचे में एकरूपता लाने के साथ इसने लॉजिस्टिक्स को आसान बनाया और सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ाया

आयरलैंड की फर्म रिसर्च ऐंड मार्केट्स ने हाल में भविष्यवाणी की कि भारत के वेयरहाउस बाजार का आकार करीब 15.6 फीसद की दर से बढ़ते हुए वर्ष 27 के अंत तक 35 अरब डॉलर का हो जाएगा. वित्त वर्ष 21 में यह बाजार करीब 14.6 अरब डॉलर का था. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 16 से 21 के बीच 17 फीसद की वार्षिक वृद्धि हुई. यह वही समय था जब केंद्र ने 2017 में बड़े परोक्ष कर सुधार माल और सेवा कर लागू किया जिसने टैक्स संबंधी मुश्किलें हटाईं और लॉजिस्टिक फर्मों को बड़े वेयरहाउस लीज पर लेने या शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया.

परोक्ष कर व्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों में से एक इस नए कर ने केंद्र और राज्यों के लगाए जा रहे 17 करों को हटा दिया. इनमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर के अलावा अन्य कर शामिल थे. नतीजा: समूचे भारत की कर व्यवस्था में एकरूपता आई और अंतिम उत्पादों की कीमतों पर करों का व्यापक असर खत्म हुआ क्योंकि यह कर आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण, निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक लगाया जाता है. यह हर चरण के वैल्यू एडिशन पर लागू होता है जिसमें क्रेडिट फ्लो निर्बाध होता है और उपभोक्ता पर कर का बोझ घटता है.

जीएसटी के सकारात्मक असर सहज लॉजिस्टिक आवाजाही में भी झलकते हैं. सामान से लदे ट्रकों को अब राज्यों में प्रवेश और निकासी पर नहीं रुकना पड़ता, कई दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो गई है. इससे कर राजस्व का भी दायरा बढ़ा है और कर संग्रह की प्रक्रिया लागत में कमी आई है. वित्त वर्ष 24 में सकल जीएसटी संग्रह 20.4 लाख करोड़ रुपए था—जिसने पहली बार 20 लाख करोड़ रु. का पड़ाव पार किया. यह पिछले साल के मुकाबले 11.6 प्रतिशत ज्यादा है.

लेकिन शराब, बिजली, तंबाकू, चुंगी, भूमि और वाहन खरीद पर स्टांप ड्यूटी जैसे उत्पादों

पेट्रोलियम उत्पादों के सभी करों के एक किए जाने पर अभी सहमति नहीं बन पाई है. तमाम तरह के टैक्स स्लैबों में भी एकरूपता लाए जाने की जरूरत है

नाकाम | एमएसएमई

वजूद के लिए चल रहा भारी संघर्ष

सरकार की राहत योजनाएं एमएसएमई क्षेत्र का विकास करने में नाकाम रही हैं. यह क्षेत्र जिंसों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक मांग में मंदी से जूझ रहा

कोविड महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र था एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम). उपभोक्ता मांग और नकदी की कमी के कारण अनेक इकाइयां बंद हो गईं. इनके कारोबार को चलाए रखने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू कीं जिनमें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और सूक्ष्म और छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट शामिल थीं. इसके अलावा डिजिटलीकरण पर फोकस—जो माल और सेवा कर और ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल उद्यम जैसी पहल में स्पष्ट था—ने इस क्षेत्र को औपचारिक स्वरूप लेने को बढ़ावा दिया. अभी तक करीब 2.5 करोड़ एमएसएमई ने सरकार से लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है.

हालांकि इस क्षेत्र की चुनौतियों का कोई अंत नहीं दिखता. जहां इस क्षेत्र पर पश्चिमी बाजारों की मंदी से चोट पहुंची है, वहीं रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने मांग कमजोर कर दी है. जिंसों खासतौर से कच्चे तेल और इस्पात कीमतों में उतार-चढ़ाव ने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सभी एमएसएमई के लिए उत्पादन योजना और मूल्य को और जटिल बना दिया है. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो ऐंड स्मॉल ऐंड मीडियम इंटरप्राइजेज (फिस्मे) के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत पटेल आगाह करते हैं, "अगर चुनौतीपूर्ण स्थिति बरकरार रही तो छंटनियां और बढ़ते फंसे कर्जों को टाल पाना मुश्किल होगा."

भारत के समूचे मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में एमएसएमई का हिस्सा अपेक्षाकृत स्थिर रहा है. यह वित्त वर्ष 20, वित्त

लगातार छलांग

वर्षवार हर महीने का औसत जीएसटी संग्रह (हजार करोड़ रुपए में)

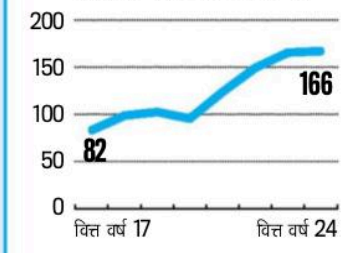

स्रोतः वित्त मंत्रालय

से संबंधित कुछ मसले हैं. साथ ही माल और सेवाओं के निर्यात पर शून्य दर से जीएसटी का भी मसला है. इसी तरह पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस) पर लगने वाले करों के विलय को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. जीएसटी को विभिन्न स्लैब में वर्गीकृत किया गया है—5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. सरलीकरण के लिए इन स्लैब को सुसंगत बनाने की जरूरत है.

राष्ट्रव्यापी जीएसटी के विचार का प्रस्ताव सबसे पहले 2000 में परोक्ष करों पर बनाए गए विजय केलकर कार्यबल ने रखा. इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल कर ढांचे को एकीकृत प्रणाली से बदलना था. 2011 में संविधान संशोधन विधेयक लाया गया लेकिन राज्यों को क्षतिपूर्ति और अन्य मसलों को लेकर इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा. संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक, 2014 का उद्देश्य जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना था. तय हुआ कि एक जीएसटी उपकर लगाया जाएगा जिससे कि 'घाटे वाले' राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जा सके. संसद ने अगस्त 2016 में इसे पारित किया. कर दरों और रियायतों सहित जीएसटी के बारे में फैसला लेने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के प्रतिनिधियों की एक जीएसटी परिषद बनी. इसने भारत में जीएसटी की व्यवस्था को स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाई.

–अनिलेश एस. महाजन

लेकिन आरबीआइ के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जैसे आलोचकों का कहना है कि इस योजना ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर सब्सिडी की बरसात की है और कोई गारंटी नहीं है कि ये कंपनियां सब्सिडी खत्म होने के बाद टिकी रहेंगी. राजन का तर्क है कि यह रकम सेवा क्षेत्र में इजाफे के लिए बेहतर इस्तेमाल की जा सकती थी, जिसका देश की जीडीपी में अब योगदान 55 फीसद है और सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हो रहे हैं, जिसमें साल-दर-साल आधार पर वृद्धि दर औसत 7 फीसद है. वित्त वर्ष 23 में सेवाओं के निर्यात में 322 अरब डॉलर का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ, जिसकी सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर वित्त वर्ष 22 के मुकाबले 26.7 फीसद है. मसलन, पर्यटन में वृद्धि की भारी संभावना है, मगर असली सवाल मांग की पूर्ति के लिए लोगों के हुनर और प्रशिक्षण में निवेश करने का है.

मोदी के दो कार्यकालों में कृषि विकास दर 4 फीसद पर स्थिर रही है और वित्त वर्ष 24 में फिसलकर 1.4 फीसद पर आ गिरी है. जाहिर है, किसान नीतिगत बदलाव से स्पष्ट रूप से नाराज हैं. निर्यात बढ़ा है लेकिन उसमें अभी बहुत संभावनाएं हैं

इस सबके अलावा, यह देखते हुए कि हम चुनावी वर्ष में हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का रिकॉर्ड पर जनता की तीखी निगाह है. सत्तारूढ़ भाजपा दावा करती है कि बेरोजगारी दर घटी है और यह 2018-19 में 5.8 फीसद से कम होकर 2022-23 में 3.2 फीसद रह गई. साथ ही श्रमिकों की भागीदारी दर भी 2018-19 में 50.2 फीसद से बढ़कर 2022-23 में 57.9 फीसद तक पहुंच गई है. विशेषज्ञ इसे कड़वी सचाई को छिपाने के लिए सुविधाजनक आवरण बताकर खारिज करते हैं और कहते हैं कि वास्तविक वृद्धि स्व-रोजगार में है, जो अधूरे रोजगार का पैमाना है. भारत के कार्यबल का 20 प्रतिशत ही औपचारिक रोजगार से जुड़ा हुआ है. *इंडिया टुडे* के साथ बातचीत में वित्त मंत्री सीतारमण कहती हैं कि ठोस रोजगार के आंकड़े मिलना मुश्किल हैं, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना आसान नहीं है लेकिन वे स्टार्ट-अप की वृद्धि, छोटे कारोबारियों द्वारा मुद्रा ऋण के बढ़ते उठाव, नए हरित ऊर्जा क्षेत्रों की वृद्धि और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बड़े निवेश का जिक्र करते हुए कहती हैं कि भारी संख्या में रोजगार का सृजन हो रहा है (*देखें बातचीत*).

वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 में क्रमशः 36.6 प्रतिशत, 36.9 प्रतिशत और 36.2 प्रतिशत रहा. इसी तरह एमएसएमई विशिष्ट उत्पादों के हिस्से की भारत के कुल निर्यात में लगातार गिरावट दिख रही है. यह वित्त वर्ष 21 में 49.4 फीसद था जो वित्त वर्ष 22 में 45 फीसद और वित्त वर्ष 23 में 43.6 फीसद रह गया. फिस्मे ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सरकार से मांग की है कि वह नियमन जैसी बाधाएं हटाए और इस क्षेत्र को बढ़ने दे.

हाल न पूछिए

वित्त वर्ष 17 के बाद से एमएसएमई से निर्यात मोटे तौर पर घटता आया है

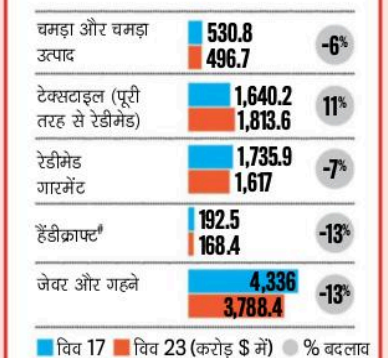

(*हैंडमेड कार्पेट को छोड़कर) *नोटः वित्त = वित्त वर्ष*

**स्रोतः सीएमआइई इकोनॉमिक आउटलुक*

इस क्षेत्र के दबाव का पूरी तरह पता नहीं चलता. इसका आंशिक कारण यह भी है कि इसके आकार को लेकर सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. एमएसएमई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, 2015-16 में जुटाए गए एनएसएसओ के आंकड़ों के आधार पर भारत में 6.3 करोड़ एमएसएमई हैं. हालांकि 2020 में एमएसएमई की परिभाषा में व्यापक बदलाव हुआ है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूरू में अर्थशास्त्री और वरिष्ठ प्रोफेसर एम.एच. बाला सुब्रह्मण्य तर्क देते हैंः क्योंकि यह क्षेत्र आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का शहरी में रूपांतरण होने से नए उद्यम उभर रहे हैं, लिहाजा इनकी वृद्धि के लिए कारगर नीति बनाने के लिए अपडेटेड डेटा महत्वपूर्ण हैं. पहेली की इस हिस्से की गुत्थी को सुलझाए बिना भारत की वृद्धि की कहानी में एमएसएमई का योगदान दिखाई नहीं देगा. *–सोनल खेत्रपाल*

ऐसा लगता है कि महंगाई पर नियंत्रण के मामले में सरकार ने बेहतर किया है. पहले कोविड के कारण आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और फिर पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में तनाव की लपटों, जिससे बुनियादी चीजों की वैश्विक कीमतों पर असर हुआ, के बावजूद औसत महंगाई 2014-15 से 2023-24 (नवंबर तक) महज 5.1 फीसद रही. इससे पहले मनमोहन सरकार (2004-14) के पिछले 10 वर्ष के दौरान यह 8.2 फीसद थी. हालांकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई ऊंची बनी हुई है, खास तौर पर चुनावी वर्ष में, जुलाई 2003 के बाद से ही यह करीब 8.7 फीसद के औसत

रोजगार तथा नौकरियों का अभाव और खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें फिलहाल मतदाताओं की चिंता के विषय हैं. के-आकार की वृद्धि का मतलब यह है कि ग्रामीण मेहनताने और मांग में कमी बनी हुई है. छोटे और मझोले उद्योग अभी तक कोविड के झटकों से उबर नहीं पाए हैं

पर है. इतना ही नहीं, जहां अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्से बेहतर काम कर रहे हैं, अन्य हिस्से पिछड़ रहे हैं जिस कारण अर्थशास्त्री इसे 'के-आकार' की वृद्धि बताते हैं. छोटे और मझोले उद्योग इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराते हैं. लेकिन वे अभी तक कोविड के झटकों से उबर नहीं पाए हैं. हालांकि सरकार का दावा है कि उसने विभिन्न योजनाओं के जरिए उनकी मदद की है. के-आकार की वृद्धि का एक और पहलू यह है कि जहां कंपनियों में वेतन में औसतन 10 फीसद का इजाफा हुआ है, वहीं ग्रामीण श्रमिकों, जिनमें

कामयाब | बैंकिंग

सुधार पर जोर

कई क्षेत्रों में एफडीआइ और निजी पूंजी को बढ़ावा देने से लेकर बैंकिंग क्षेत्र को साफ-सुथरा बनाने और दिवाला प्रक्रिया में न्यायिक अनुशासन लाने तक, मोदी सरकार ने सावधानी के साथ विकास पर जोर दिया है

वर्ष 2008 में कुछ देशों में आए आर्थिक संकट के दौरान देखा गया कि देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रोत्साहनों का ऐलान किया. भारत भी इसका अपवाद नहीं था. हालांकि, भारी मात्रा में पूंजी झोंकने से अपव्यय बढ़ा और डूबत ऋण या खराब कर्ज की संख्या बढ़ती गई जिससे ट्विन बैलेंस शीट की समस्या उत्पन्न हुई, अत्यधिक कर्ज लेने के चलते कॉर्पोरेट्स उन्हें चुकाने में विफल रहे, इससे बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) बढ़ीं जिससे उन पर भारी दबाव पड़ा.

मार्च 2010 में जो एनपीए 60,000 करोड़ रु. था वह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले यानी मार्च 2014 में तीन गुना बढ़कर 2 लाख करोड़ रु. के स्तर पर पहुंच गया था. मार्च 2018 तक यह बढ़ते हुए 10.2 लाख करोड़ रु. जितना भारी भरकम हो गया और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का हिस्सा 80 प्रतिशत था.

इस सबसे बैंक कमजोर हुए और उनकी कर्ज देने की क्षमता प्रभावित हुई. बड़ी संख्या में कंपनियां भूमि अधिग्रहण और कच्चा माल खरीदने से जुड़े संकटों में उलझ गईं, लिहाजा कॉर्पोरेट्स और व्यक्तियों के दिवालिया और शोधन अक्षमता की प्रक्रिया की खातिर एक व्यापक संहिता की अनिवार्यता महसूस हुई. इसमें न्यायिक अनुशासन भी शामिल होना था. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आइबीसी) 2016 का मकसद 1956 और 2013 के कंपनी अधिनियम में कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों और विसंगतियों को संबोधित करना है. यहां तक कि 1985 का सिक (बीमारू) इंडस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोवीजंस) ऐक्ट 1985 भी इस मोर्चे पर नाकाम ही साबित हुआ. 2016 के अंत में आइबीसी लागू होने के बाद से दिसंबर 2023 तक कुल मिलाकर 887 दिवालिया कंपनियों के दिवालियापन का समाधान किया गया. लेनदारों के लिए कुल वसूली लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए या उनके स्वीकृत दावों की लगभग 32 फीसद रही.

इसका मतलब यह था कि बैंकों को अपने लोन पर भारी हेयरकट लेना पड़ा, फिर भी कुछ बकाया लोन चुकाया गया. बैड लोन में कमी लाने के लिए भी कई उपाय किए गए. वर्ष 2023 के अंत तक, सकल एनपीए घटकर 4.85 लाख करोड़ रुपए हो गया. बैंकों की ओर से कर्ज वसूली के साथ-साथ कुछ बड़े राइट-ऑफ (देनदारियों के खाते से डेबिट करते समय परिसंपत्ति के मूल्य को कम करना) इस कमी का कारण हैं, जिसे कुछ आलोचकों ने 'विंडो-ड्रेसिंग' की संज्ञा दी है.

केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की बैलेंस शीट मजबूत करने और ऋण देने की उनकी क्षमता में सुधार के लिए एक बड़ा समेकन भी किया. यह भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) के 2017 में अपने पांच सहायक बैंकों के अधिग्रहण के साथ शुरू हुआ. आज, केवल 12 पीएसबी हैं जबकि वर्ष 2017 में यह संख्या 27 थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''हमें खुशी है कि हमने भारतीय बैंकों को फिर से अच्छी स्थिति में ला दिया है, लेकिन पूरे क्षेत्र को और अधिक जीवंत बनाने की जरूरत है और इसके लिए हमें और अधिक बैंकों की आवश्यकता है.'' साथ ही जोड़ा कि इसमें बड़े और छोटे दोनों बैंक शामिल होंगे. *—एम.जी. अरुण*

4.85
लाख करोड़ रु.
सकल एनपीए दिसंबर 2023 में, वित्त वर्ष 2018 के 10.2 लाख करोड़ रु. के मुकाबले काफी कम

3.2
लाख करोड़ रु.
कर्जदाताओं को दिवालिया फर्मों से वसूली प्रक्रिया के दौरान हासिल हुए (2016-23)

12
संख्या है अभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की 2017 के 27 बैंकों के मुकाबले

नाकाम निर्यात

व्यापार की पहेली

भारत अब तक अपनी निर्यात क्षमता को पहचान नहीं पाया है, जो विकसित भारत के सपने को पटरी से उतार सकती है और देश को चीन+1 अवसर का लाभ उठाने से रोक सकती है

असल में, निर्यात लंबे वक्त से भारत की दुखती रग है. पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया में लगातार अशांति, लाल सागर में गतिरोध और वैश्विक बाजारों में वृद्धि की धीमी गति के कारण अपनी विभिन्न योजनाओं—आत्मनिर्भर भारत हो या प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ)—के जरिए इस दिशा में सुधार लाने की मोदी सरकार की उम्मीदों को झटका ही लगा है.

विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2013 में माल और सेवाओं का निर्यात जहां सकल घरेलू उत्पाद का 25 फीसद था वहीं 2022 में घटकर 22.8 फीसद पर पहुंच गया. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएं) 777 अरब डॉलर होने का अनुमान है, जो एक साल पहले की तुलना में 0.04 फीसद अधिक है. वहीं, डब्ल्यूटीओ के मुताबिक, 2023 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8 फीसद थी.

राहत की बात यह है कि भारत वित्त वर्ष 2024 में अपना व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 में 121 अरब डॉलर से घटाकर 78 अरब डॉलर करने में सफल रहा है. वह बीते दशक में अपने निर्यात क्षेत्र का दायरा बढ़ाते हुए उसमें पेट्रोलियम, मशीनरी, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, जैव प्रौद्योगिकी सहित कई अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करने में सफल रहा है. हालांकि, कपड़ा और परिधान, चमड़ा, रत्न और आभूषण तथा हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक श्रम-प्रधान क्षेत्र अपनी चमक खो रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन प्रभावित हो रहा है.

ज्यादातर विशेषज्ञ इससे सहमत हैं कि भारत को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वैश्विक मानक के अधिक उत्पाद विकसित करने और नए बाजार तलाशने की जरूरत है. कोविड-19 महामारी के बाद, विकसित देशों में जीवीसी यानी ग्लोबल वैल्यू चेन (वैश्विक मूल्य श्रृंखला) और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए क्षेत्रों के विकास की मांग बढ़ी है, जिस पर अभी चीन का प्रभुत्व है. भारत को इस दिशा में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे आसियान देशों के साथ-साथ पड़ोसी बांग्लादेश से भी कड़ी चुनौती मिल रही है.

प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, आपूर्ति श्रृंखला की लागत घटाकर और निर्यात-संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार करके निर्यात के लिए एक उपयुक्त माहौल बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. इसमें माल ढुलाई में सुधार के लिए राजमार्गों का निर्माण, रेल नेटवर्क का विस्तार और समर्पित माल गलियारों की स्थापना शामिल है. पर भारत को वैश्विक ख्याति वाली शिपिंग लाइन विकसित करने में सीमित सफलता मिली है. एफआइईओ के महानिदेशक और सीईओ अजय सहाय कहते हैं, ''हमें माल के बदले देश में आने वाले पैसे में 80 अरब डॉलर से अधिक का नुक्सान हो रहा है. भविष्य में जब हमारा निर्यात 10 खरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, तो यह 200 अरब डॉलर तक हो सकता है. एक भारतीय शिपिंग लाइन, जिसे कारोबार का 25 फीसद हिस्सा मिले, इस राशि में साल-दर-साल के आधार पर 50 अरब डॉलर की कमी ला सकती है.''

भारत की नीति में भी बदलाव आ रहा है. मोदी सरकार मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर संदेह करती रही है. मगर, अब भारत ने व्यापार को लेकर सकारात्मक रुख रखने वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ एफटीए पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया है. 2021 में भारत ने मॉरिशस के साथ तो 2022 में संयुक्त अरब अमीरात और इस वर्ष ईएफटीए ब्लॉक के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते पर दस्तखत किए. *—अनिलेश एस. महाजन*

मंदार देवधर

खुशहाली का ख्याल

सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से देशभर में जरूरी सेवाएं मुहैया कराने में भारी कामयाबी मिली

गेट्टी इमेजेज

दरअसल, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सिद्धांत अंत्योदय (यानी कोई न छूटे) है. नल से पेयजल, रसोई गैस कनेक्शन, सबके लिए आवास और स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने सरीखे कार्यक्रमों से यही हुआ है.

इसका सबूत देशभर में इनका लाभ पाने वालों की संख्या है. मसलन, सबसे प्रमुख पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं; स्वच्छ भारत योजना के तहत 11.72 करोड़ शौचालय बने हैं; हर घर नल से जल योजना के तहत 14.67 करोड़ घरों में नल का पानी पहुंचा और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं.

स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ तथा नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल कहते हैं, ''मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत है.'' डेटा से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में 77,298 करोड़ रुपए के खर्च से छह करोड़ मामलों का इलाज हुआ. सरकार का अनुमान है कि इससे देश के लोगों को अपनी जेब से होने वाले खर्च में 1.25 लाख करोड़ रुपए की भारी बचत हुई है. इस मद में जन औषधि केंद्रों से और मदद मिली है, जहां सस्ती दवाएं मिलती हैं. अब ऐसी 10,000 से अधिक दुकानें हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड-19 के दौरान कई अहम उपलब्धियां संभव हुई हैं. डॉ. पॉल कहते हैं, ''वह अप्रत्याशित संकट था, मगर कामयाबी हमारे टीकाकरण कार्यक्रम से मिली, जिसके तहत देश में निर्मित 2.2 अरब टीके मुहैया कराए गए.'' उस समय के अन्य प्रमुख लाभ में आइसीयू बिस्तरों को 2,168 से बढ़ाकर 1,44,000 करना, ऑक्सीजन वाले बिस्तरों को 50,583 से बढ़ाकर 5,14,000 करना और 1,500 पीएसए संयंत्र (मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन) की मंजूरी शामिल है. इनमें अधिकांश अब भी स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में शामिल हैं.

सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के लिए मानव संसाधन जुटाने में भी निवेश किया है. अगर आयुष डॉक्टरों को जोड़ लें, तो डॉक्टर-मरीज अनुपात 1:834 है. डॉ. पॉल कहते हैं, ''हमारे पास नर्सिंग, कौशल, शिक्षा, फार्मा और दंत चिकित्सा के लिए मानव संसाधन नीतियां हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में पूरे तंत्र में दिखेगा.'' 2014 से चिकित्सा संस्थानों में कुल 57,592 एमबीबीएस सीटें और 39,489 पीजी सीटें जोड़ी गई हैं, और 15 नए एम्स और 225 अन्य नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं.

डिजिटल स्वास्थ्य सेवा सरकार के फोकस का एक अहम हिस्सा है. आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए 15 करोड़ टेली-परामर्श दिए गए हैं. सरकार ने ऐसे 1,64,000 केंद्र स्थापित किए हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है.

कई लोग कहते हैं कि असली कामयाबी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए रखी गई नींव है. एम्स, दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ''जब आप स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, तो आपको जमीनी स्तर की बुनियादी बातों सहित सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए.'' नतीजतन, लिंगानुपात के मामले में पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाएं है, और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित शिशु जन्म में 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई. विशेषज्ञ इसका श्रेय मातृ तथा शिशु देखभाल के लिए 3.94 करोड़ मुफ्त प्रसवपूर्व जांच और आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को देते हैं. इसमें कन्या के जन्म पर मिलने वाले लाभ की भी अहम भूमिका है. करीब दस लाख आशा और 13 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से स्वास्थ्य सेवा उपायों को सरकार के कल्याण लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है, ताकि कोई भी पीछे न छूटे.

—सोनाली अचार्जी

75% गांव **खुले में शौच से मुक्त** हो गए हैं

9.6 करोड़ **खाना पकाने के गैस कनेक्शन** प्रदान किए गए पीएम उज्ज्वला योजना के तहत

3 करोड़ **मकान** बनाए गए पीएम आवास योजना के तहत

76% परिवारों को **नल का जल** मुहैया कराया गया है *हर घर नल से जल* योजना के तहत

6.0 करोड़ **अस्पताल दाखिले हुए** अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के तहत

10,000 **जन औषधि** केंद्र काम कर रहे हैं

2.2 अरब **भारत में निर्मित टीके** कोविड के दौरान लगाए गए

>97,000 **सीटें** मेडिकल संस्थानों में जोड़ी गई हैं

नाकाम कौशल विकास

खाई बरकरार

देश कामकाजी आबादी में हुनर की खाई पाटने का काम युद्धस्तर पर करे, तभी 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा

इस साल 1 फरवरी को 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2015 में शुरू हुए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) के असर पर रोशनी डालने के लिए कुछ बड़े आंकड़े सामने रखे. उनके अनुसार, 1.4 करोड़ युवाओं का कौशल विकास किया गया, और अन्य 54 लाख का कौशल बढ़ाया गया या उनमें फिर से कौशल विकसित किया गया. 3,000 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) स्थापित किए गए जो देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की रीढ़ हैं. तेजी से बूढ़ी होती दुनिया में, भारत का जनसंख्या लाभ उसके महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों के लिए वरदान माना जाता है. मगर सही कौशल और नौकरियों के बिना, देश की 65 फीसद आबादी के 35 साल से कम उम्र के होने का लाभ आसानी से गंवाया जा सकता है.

इसलिए एनएसडीएम के तहत विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इनमें एक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) का एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाइ) है. कौशल प्रशिक्षण पर जोर है, फिर भी रोजगार योग्यता बड़ा मुद्दा बनी हुई है. मसलन, पीएमकेवीवाइ 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 17 और वित्त वर्ष 23 (5 जनवरी, 2023 तक) के बीच लगभग 1.1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, मगर उनमें सिर्फ 21.4 लाख या 20 फीसद को ही नौकरी मिल पाई.

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्योग अनुकूल कौशल की कमी इसकी एक प्रमुख वजह है. देश में कौशल पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सरकार के नेतृत्व में होते हैं, जो उत्पादक साबित नहीं हुए हैं. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के पूर्व सीईओ तथा सीओओ जयंत कृष्णा कहते हैं, ''सिखाने और प्रशिक्षण के लिए उद्योगों में कार्यरत लोग बेहतर होते हैं.'' वे कहते हैं कि बेहद गरीब लोगों के लिए कौशल प्रशिक्षण पर रियायत दी जानी चाहिए और कौशल में उद्योग की भूमिका बढ़ाना बहुत जरूरी है.

ऐसे में हैरानी नहीं कि प्रशिक्षण पाए उम्मीदवारों के कौशल में भी कमी है. ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड टेस्टिंग फर्म व्हीबॉक्स की 'इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023' के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न डोमेन में 3,75,000 परीक्षार्थियों में से केवल 50.3 फीसद ही 'बेहद रोजगार योग्य' पाए गए. व्हीबॉक्स के संस्थापक और सीईओ निर्मल सिंह कहते हैं, ''बड़े बदलाव'' की जरूरत है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी और नौकरियां कौशल प्रशिक्षण को 'जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया' बना देती हैं. *–सोनल खेत्रपाल*

रिपोर्ट कार्ड

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0* के तहत प्रशिक्षण पाने वालों में से केवल 20 फीसद को नौकरी के ऑफर मिले

*वित्त वर्ष 17-वित्त वर्ष 23 (जन. 2023 तक)

स्रोतः कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

> **"पीएमकेवीवाइ सरीखी सरकारी योजनाओं ने उद्योग की अगुआई वाले और फीस आधारित कौशल विकास के बाजार को परे धकेल दिया है"**
>
> **जयंत कृष्णा,** पूर्व सीईओ और सीओओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

कृषि मजदूर भी और शहरी कामगारों का एक हिस्सा भी शामिल है, की मजदूरी में पिछले एक साल में महज एक फीसद या उससे कम की बढ़ोतरी हुई है. मोदी सरकार ने परोक्ष रूप से उनकी दारुण हालत को माना है और 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना पांच साल और बढ़ा दी है. इस योजना को अप्रैल 2020 में कोविड के दौरान शुरू किया गया था. श्रमिकों के हाथ में अपने रोजमर्रा की जरूरतें किसी तरह पूरी करने के अलावा अधिक पैसा नहीं होने से खपत में भारी गिरावट आई है. इसकी वजह से निजी क्षेत्र की निवेश और वस्तु और सेवाओं के विस्तार की इच्छा कुंद हो गई है. गैर-भाजपा शासित राज्य, खास तौर से दक्षिण में, भी कर में हिस्सेदारी को लेकर केंद्र के रवैए से नाखुश हैं और अपने योगदान की तुलना में कम हिस्से का हवाला देते हैं.

अब जबकि देश में आम चुनाव का बुखार बढ़ता जा रहा है तो इन सब का मतदाताओं के मानस पर क्या असर होगा? विकास के चार इंजन में से केवल एक—भारी सार्वजनिक खर्च—अभी भी चल रहा है. निर्यात उतना अच्छा नहीं है, जितना दिखता है. निजी निवेश और खपत बढ़ने लगी है. हालांकि उनमें इससे बहुत-बहुत अच्छे प्रदर्शन की ताकत है मगर कर नहीं पा रहे हैं. वित्त मंत्री बातचीत में कहती हैं कि अगर प्रधानमंत्री फिर से जीतकर आते हैं तो मोदी 3.0 में सभी महत्वपूर्ण आर्थिक मसलों पर बहुत तेजी से काम किया जाएगा. सभी बड़े लोकतंत्रों की तरह भारतीय मतदाता यह फैसला करेगा कि क्या प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर अच्छा काम किया है और वह तीसरे कार्यकाल के योग्य है. ■

बातचीत | निर्मला सीतारमण

“मोदी 3.0 में टेक्नोलॉजी से जुड़े बदलाव हमारी बड़ी प्राथमिकता होंगे”

आम चुनाव 2024 के दौर में केंद्रीय वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** नॉर्थ ब्लॉक के लकदक परिसर से निकलकर चुनावी मैदान की धूल-गर्मी झेल रही हैं. चुनाव प्रचार की अपनी भारी व्यस्तता के बीच उन्होंने ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर **राज चेंगप्पा** और मैनेजिंग एडिटर **एम.जी. अरुण** के साथ खास बातचीत में बेबाकी से जवाब दिए. उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई जैसे असहज मसलों सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर रोशनी डाली और यह भी बताया कि अगर भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आती है तो हम मोदी 3.0 से क्या उम्मीद कर सकते हैं. बातचीत के संपादित अंशः

सभी फोटोः बंदीप सिंह

प्र. मोदीनॉमिक्स के 10 साल हो गए हैं. मोदी सरकार की नीतियों के चार मुख्य स्तंभ क्या रहे हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था न सिर्फ महामारी के बाद पटरी पर लौटी, बल्कि 7.6 फीसद की मजबूत वृद्धि दर्ज की?

मेरे दिमाग में जो चार बातें फौरन आती हैं, उनमें एक, भारत के बारे में भ्रामक धारणा को दूर करने के लिए किया गया प्रयास है कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं, कि आप बढ़ नहीं सकते, कि आप भ्रष्ट हैं, कि आपकी लालफीताशाही हमेशा कायम रहेगी...दूसरा, यह तय करना कि नीतियां लोगों और उनकी जरूरतों के मुताबिक हों—इतनी रैडिकल न हों कि खारिज कर दी जाएं, लेकिन भारत को आगे ले जाएं, नीतियां स्थिर हों जो लोगों को हमारे देश की ओर आकर्षित करें, अपने देश के लोगों को यकीन दिलाएं कि सरकारें काम कर सकती हैं और न सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों, बल्कि व्यावस्था में सुधार के लिए भी. तीसरा, यह तय करना रहा कि उन क्षेत्रों की पहचान की जाए, जिनमें नीतियां टिकाऊ विकास के साथ 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनें. और चौथा, उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें भारत विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकता है, उनमें निवेश करें और लोगों को उस ओर बढ़ने में मदद मुहैया करें और देश को फायदा पहुंचाएं.

• आपने सुधारों में संतुलन बनाए रखने की बात की, मगर 2016 में नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया. उसके अमल से क्या सबक मिले?

तथ्य यह है कि लोगों ने उसे बड़ी नोटों की वजह से काले धन को दूर करने के बड़े कदम के रूप में स्वीकार किया. लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इरादे एकदम साफ हैं; हां, कठिनाइयां हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे. इसका एक नतीजा यह हुआ कि लोग उसकी और कोविड की वजह से डिजिटल लेनदेन ज्यादा करने लगे. और आप कह रहे हैं कि भारत ने अपने लिए नेतृत्व की भूमिका तैयार की, यह सिर्फ नेताओं के मामले में नहीं, (बल्कि) आम लोगों के लिए भी, जिस तरह से उन्होंने इसे अपनाया है. विदेशों से आने वाले कुछ नेता यह देख बेहद प्रभावित होते हैं कि नारियल पानीवाला, ठेलेवाला, यहां तक कि दूर-दराज के गांवों में भी लोग कितनी आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

"रोजगार पर ठोस बात करने के लिए ज्यादा आंकड़ों की जरूरत है. हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं. लोग औपचारिक या संगठित क्षेत्र के आंकड़ों से ही पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींचने लगते हैं"

"अनौपचारिक या असंठित क्षेत्र में आज उछाल दिख रहा है. क्या स्टार्ट-अप रोजगार पैदा नहीं करते? सौर और हरित या स्वच्छ ऊर्जा के नए क्षेत्र उभर रहे हैं. क्या ये महज एक आदमी से चलते हैं?"

• फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नकदी पूरी मात्रा में वापस आ गई है और इसलिए नोटबंदी बेमानी साबित हुई, यह नाकामी है.

उन्हें क्या उम्मीद थी? क्या प्रधानमंत्री के नोटबंदी पर अमल से पहले उनके पास इसका कोई ब्लूप्रिंट था कि नोटबंदी क्या है? क्या प्रधानमंत्री, खासकर सभी उच्च मूल्य वाले नोट की बंदी जैसे बड़े कदम के पहले सभी दलों के साथ बैठ कर पूछते, "देखो, आप लोग मुझे मुहूर्त बताओ, मैं ऐलान करूंगा और फिर हम यह करेंगे?" उस समय उनकी दलील क्या थी? आप काले धन के जखीरे पर हमला करने जा रहे थे, आप उसके प्रवाह के बारे में बात नहीं कर रहे थे. ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 2014 में आते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं, वह काले धन के मामलों के लिए विशेष जांच दल का गठन है. उसके बाद, एक के बाद एक, कानून यह तय करने के लिए लाए गए, ताकि विदेशों में पैसा जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उसके बाद, आप बैंकों में कुछ खास केवाइसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रथाएं लागू करते हैं, बैंकों का संचालन पेशेवर तरीके से करते हैं, देखते हैं कि पैसा कहां जा रहा है, किसका पैसा आ रहा है. राजनैतिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों या (जो लोग) एफएटीएफ (वित्तीय कार्रवाई कार्यबल) कानून का उल्लंघन करने वालों के मद में यही उम्मीद की जाती है कि जब भी एक खाते से बड़ी मात्रा में नकदी स्थानांतरित की जाती है, तो उसे रोक दिया जाए. ये सभी कदम प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए हैं.

• और क्या काले धन की मात्रा कम हो गई है?

कम से कम आप यह सब ट्रैक करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के काबिल हैं. और देखिए कि कैसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) घरों, शौचालयों या फार्महाउसों में छुपा कर रखे रुपए-पैसों के ढेर पकड़ रही है. क्या यह काले धन को खत्म करने की दिशा में कोशिश नहीं है? जब हम ऐसा करते हैं, तो वे कहते हैं, "हे भगवान, आपने इन एजेंसियों को पीछे लगा दिया है." और जब हम ऐसा नहीं करते, तो वे पूछते हैं, "आपने इसके बारे में क्या किया है?"

• इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा नौकरियों और रोजगार का उभर आया है. *इंडिया टुडे* सहित तमाम जनमत सर्वेक्षण बता रहे हैं कि बेरोजगारी आज देश में नंबर एक मुद्दा है. आपका क्या कहना है?

इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नौकरियों या रोजगार के बारे में सही बात करने के लिए आपको अधिक डेटा की जरूरत है. हमारे देश में ये आंकड़े नहीं हैं, और मैं ऐसा बचने के लिए नहीं कह रही हूं. मैं मानती हूं कि औपचारिक क्षेत्र और, समान रूप से या उससे बढ़कर अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए अच्छे और भरोसेमंद दोनों आंकड़ों की जरूरत है. हमें औपचारिक क्षेत्र का कुछ डेटा मिलता है तो हम पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक निष्कर्ष पर पहुंचने लगते हैं, जो सही नहीं है. अनौपचारिक क्षेत्र में आज काफी उछाल दिखा है. अब आइए इन सवालों का जवाब देते हैं. क्या स्टार्ट-अप किसी तन्हाई में काम करते हैं? मुझे लगता है कि आखिरी आंकड़ा 97,000 स्टार्ट-अप का था, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) में पंजीकृत हुए थे. यानी 2016 के बाद से जब (स्टार्ट-अप इंडिया योजना) लॉन्च की गई. क्या आपको लगता है कि ये नौकरियां पैदा नहीं करते? क्या इन कंपनियों को इकलौते आदमी चलाते हैं? दूसरे, नए उभरते क्षेत्रों—अक्षय ऊर्जा, ग्रीन अमोनिया, खासकर सौर ऊर्जा—में हम कितनी बड़ी सौर ऊर्जा कंपनियां देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक व्यक्ति के जरिए चलाई जाती हैं? फिर पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा के जरिए ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है, जिन्होंने बिना किसी गारंटी के ऋण लिया है. मैं न्याय की बात करने वाली कांग्रेस से पूछना चाहती हूं कि जब छोटे लोगों को कर्ज दिया जाता है तो आप उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं और इसकी आलोचना करते हैं कि मोदी सिर्फ अपने दोस्तों को कर्ज दे रहे हैं. तो क्या ये अंबानी और अदाणी हैं? साथ ही, सरकारी रोजगार मेले के तहत नवंबर 2022 से अक्तूबर 2023 तक पिछले 12 महीनों में खाली पड़ी 10 लाख नौकरियां भरी गई हैं.

• स्व-रोजगार की यह कहकर आलोचना की जा रही है कि यह औपचारिक नौकरियों के मुकाबले काफी हद तक प्रच्छन्न रोजगार या अधूरा रोजगार है.

जब लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं और अपना खुद का काम-धंधा कर रहे हैं तो यह अधूरे रोजगार का तर्क काम नहीं कर सकता. जब कृषि पर

निर्भर लोगों की अधिक संख्या के बारे में बात की जाती थी तो अधूरा रोजगार अर्थशास्त्र में एक कारक के रूप में महत्वपूर्ण था. पिछले दशक में कृषि से दूसरे हुनर के पेशों की ओर लोगों का जाना साफ-साफ दिखा है. इसीलिए, जब ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, तो खुद मंत्रालय को बहुत आश्चर्य हुआ, उसमें 200 से अधिक पेशे पंजीकृत थे, जिनमें लोग जुड़े हुए थे, और जिन पर अब राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद काम कर रही है. इसलिए, जब स्व-रोजगार आता है तो अधूरा रोजगार कोई मुद्दा नहीं है. आज की अर्थव्यवस्था लोगों को अपना काम करने की ओर ले जा रही है, यह सब उद्यमशील बनने के बारे में है.

• दूसरा बड़ा चुनावी मुद्दा महंगाई है. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महंगाई नियंत्रण में है लेकिन जब आम आदमी सामान खरीदने निकलता है तो उसे कीमतें ऊंची लगती हैं. क्या महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए और कुछ किया जा सकता है?

महंगाई पर मेरा जवाब यह है कि बाजार में आने वाली और गरीब आदमी की थाली तक पहुंचने वाली वस्तुओं की प्रकृति के कारण कोई भी कोशिश हमेशा नाकाफी होगी. इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे (समस्या से) हाथ धो रही हूं. बिल्कुल नहीं. चाहे मामला प्याज, आलू, खाद्य तेल का हो, या यह तय करना हो कि सब्जियां समय पर पहुंचें, या दालों की पैदावार कम होती है, तो उन्हें समय पर और थोक में आयात करना हो, सब पर ध्यान दिया जाता है. कम से कम, 5-6 साल पहले दिए गए प्रोत्साहन के कारण कई किसान दलहन ज्यादा उगाने लगे. लेकिन उसके बाद, खरीद या कीमत संबंधी मुद्दों के कारण दिलचस्पी घट गई. इसमें राज्य सरकारें भी भूमिका निभाती हैं. अब एक सीमा के बाद आयातित महंगाई भी आपका बोझ बढ़ा देती है. खाद्य तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. क्रूड ऑयल में तो बहुत ही ज्यादा. कोविड के बाद यूरिया की कीमतें 3,000 रुपए प्रति बोरी तक पहुंच गईं. किसान जो बोरी 298 रुपए में खरीदता है, वह पूरी तरह से आयातित होती है. मुझे इसे प्रधानमंत्री के सामने रखना था और उनका कहना एकदम साफ था. उन्होंने कहा कि आपको आयात करना होगा. आप कितनी भी कीमत पर आयात करें, इसकी कमी न हो और इसका बोझ हमारी सरकार उठाएगी. यह स्पष्ट निर्देश था. इसलिए, हम उस इनपुट लागत का प्रबंधन कर रहे हैं और यह भी तय कर रहे हैं कि ईंधन की कीमतें भी एक स्तर पर कायम रखी जाएं, जो एक बड़ा घटक है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण, हमें प्रतिबंधों का डर नहीं था और यूक्रेन युद्ध के बाद भी हम रियायती दर पर रूस से कच्चा तेल आयात कर सकते थे. हमने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा और पीछे नहीं हटे.

"अब कम से कम आप काले धन को ट्रैक कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं. देखिए ना! कैसे ईडी और सीबीआइ घरों, शौचालयों और फार्महाउसों में छुपा कर रखे रुपयों के जखीरे पकड़ रही है."

• रूस से तेल आयात करने के फायदे अब कुछ अर्थों में घट रहे हैं, और पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात हैं. उनका असर क्या होगा?

मुझे लगता है कि तीन युद्धों के साथ-साथ लाल सागर में भी एक बड़ा अड़ंगा है. खुले समुद्र में माल ढुलाई सहित भारी अस्थिरता होने वाली है. भारत समेत सभी देशों को इन अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना है. क्रूड की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल (18 और 19 अप्रैल को) को पार कर गई हैं. कोविड, कई युद्धों, खुले समुद्र में रुकावटों, चीन-अमेरिका समस्या के बावजूद हम अब भी महंगाई पर काबू रखे हुए हैं और इसे सीमा के भीतर रख रहे हैं.

• विशेषज्ञ अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी के अक्षर के-आकार की वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब और गरीब. क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए?

जरा जीएसटी संग्रह पर गौर कीजिए. जीएसटी अभी अपने अनुकूल ग्रेड ढांचे में नहीं है. हमें दरों को तर्कसंगत बनाने पर कुछ काम करना होगा. हमें प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी नजर रखनी होगी. एक समय था जब लोग कहते थे कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर से ज्यादा कमाई करा रही है. यह सच नहीं है. प्रत्यक्ष कराधान अब बहुत अधिक योगदान दे रहा है और ऐसा ही होना चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक दृष्टि यह है कि हर कोई अपने लिए धन पैदा करे. जैसे कि तमिल में एक कहावत है—विरलुक्वेथा

वीक्कम—उंगली का आकार बताएगा कि उसमें सृजन कितनी है. इसी तरह हर कोई अपने आकार के अनुसार कमाएगा. अगर लोग अपने दम पर कमाने में सक्षम हैं, अपने दम पर बचत कर सकते हैं, उनके पास अपनी खुद की कुछ संपत्ति है, तो यह उन्हें अपने पायदान से ऊपर ले जाता है. यह उस प्रकार का लक्षित दृष्टिकोण है जो असमानता को दूर करने में मदद कर सकता है और जिसे बहुआयामी गरीबी को देखने वाले लोगों से भी मान्यता मिली है. लगभग 25 करोड़ लोगों को नितांत गरीबी से बाहर निकाला गया है. गरीबी हटाओ ने 50 साल में ऐसा नहीं किया.

• कांग्रेस तो सहमत नहीं है.

गैर-बराबरी ऐसी बहस है जो कांग्रेस को बहुत पसंद है क्योंकि वे संपदा निर्माण के विरोधी हैं. क्या आपको लगता है कि एक लाख रुपए देने से, जैसा कि कांग्रेस ने वादा किया है, किसी व्यक्ति की चिकित्सा, शिक्षा, मकान या उस मकान में पीने के पानी या रसोई गैस हासिल करने की जरूरतें पूरी होंगी. इससे कांग्रेस की मानसिकता साफ पता चलती है. गरीबी पर पैसा फेंको और गरीबी चली जाएगी. इसीलिए वे हमेशा यह बात कहते हैं, ''मेरे पास जादुई छड़ी है जिससे मैं गरीबी दूर कर सकता हूं.'' आपको अपने बचपन में भी अपनी दादी मां को बताना चाहिए था कि यह जादुई छड़ी है, इंदिराम्मा, आपको इसका इस्तेमाल गरीबी दूर करने के लिए करना चाहिए! यह इस बात का भ्रम पैदा करने का बहुत गैर-जिम्मेदार तरीका है कि समस्या कितनी सीधी-सादी है.

• निजी निवेश के मामले में क्या आप निराश हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने सहित सरकार के बहुतेरे कदमों के बावजूद यह सुस्त ही है? क्या कंपनियों ने जो मुनाफा कमाया, वह अर्थव्यवस्था को लौटाया नहीं?

उन्होंने अर्थव्यवस्था को लौटाया या नहीं, इस पर मुझे लगता है कि यह उन्होंने अपने शेयरधारकों को बेहतर लाभांश देने की शक्ल में किया है. ज्यादातर निजी मिल्कियत वाली कंपनियां नहीं हैं. उनमें छोटे निवेशक धन लगाते हैं, जो बैठकर उस सुनहरे दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें वह धन मिलेगा. इसलिए लाभांश निजी और छोटे निवेशकों के पास भी गया है. दूसरे, उन्होंने टैक्स चुकाया है. उन्होंने बैंकों का भी धन लौटाया. इसीलिए आपके बैंकों की सेहत बहाल हुई. ऐसा नहीं कि उन्होंने इसमें ज्यादा नहीं किया. मगर मैं यह भी चाहूंगी कि हमारा ध्यान उन निवेशों पर जाए जो नए इलाके में हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश कर रहे हैं, पवन और सौर पार्क लगा रहे हैं. फिर, आज के भारत में, चाहे सरकारी बॉन्ड हों या व्यावसायिक उधारियां, लोग भारत में ऐसे बाजार ढूंढते हैं जहां धन मौजूद हो और जहां से कोई भी उधार ले सके. जिसे 'क्राउडिंग इन' (सरकारी खर्च से निजी निवेश का बढ़ना) कहा जाता है, वह वास्तव में अब हो रहा है. निजी धन बाजारों में आ रहा है. कंपनियां इससे उधार ले पा रही हैं. बाजार से सरकारी उधारियों ने उन्हें बाहर नहीं निकाला है.

• तो जो निजी निवेश आ रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं?

मैं चाहूंगी कि यह और ज्यादा आए. नए-नए इलाके हैं. भारत में अक्षय ऊर्जा, एपीआइ, मेडिसिन, विशाल जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार हो रहा है. देखिए कि एपीआइ या एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (सक्रिया दवा घटक) किस तरह भारत में वापस आ रहे हैं. कम से कम 30 साल पहले भारत एपीआइ में अगुआ था. धीरे-धीरे हम चीन की

"बाजार में और गरीब की थाली तक पहुंचने वाली चीजों की प्रकृति ही ऐसी है कि महंगाई पर अंकुश लगाने की कोई भी कोशिश नाकाफी होगी"

प्रीडेटरी प्राइसिंग से हार गए. आज सरकार की नीति ने इसे कंपनियों के लिए आकर्षक बनाया है कि वे आएं और भारत में एपीआइ उत्पादन की इकाइयां स्थापित करें. वे बहुत ज्यादा निवेश करने वाली इकाइयां हैं क्योंकि एपीआइ के उत्पादन में ढेरों ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनसे प्रदूषण हो सकता है. उस प्रदूषण से निबटने के लिए उन्हें प्रदूषण उपचार संयंत्रों वगैरह में निवेश करना पड़ता है. सरकार एपीआइ इकाइयां नहीं लगा रही है, निजी क्षेत्र उनकी स्थापना कर रहा है.

• एयर इंडिया की बिक्री तो देखने को मिली मगर विनिवेश के कुछ दूसरे ऐलान लंबित हैं. इसकी क्या वजह है और अगर आपकी सरकार फिर चुनी गई तो क्या उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा?

कैबिनेट पहले ही उन मामलों की सूची सौंप चुकी है, जिनमें विनिवेश को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट से जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, उसका विनिवेश हमने अगर पूरा नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि हमने उसे छोड़ दिया है. ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का मूल्यांकन कई गुना बढ़ गया है. दरअसल, वैल्युएशन में सबसे कम बढ़ोतरी 150 फीसद की है. कुछ का मूल्यांकन तो 1,000 गुना तक बढ़ गया है. हम उनमें विनिवेश को लेकर गंभीर हैं और ऐसा करने के लिए सही समय ढूंढेंगे.

• विनिवेश खासा उत्तेजक राजनैतिक मुद्दा भी है. क्या आप निजीकरण की सूची वाली कंपनियों की ट्रेड यूनियनों के विरोध से चिंतित हैं?

लगातार वही दलीलें आगे रखना अच्छा नहीं है. एयर इंडिया के मामले में, ट्रेड यूनियनों के साथ अंतिम समय तक बातचीत चलती रही. मुझे बताइए कि निजी क्षेत्र को सौंपने के बाद क्या किसी को नौकरी से हटाया गया? इसके बदले उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है. और जो कोई छोड़ना चाहता था, उसे विदाई में इतना कुछ मिला, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी. इसलिए, जब हम विनिवेश कर रहे हैं, तो हम वहां काम करने वाले लोगों की जरूरतों के प्रति लापरवाह या बेफिक्र नहीं हैं. आज ट्रेड यूनियनें बहुत व्यावहारिक हैं. वे जानती हैं कि उनका क्या काम है. वे चाहती हैं कि कामकाज चलता रहे और कंपनी मुनाफा कमाती रहे. वे चाहती हैं कि ये संस्थान काम करें. वे उन्हें बंद होते नहीं देखना चाहतीं. इसलिए, हमारा विनिवेश उन्हें बंद करने के लिए नहीं है. वे उन्हें विकसित फर्मों के रूप में बिक्री के पक्ष में हैं और उनकी नौकरियां कायम रहेंगी.

"क्या आपको लगता है कि एक लाख रुपए दे देने से, जैसा कांग्रेस वादा कर रही है, किसी की चिकित्सा, शिक्षा, घर, पीने के पानी वगैरह पर खर्च की जरूरतें पूरी हो जाएंगी?"

• एसेट मॉनिटाइजेशन के बारे में क्या चल रहा है? ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां बात आगे नहीं बढ़ी.

सड़कों के मामले में, आरईआइटी (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और आइएनवीआइटी (बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट) जैसे निवेश के दो नए तरीके हैं जो उस क्षेत्र में जान फूंकने में कामयाब साबित हुए हैं. आज, रियल एस्टेट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि मांग बढ़ी है और बकाया भी पूरा हो रहा है. आज रियल एस्टेट क्षेत्र में हम राज्यों के साथ मिलकर काम करते हैं और राज्य सरकारों ने भी पंजीकरण स्टांप शुल्क में आसानी से बदलाव किया है. खासकर महाराष्ट्र ने शानदार काम किया है, जिसकी वजह से सभी बकाया खाता साफ-सुथरा हो गया है.

"प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि हर कोई अपनी धन-संपत्ति खुद पैदा करे. अगर लोग अपनी कमाई, बचत और संपत्ति खड़ी कर पाते हैं तो वही उन्हें ऊपर के पायदान पर पहुंचा देगा"

• क्या दूसरे क्षेत्रों के एसेट मॉनिटाइजेशन के फैसले तेजी से किए जाएंगे?

हमें उस ओर आगे बढ़ना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं. कैबिनेट के फैसले पर मोलतोल या विवाद नहीं किया जा सकता. लेकिन ऐसा करने का सही मौका कब और क्या है, सवाल यह है.

• मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी औसतन 15 फीसद ही बनी हुई है. क्या हमें नौकरियों में इजाफे के लिए इसे कम से कम 20 फीसद तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है?

मैं कोई संख्या तय नहीं कर रही हूं. मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा. यह कौन-सा मॉडल होगा, यह दीगर बात है. कुछ लोग कहेंगे, "चीन की नकल करो." कुछ कहेंगे कि ऐसा मत करो. भारत को अपनी खपत वाली कई चीजों पर आत्मनिर्भर बनना होगा, जिनका उत्पादन करने में देश सक्षम है. हमें उन चीजों को प्राथमिकता देने की जरूरत है जिनका हम फिलहाल आयात कर रहे हैं, लेकिन अंतत: उतना भर ही नहीं होना चाहिए. दूसरी चीजों के मामले में भी विस्तार किया जाना चाहिए. इसमें शक नहीं कि आपके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग आधार होना चाहिए.

• एमएसएमई (लघु, छोटे और मंझोले उद्यम) क्षेत्र विकास का एक प्रमुख इंजन है. उसके लिए और क्या किया जा सकता है?

मैं यह कतई नहीं कहना चाहती कि हमने बहुत कुछ किया है. लेकिन हमने एमएसएमई के लिए वाकई बहुत कुछ किया है, उनकी परिभाषा बदल दी है, उन्हें 59 मिनट के भीतर कर्ज मुहैया कराया है. उन्हें बस पंजीकरण कराना होगा और कहना होगा कि इतनी रकम चाहिए, और 59वें मिनट में मंजूरी मिल जाती है. उसके बाद वे हमेशा के लिए तमाम लाभ उठा सकते हैं. एमएसएमई को सीधे पैसा मुहैया कराने के लिए सिडबी (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक) को अधिक से अधिक धन दिया गया है. मैंने सिडबी के साथ बैठक की और कहा कि इस देश में एमएसएमई के लगभग 300 क्लस्टर हैं, अधिकांश में सिडबी की मौके पर मौजूदगी होनी चाहिए. हमने उससे हर क्लस्टर में शाखाएं खोलने को कहा है और जहां वे दूरी या किसी दूसरी वजह से शाखाएं नहीं खोल सकते हैं, वे वहां का काम ऑनलाइन करते हैं. इसके अलावा, 45 दिन में भुगतान का मामला है. एमएसएमई वाले कहते हैं कि कोई भी उन्हें 45 दिनों के भीतर (बकाया) भुगतान नहीं कर रहा है. यह 2008 या 2006 से एमएसएमई कानून है. कोई भी उसका पालन नहीं कर रहा था. हमने यह तय किया कि भुगतान 45 दिनों के भीतर किया जाए ताकि उनका पैसा न फंसे. एमएसएमई के साथ हम बैठकें करके उनकी बात सुन रहे हैं और उनके सुझावों को आगे बढ़ा रहे हैं. हम ऐसा करना जारी रखेंगे.

• अब मोदी 3.0 की बात करते हैं.अगर आपकी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है तो किन बातों की उम्मीद की जा सकती है?

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर जारी रहेगा. जो इलाके अभी भी दूर-दराज हैं, उन तक पहुंच काफी हद तक आसान हो जाएगी. डिजिटल बुनियादी ढांचे को निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा. शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति सरोकार उसी तरह बना रहेगा, जो पिछले कुछ वर्षों से कायम है. इसी तरह कौशल विकास. हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जो विश्वविद्यालय का कोर्स पूरा करते ही नियुक्ति के लायक तैयार हो जाएं. आज उद्योगों की शिकायत है कि कॉलेजों से निकलने वाले स्नातकों को नौकरी में प्रशिक्षित करने में लगभग साल भर लग जाता है. यह खर्च कोई भी उद्योग नहीं करना चाहता. हमें चाहिए कि हमारे स्नातक नौकरियों के लिए तैयार होकर

आएं और उनमें से कई जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, उनके पास उस देश की भाषा के साथ-साथ आवश्यक हुनर होना चाहिए. इसलिए हम इन बातों पर बहुत ज्यादा जोर देंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी ध्यान देना होगा, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने में कुशल बनाना है. फिर, उभरते हुए क्षेत्र हैं—रेयर अर्थ मटीरियल, ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल वगैरह में निवेश आ रहे हैं. यह तय करना है कि भारत सेवा क्षेत्र में अग्रणी बना रहे. इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो.

• वे कौन-से प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें आगे सुधार या बड़े बदलाव की संभावना है?

टेक्नोलॉजी आधारित बदलाव सर्वोच्च प्राथमिकता होने जा रहे हैं. बेशक, फिनटेक के क्षेत्र में स्टार्ट-अप, ग्रामीण आजीविका की समस्याओं के समाधान के लिए टेक्नोलॉजी, पर्यावरण के लिए मिशन जीवन-शैली वगैरह पर भी जोर होगा. आपको ऐसे उपकरण, टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो जिंदगी को आसान और टिकाऊ बना सके. हम जेनरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने की ओर भी देख रहे हैं. सुधारों को अब क्रमबद्ध तरीके से नहीं किया जा सकता, उन्हें निरंतर और व्यवस्थागत होना होगा. कुछ समय से लंबित व्यवस्थागत सुधारों को शुरू करना होगा और पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर तक ले जाना होगा. मसलन, किसी पंचायत में कोई संयंत्र लगाने की मंजूरी. आपको लगता है कि पंचायतें इसे आसान बना रही हैं? आपको वह करने की जरूरत है, ताकि यह पारदर्शी तरीके और सरलता से हो.

• क्या जीएसटी में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जिनमें इसे तर्कसंगत बनाना भी शामिल है?

यह कोई उपेक्षा वाला क्षेत्र बिल्कुल नहीं है. एक मंत्री-समूह है और उसकी रिपोर्ट को चुनाव के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में रखा जाएगा और अगले स्तर तक ले जाना होगा.

• जीएसटी और उसके बंटवारे को लेकर केंद्र-राज्य संबंधों में कई ऊंच-नीच बनी हुई है. इसे सुलझाने का आपका प्रस्ताव क्या है?

मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से राजनैतिक खेल है जो विपक्षी दल खेल रहे हैं. मैं किसी को भी चुनौती देती हूं, वह मुझे बताए कि क्या किसी राज्य को उसका बकाया देने से इनकार किया गया है. वित्त मंत्रालय की ओर से मैं आपको बता सकती हूं कि अगर कुछ हुआ है तो यह कि वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक भुगतान समय पर किया गया है, कभी-कभी तो समय से काफी पहले. जनवरी में जो भुगतान करना था, मैंने दिसंबर में कर दिया, दिसंबर में जो भुगतान करना था, नवंबर में ही कर दिया गया है. लेकिन फिर भी आपको अपने कामकाज या आपकी आबादी या आपकी कार्यकुशलता के स्तर की वजह से कोई और मुद्दा उठाना है, तो आपको अगले वित्त आयोग से बात करनी चाहिए. उसका पहले ही गठन हो चुका है.

• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चुनावी रैलियों में यही कहा है. उनके राज्य से केंद्रीय खजाने में हर एक रुपए के योगदान के बदले करों के हिस्से के रूप में सिर्फ 29 पैसे वापस आते हैं.

यह कैसी दलील है भला, यह सनसनीखेज बनाने और लोगों के बीच दरार पैदा करने जैसी है. सोचिए, अगर तमिलनाडु के भीतर ही राज्य के खजाने में अच्छा-खासा योगदान करने वाला कोयंबत्तूर और उसके आसपास के इलाके के लोग कहने लगें, ''नहीं, हमारा सब हमें वापस दे दो,'' तो क्या होगा. जिस जिले से मुख्यमंत्री आते हैं यानी तंजावुर को पैसा नहीं मिलेगा, या श्रीपेरंबदुर को. क्या वे देश में यही सब चलाना चाहते हैं? क्या तमिलनाडु में बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं बनाए जा रहे? क्या वंदे भारत ट्रेनें नहीं जा रही हैं? इन सब मदों में कौन खर्च करता है? तमिलनाडु में निर्मित उत्पादों की खरीदारी पूरे देश में होती है. तो टैक्स के रूप में जो पैसा आपको मिलता है, वह कोई आपका अपना पैसा नहीं है, उसमें सभी देशवासियों का योगदान है. यह किस तरह का कैसा ऊल-जुलूल तर्क है?

• सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, दक्षिणी राज्यों के सभी वित्त मंत्रियों ने यह सवाल उठाया है.

''मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ना होगा. यह दीगर बात है कि उसका मॉडल क्या हो. कुछ कहेंगे, ''चीन की नकल'' करो, कुछ दूसरे कहेंगे कि मत करो. जो भी हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा''

इसीलिए मैं कह रही हूं कि यह पूरा राजनैतिक मामला है. अब कर्नाटक इसे उठा रहा है क्योंकि मुफ्त सुविधाओं के नाम पर न निभ सकने वाले वादे किए गए हैं और अब वहां के उप-मुख्यमंत्री कहते हैं, ''मेरे पास विकास की मद में देने के लिए और पैसा नहीं है. अब बस. माफ करें, मैंने सब कुछ दे दिया है.'' और फिर कहते हैं, ''मोदी, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं.'' बताओ मोदी ने कौन-सा पैसा नहीं दिया? यह पूरी तरह से विकृत राजनैतिक, अवसरवादी दलील है. अगर कारगर कामकाज के संदर्भ में कोई मुद्दा है, तो वित्त आयोग से बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार को दोष नहीं देना चाहिए.

• आप आइबीसी (दिवाला और दिवालियापन संहिता) प्रक्रिया में देरी से कैसे निबटेंगी, जो अभी भी दिवालियापन के मुद्दों के समाधान का मुफीद तंत्र है?

मेरा मानना है कि आइबीसी में कोई गलती नहीं है. इसे उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया है ताकि प्रक्रिया में तेजी आए. यह कंपनियों को खत्म करने के बजाए चालू बनाए रखने के लिए है. लेकिन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी)

"सुधार अब आइटमाइज्ड ढंग से नहीं हो सकते. निरंतर और व्यवस्थित ढंग से सुधार करना होगा. ऐसे सुधार जो पंचायत और स्थानीय निकायों के स्तर पर पहुंचें"

की रिक्तियों को भरने, ज्यादा उम्दा समाधान देने वाले प्रोफेशनल्स की उपलब्धता निश्चित रूप से समस्याएं हैं जो कुछ स्किल सेट्स के साथ आते हैं और उन्हें प्रशिक्षित भी करना पड़ता है. फिर कई बार ऐसा भी आ जाता है जब आप झटका खा जाएं, जब लोग सिस्टम के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं कि पुराना, बदनाम प्रमोटर खुद पिछले दरवाजे से अंदर आना चाहता है. इसलिए, हम फायरवॉल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ऐसा न हो. इस तरह की शुरुआती दिक्कतें हैं जिनसे आइबीसी में रुकावट आई है, लेकिन आइबीसी में कोई दिक्कत नहीं है. यह ऐसी प्रणाली है जिसे और अधिक बेहतर बनाना होगा ताकि यह समय की कसौटी पर खरा उतरे.

• क्या मोदी 3.0 में सरकारी बैंकों का अधिक एकीकरण होगा और नए निजी बैंकों को लाइसेंस दिए जाएंगे?

इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में बहुत ज्यादा बैंकों की जरूरत है. बहुत सारे बड़े बैंकों की. साथ ही साथ, बहुत सारे छोटे बैंक भी हैं, जिनकी आपको जमीनी स्तर पर जरूरत है, जो स्थानीय क्षेत्रों में हों. छोटे वित्तपोषण संस्थान अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें उनकी और ज्यादा जरूरत भी है. इसलिए बैंकिंग प्रणाली को और अधिक चुस्त होना होगा. हमें खुशी है कि हमने भारतीय बैंकों को अच्छी स्थिति में ला दिया है, लेकिन पूरे क्षेत्र को काफी चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है और हमें बहुत अधिक बैंकों की जरूरत है.

• कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ कमजोर रुपए का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

इसमें संदेह नहीं कि यह बड़ी चुनौती होगी. लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया और उसके उतार-चढ़ाव की कहानी दूसरी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की स्थिति जैसी नहीं है. यह दूसरी मुद्राओं के मुकाबले स्थिर रहा है, उतार-चढ़ाव न्यूनतम रहा है. अगर डॉलर के मुकाबले इसमें उतार-चढ़ाव हो रहा है, तो वजह डॉलर की ताकत है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संकेत हैं कि वह और मजबूत होगी. इसलिए, हमें यह देखना होगा कि हम उस चुनौती का सामना कैसे कर सकते हैं, चाहे वह कच्चे तेल की कीमतें हों या खासकर डॉलर के मुकाबले विनिमय दर में उतार-चढ़ाव हो. रिजर्व बैंक भी लगातार नजर बनाए हुए है.

• अर्थव्यवस्था को संभालने के यूपीए के तरीके पर आपने जो श्वेत-पत्र निकाला था, उसमें आपने 2011 और 2013 के बीच रुपए को 36 फीसद तक गिरने देने के लिए उसकी आलोचना की थी. लेकिन एनडीए के तहत भी रुपया काफी गिर रहा है.

क्या नाजुक पांच अर्थव्यवस्थाओं के दौरान डॉलर के कमजोर होने और आज की मजबूत अर्थव्यवस्था के बीच कोई फर्क नहीं है? आज वह तेजी से बढ़ रही है, जहां जीडीपी का विस्तार हो रहा है और आप दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कर रहे हैं.

• सेंसेक्स 75,000 अंक को पार कर गया. यह क्या दर्शाता है?

भारतीय अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास की भावना. स्थिर नीतियों वाली, स्थिर बहुमत वाली सरकार में विश्वास. कराधान में विश्वास, जो ऊपर-नीचे नहीं होता. कोई फ्लिप-फ्लॉप नहीं. शेयर बाजार यही दिखा रहा है.

•प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रहे हैं. मोटे अनुमान कहते हैं कि आपको लगभग 12 फीसद चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ना होगा. क्या आपके पास इसका कोई खाका है कि लक्ष्य पूरा हो जाए?

ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं. हमें अपनी नीति में सुसंगत रहना होगा. हमें समाज के हर वर्ग का मददगार बनना होगा. हमें भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना लोग दूसरों का धन हड़प लेंगे और अर्थव्यवस्था को बढ़ने नहीं देंगे. देश के हर क्षेत्र में निर्यात की संभावनाएं हैं. कृषि में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं. मैन्युफैक्चरिंग को अपने अच्छे, गौरवशाली दिनों में वापस आना होगा. इसी तरह, सेवा क्षेत्र को दी जा रही मदद को व्यापक करना होगा. हमारे रक्षा निर्यात ने दिखाया है कि हमारी नीतियों का संतुलन सही रहे तो वे अच्छा कर सकते हैं. हमें यह सब करना है और करते रहना है. लेकिन कुछ हल्के-फुल्के अंदाज में कहें तो, हमें कम से कम विपक्षी दलों में ऐसे लोगों की जरूरत है, जो भारत में विश्वास करते हों. अगर उन्हें हमारे अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें भारत के विचार का प्रचार करने की जरूरत नहीं है. कृपया भारत के अपने लोगों की विश्वसनीय उपलब्धियों को कमजोर न करें.■

धमक दिखाने उतरा मुलायम का परिवार

लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमा रहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समेत मुलायम सिंह यादव परिवार के पांच सदस्य. यादव बेल्ट की कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद और आजमगढ़ सीट को फिर से जीतने की चुनौती

आशीष मिश्र

मनीष अग्निहोत्री

लौटकर फिर कन्नौज
सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे

इटावा जिले से मैनपुरी को जाने वाले हाइवे पर 23 किलोमीटर चलने के बाद दाहिनी ओर एक चौड़ी सड़क सैफई गांव की ओर जाती है. यह समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का पैतृक गांव है. गांव के पूर्वी पर उनकी कोठी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में सपा की राजनैतिक गतिविधियों का केंद्र है. यहीं रहकर मुलायम परिवार की बड़ी बहू और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं. इस कोठी की सरगर्मियां 24 अप्रैल की सुबह और भी ज्यादा बढ़ गईं जब अखिलेश यहां कुछ सपा नेताओं और अपने चाचा व पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के साथ चुनावी मंत्रणा कर रहे थे. यह मंत्रणा कन्नौज लोकसभा सीट से मुलायम के पौत्र और अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार घोषित होने के एक दिन बाद हो रही थी. वैसे, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा का गढ़ रहे कन्नौज में अखिलेश की सक्रियता को देखते हुए उनके इस सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लग रही थीं. लेकिन 22 अप्रैल को तेज प्रताप के नाम की घोषणा होते ही कन्नौज के सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए.

अगले दिन कन्नौज के सपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ के सपा कार्यालय में अखिलेश से मिला. सपा नेताओं का तर्क था कि अगर अखिलेश कन्नौज से नहीं लड़ते हैं तो इस बार भी यहां का नतीजा पिछली बार जैसा ही होगा जब डिंपल को हार का सामना करना पड़ा था. कार्यकर्ताओं की राय पर अखिलेश ने सैफई में रामगोपाल, डिंपल और तेज प्रताप के साथ मिलकर मशविरा किया. इसके बाद ही अखिलेश ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया. इस फैसले से तेज प्रताप को दूसरी बार निराशा हाथ लगी. इससे पहले उन्हें रामपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाने के निर्णय से भी पार्टी को पलटना पड़ा था. इसके बावजूद मुलायम परिवार एकजुट दिखाई दिया.

तेज प्रताप की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व और कन्नौज की जनता का है, उनका फैसला सपा के हित में बिल्कुल सही है.'' 2009 का लोकसभा चुनाव जीतने के 15 साल बाद 25 अप्रैल को एक बार फिर कन्नौज से पर्चा भरने निकले अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल, चाचा रामगोपाल के साथ सपा कार्यकर्ताओं के हुजूम ने ने मुलायम सिंह यादव परिवार के एकजुट होने का संदेश दिया. सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने कहा, ''कन्नौज क्रांति' होकर रहेगी.''

सपा के संस्थापक मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद हो रहे इस लोकसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में इस बार पूरा सैफई परिवार एकजुट है. यह एकजुटता 16 अप्रैल को मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव के नामांकन के दौरान भी दिखी थी. मुलायम सिंह 1996 में यहां से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे. उसके बाद लगातार सपा के प्रत्याशी यहां से अजेय रहे हैं. मुलायम सिंह की 10 अक्तूबर, 2022 को मृत्यु के बाद हुए लोकसभा उपचुनाव में डिंपल ने पौने तीन लाख वोटों से जीत हासिल कर अपने ससुर की विरासत संभाली. नामांकन के लिए जाने से पहले डिंपल ने सैफई मेला ग्राउंड की बगल में मौजूद मुलायम सिंह की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की. 30 जनवरी को सपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नाम आने के अगले ही दिन से डिंपल ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था. रोज सुबह सात बजे से सैफई की कोठी में सपा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता है. डिंपल एक-एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मिलती हैं. चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेती हैं. सुबह ठीक 10 बजे उनका काफिला चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़ता है. डिंपल अपनी हर सभा में मंच पर मौजूद मुलायम सिंह के करीबी बुजुर्ग नेताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के बाद ही चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाती हैं. डिंपल ''नेताजी'' के सपनों को पूरा करने की बात कहकर वोट मांगती हैं.

पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को मिली हार का बदला लेने के लिए मुलायम परिवार के तीन और सदस्य भी मैदान में हैं. मैनपुरी से सटी फिरोजाबाद लोकसभा सीट से रामगोपाल के पुत्र अक्षय यादव लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में मुलायम परिवार के अंदरूनी विवाद की वजह से अक्षय हार गए थे. तब शिवपाल अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के झंडे तले फिरोजाबाद सीट से चुनाव में उतरे और 90 हजार से अधिक वोट लेकर शिवपाल

अखिलेश यादव, 50 वर्ष

मुलायम सिंह यादव के पुत्र, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार

पिछला नतीजा: पिछले चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को 12 हजार से अधिक मतों से हराया था

वर्तमान चुनौती: 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव को भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक और बसपा उम्मीदवार इमरान बिन जफर से चुनौती मिल रही है

विधानसभा चुनाव नतीजा: 2022 के विधानसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट के तहत आने वाली छिबरामऊ, तिर्वा, रसूलाबाद (सुरक्षित) और कन्नौज (सुरक्षित) विधानसभा सीट भाजपा, सपा ने केवल एक विधुना विधानसभा सीट जीती थी

कन्नौज लोकसभा सीट
कुल मतदाता: 18.08 लाख

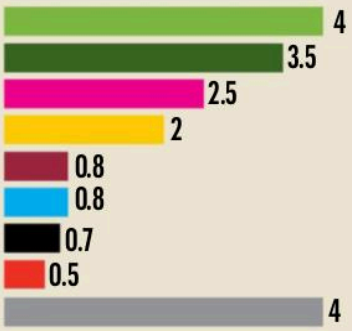

संख्या लाख में

अक्षय यादव, 37 वर्ष

मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल यादव के पुत्र, फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार

फिरोजाबाद लोकसभा सीट
कुल मतदाता: 18.87 लाख

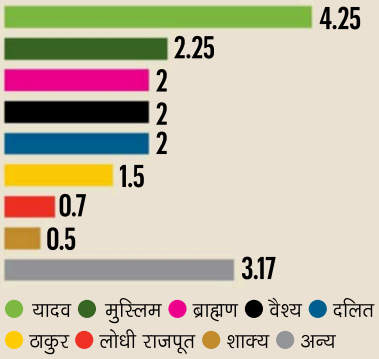

पिछला नतीजा: पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार डॉ. चंद्रसेन जादौन ने सपा उम्मीदवार अक्षय को 28 हजार से अधिक मतों से हराया था

वर्तमान चुनौती: 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार अक्षय यादव को विश्वदीप सिंह और बसपा उम्मीदवार चौधरी बशीर से चुनौती मिल रही है

विधानसभा चुनाव नतीजा: 2022 के विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट के तहत आने वाली टूंडला (सुरक्षित) और फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर भाजपा, जसराना, शिकोहाबाद और सिरसागंज विधानसभा सीट सपा ने जीती थी

संख्या लाख में

डिंपल यादव, 46 वर्ष

मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी. मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार और वर्तमान सांसद

मैनपुरी लोकसभा सीट
कुल मतदाता: 17.87 लाख

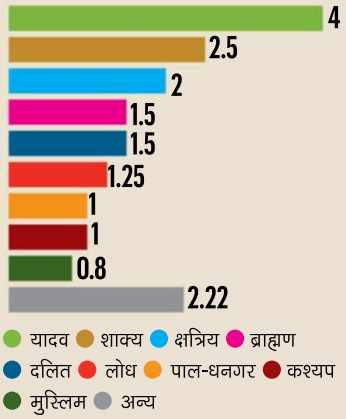

ने अक्षय को भाजपा उम्मीदवार से 28 हजार मतों से चुनाव हराने में बड़ी भूमिका अदा की. सैफई परिवार के करीबी और शिकोहाबाद निवासी डॉ. एस.पी. राणा बताते हैं, ''2024 के लोकसभा चुनाव में हालात बदल चुके हैं. पूरा मुलायम परिवार एकजुट है. इसका असर केवल फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि मैनपुरी, बदायूं, आजमगढ़, कन्नौज समेत उन सभी लोकसभा सीटों पर दिखेगा जहां पर यादव मतदाता बहुतायत में हैं.''

मुलायम के छोटे भाई शिवपाल अगर 2019 के चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर सपा की हार के पीछे के मुख्य किरदार थे तो इस बार उनके कंधों पर बदायूं लोकसभा सीट पर साइकिल दौड़ाने की चुनौती है. सपा ने अपनी पहली सूची में ही दो बार सांसद रहे और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव को बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था. लेकिन कुछ स्थानीय सपा नेताओं और पूर्व सांसद सलीम शेरवानी के विरोध में आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल यादव को बदायूं सीट से उतार दिया. धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया गया जहां वर्ष 2022 को हुए लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ से हार का सामना करना पड़ा था.

बदायूं से उम्मीदवार घोषित होने के बाद शिवपाल यादव इस सीट पर खुद को बहुत असहज महसूस कर रहे थे. उम्मीदवार घोषित होने के 18 दिन तक शिवपाल बदायूं नहीं आए. 19वें दिन जब वह आए तो बेटे आदित्य यादव साथ में थे. शिवपाल ने अखिलेश से अपने बेटे आदित्य यादव को बदायूं से उम्मीदवार बनाने का आग्रह किया था. उनके एक करीबी नेता बताते हैं, ''शिवपाल के लोकसभा चुनाव लड़ने से वे मैनपुरी में ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे जिसका असर चुनाव में पड़ सकता था. पिछले लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव केवल 94 हजार मतों से ही जीत पाए थे जिसमें अकेले जसवंतनगर विधानसभा से उन्हें 62 हजार वोटों की लीड मिली थी जहां से शिवपाल विधायक हैं.'' अंतत: सपा ने एक बार टिकट बदलकर आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा था कि बदायूं लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, अब तक दो भाग चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल बताते हैं, ''जैसे नेताजी (मुलायम सिंह यादव) ने अखिलेश यादव को जब टिकट दिया तब वे केवल 26 साल के थे. धर्मेंद्र यादव को जब मैनपुरी से चुनाव लड़ाया गया तब वे 25 साल के थे. अब आदित्य भी युवा हैं. युवाओं की मांग और पार्टी की रणनीति के तहत आदित्य को उम्मीदवार बनाया गया है.'' बदायूं लोकसभा सीट पर छह बार जीत हासिल करने वाली सपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने की चुनौती आदित्य यादव के सामने है.

'नेताजी' की गैरमौजूदगी में पहली बार हो रहे लोकसभा चुनाव में एकजुट मुलायम परिवार को सपा के दूसरे नाराज नेताओं का मनाने की कठिन जिम्मेदारी है. बेटे आदित्य की राह आसान करने के लिए शिवपाल बदायूं में लगातार कैंप करके चुनावी प्रबंधन की कमान संभाले हुए हैं. राज्यसभा चुनाव में सपा की ओर से मुस्लिम उम्मीदवार न उतारे जाने के बाद से बागी तेवर दिखाने वाले पांच बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी को

पिछला नतीजा: पिछले चुनाव में सपा उम्मीदवार मुलायम सिंह यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को करीब 94 हजार वोटों से हराया था. मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने भाजपा उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य को 2.88 लाख मतों से हराया था

वर्तमान चुनौती: 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को भाजपा उम्मीदवार और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह और बसपा के शिवप्रसाद यादव से चुनौती मिल रही है

विधानसभा चुनाव नतीजा: 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आने वाली मैनपुरी, भोगांव सीट भाजपा और किश्नी (सुरक्षित), करहल, जसवंतनगर सीट सपा ने जीती थी

संख्या लाख में

मनाने में शिवपाल ने कामयाबी हासिल की है. शेरवानी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 51 हजार वोट लेकर सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को भाजपा प्रत्याशी से 18 हजार मतों से हारने में बड़ी भूमिका निभाई थी. शेरवानी 14 अप्रैल को बदायूं में आदित्य के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर विशेष तौर पर मौजूद थे. शेरवानी बताते हैं, ''मैं समाजवादी पार्टी के लिए बदायूं नहीं गया बल्कि शिवपाल और उनके बेटे के लिए गया था.''

इसी तरह मुस्लिम मतों में बंटवारे के चलते सपा को उपचुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट से हाथ धोना पड़ा था. अखिलेश ने आजमगढ़ सीट को छोड़ दिया था जिस पर 2022 के लोकसभा उपचुनाव में सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को महज आठ हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव में बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2.6 लाख से अधिक वोट लेकर सपा से मुस्लिम मतों का बंटवारा कर लिया था. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने गुड्डू जमाली और आजमगढ़ के वरिष्ठ सपा नेता बलराम सिंह यादव को विधान परिषद सदस्य निर्वाचित कराकर यादव-मुस्लिम मतदाताओं का जिताऊ गठजोड़ पुख्ता करने की कोशिश की है.

वहीं रामगोपाल यादव ने फिरोजाबाद में सपा के पूर्व नगर विधायक अजीम भाई समेत पार्टी के सभी रूठे समर्थकों को मनाने में कामयाबी हासिल की है. पहले से नाराज चल रहे जसराना के पूर्व विधायक रामवीर यादव और उनके बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष

आदित्य यादव, 35 वर्ष

मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव के पुत्र, बदायूं लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार

पिछला नतीजा: पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार संघमित्रा मौर्या ने सपा उम्मीवाद धर्मेंद्र यादव को 18 हजार से अधिक मतों से हराया था

वर्तमान चुनौती: 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार आदित्य यादव को भाजपा उम्मीदवार दुर्विजय सिंह शाक्य और बसपा उम्मीदवार मुस्लिम खां से चुनौती मिल रही है

विधानसभा चुनाव नतीजा: 2022 के विधानसभा चुनाव में बदायूं लोकसभा सीट के तहत आने वाली गुन्नौर, बिसौली (सुरक्षित) और सहसावान विधानसभा सीट सपा, बिल्सी और बदायूं भाजपा ने जीती थी

बदायूं लोकसभा सीट
कुल मतदाता: 19.30 लाख

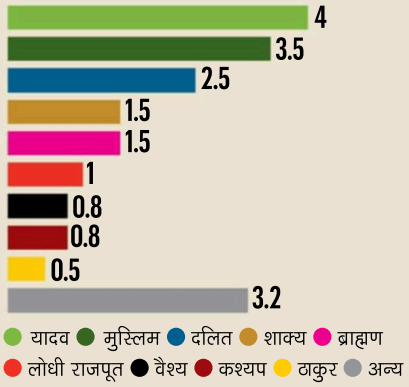

संख्या लाख में

धर्मेंद्र यादव, 45 वर्ष,
मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभय राम यादव के बेटे, आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार

आजमगढ़ लोकसभा सीट
कुल मतदाता: 18.38 लाख

पिछला नतीजा: पिछले लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव ने भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को करीब 2.6 लाख मतों से हराया था. अखिलेश द्वारा रिक्त की गई आजमगढ़ सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीवार निरहुआ ने सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को करीब आठ हजार वोटों से हराया था

वर्तमान चुनौती: 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को भाजपा उम्मीवार और वर्तमान सांसद निरहुआ और बसपा उम्मीदवार भीम राजभर से चुनौती मिल रही है

विधानसभा चुनाव नतीजा: 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी पांच गोपालपुर, सिगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर (सुरक्षित) लोकसभा सीट सपा ने जीती थी

अमोल यादव ने 14 अप्रैल को अक्षय यादव के पक्ष में सम्मेलन करके यादव मतदाताओं से सपा के पक्ष में एकजुट होने की अपील की थी.

मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, कन्नौज, आजमगढ़ लोकसभा सीटें उन सीटों में शामिल हैं जहां यादव मतदाताओं की 20 फीसद या इससे अधिक आबादी है. इन्हें सपा का गढ़ माना जाता है. सपा पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से केवल मैनपुरी और आजमगढ़ ही जीत पाई थी. सपा के गढ़ को भाजपा के मुख्यमंत्रियों की चुनौती भी मिल रही है. कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने की अटकलबाजी शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी. 3 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में एक बड़ी रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने दलितों को रिझाने के लिए सपा शासनकाल के दौरान कन्नौज में बने मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के नाम पर करने की घोषणा भी की. योगी ने कन्नौज में 352 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया. इस दौरान योगी ने सपा शासनकाल में बनाए गए 'इत्र पार्क' और 'विधि विज्ञान प्रयोगशाला' का भी लोकार्पण किया. करीब पांच साल से बनकर तैयार इन प्रोजेक्ट का लोकसभा चुनाव से पहले लोकार्पण करना योगी आदित्यनाथ की सपा को कोई चुनावी मुद्दा न देने की ही रणनीति है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 15 अप्रैल को मैनपुरी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जयवीर सिंह के नामांकन में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर यादव मतों में पैठ बनाने की कोशिश की. इससे पहले मोहन यादव आजमगढ़ में भी रैली कर चुके हैं. भाजपा संगठन यादव बेल्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली के साथ योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव की कम से कम पांच जनसभाओं की योजना तैयार कर रहा है.

साइकिल के गढ़ में जमीनी नेताओं को साथ लाकर ताकत बढ़ाने की रणनीति के तहत भाजपा ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से यादव परिवार के गढ़ को निशाने पर रखा है. मुलायम सिंह के समधी और पूर्व विधायक हरिओम यादव को शामिल करके भाजपा ने सैफई परिवार को सीधे चुनौती दी थी. लोकसभा चुनाव के दौरान मैनपुरी से भाजपा उम्मीदवार जयवीर सिंह ने 14 अप्रैल को मुलायम सिंह यादव के राजनैतिक गुरु कहे जाने वाले चौधरी नत्थू सिंह यादव के पौत्र धीरज यादव को भाजपा में शामिल कर सपा के कोर वोट बैंक को खींचने की कोशिश की है. महिला पीजी कॉलेज, इटावा में प्रोफेसर पद्मा त्रिपाठी बताती हैं, ''इस बार के लोकसभा चुनाव में सपा ने जितने भी यादव उम्मीदवार उतारे हैं, सभी मुलायम सिंह यादव परिवार के ही सदस्य हैं जबकि 2019 के चुनाव में कुल 10 यादव उम्मीदवार सपा से चुनाव लड़े थे. अखिलेश यादव के सामने अपने कोर मतदाताओं को बांधे रखने की चुनौती भी होगी.''

हालांकि सपा नेताओं का तर्क है कि मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य अपनी परंपरागत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं. इसके अतिरिक्त यादव जाति के नेताओं को कम उम्मीवार बनाना सपा की रणनीति का हिस्सा है. यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे. ■

"हमसे पहले परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी (योगी आदित्यनाथ) और उनकी पार्टी भाजपा ने"

अखिलेश यादव,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा

INDIA TODAY

INDIA TODAY GROUP

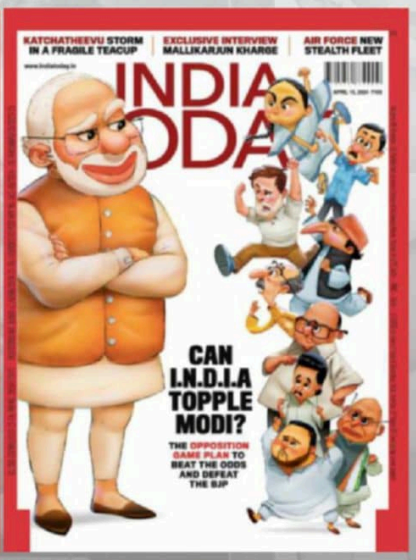

IN DEPTH KNOWLEDGE FROM THE MOST CREDIBLE SOURCE

Subscribe and get upto 72% discount

YES! I WISH TO SUBSCRIBE TO INDIA TODAY

Please tick your subscription choice and send the form to: We Care, Living Media India Limited, C-9, Sector 10, Noida-201301 (India)

TERM-1 YEAR | NO. OF ISSUES-52				
PLAN	**COVER PRICE**	**OFFER PRICE**	**SAVINGS**	**SELECT**
DIGITAL + PRINT	₹10400	₹2999	72%	☐
DIGITAL ONLY	₹5200	₹999	81%	☐

Please fill the form in CAPITAL LETTERS

I am enclosing Cheque/DD No.:_____ dated:_____

drawn on (specify bank):_____ favouring Living Media India Limited for

₹ _____

Name:_____ Address: _____

_____ City:_____ State:_____ Pin:_____

Mobile:_____ Email:_____

SCAN HERE TO SUBSCRIBE

FOR MORE DETAILS ON THE OFFER, YOU MAY CONTACT THROUGH BELOW OPTIONS

PHONE AND WHATSAPP +91 8597778778

E-MAIL wecare@intoday.com

LOG ON TO www.indiatoday.in/subscribe

Living Media India Ltd. reserves the right to terminate or extend this offer or any part thereof at any time. For other terms and conditions, please visit www.indiatoday.in

IRS 2019 Q4 (TR)

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

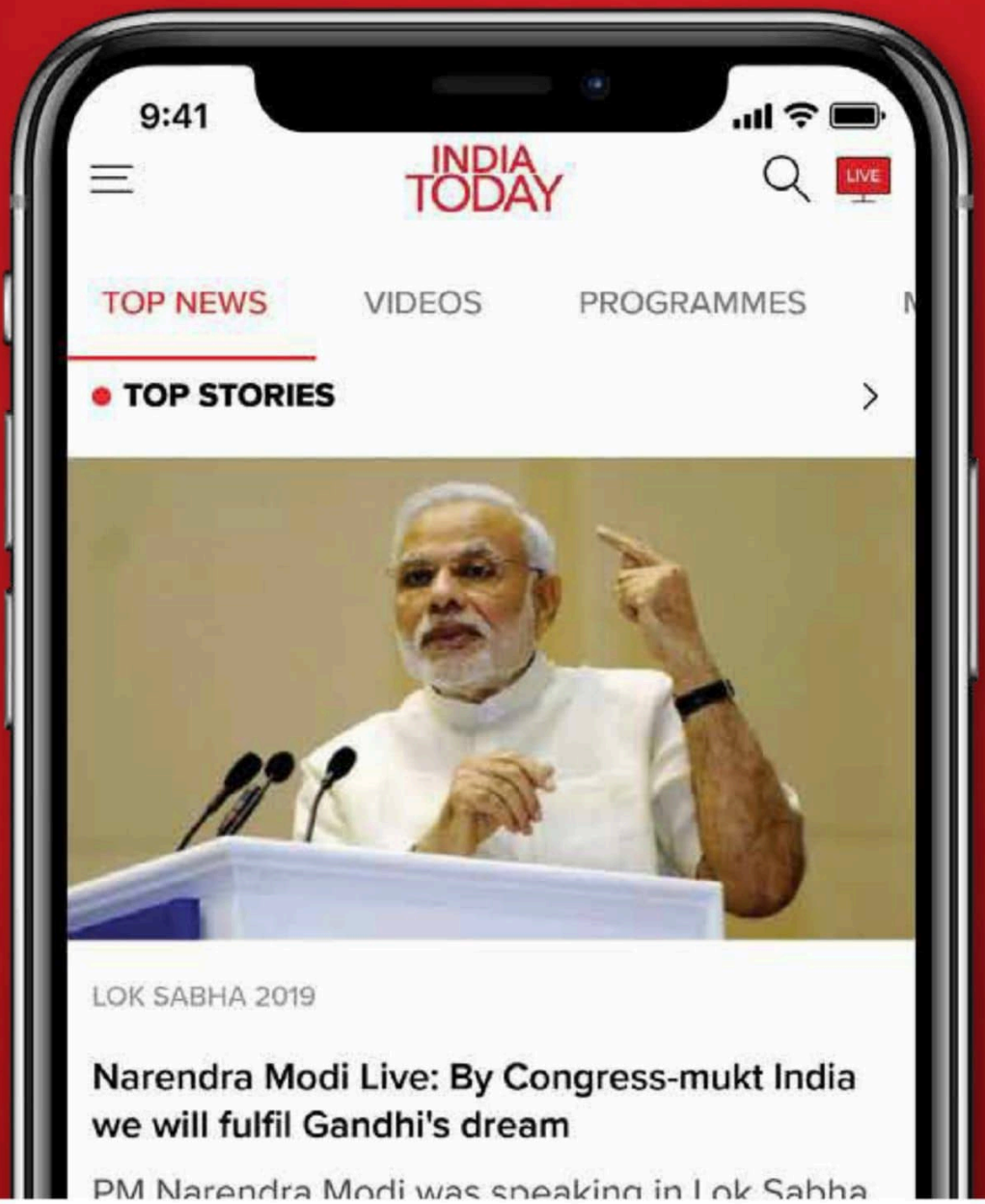

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रचार की धुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर में एक जनसभा में

भाजपा के ट्रंप कार्ड को चुनौती देती कांग्रेस

टीम मोदी विधानसभा चुनाव में हासिल जीत की लय के भरोसे है लेकिन चतुराई से प्रत्याशियों का चयन शायद कांग्रेस का सूपड़ा साफ न होने दे

राहुल नरोन्हा

पांच साल पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरे उत्साह से मैदान में उतरी थी, क्योंकि उससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की थी और 90 में से 68 सीटें कब्जा कर राज्य में करीब डेढ़ दशक बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बेदखल कर दिया था. उसे लोकसभा चुनाव में भी जीत अपनी मुट्ठी में लग रही थी. लेकिन नतीजे एकदम उलट रहे, लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से नौ पर जीत दर्ज कराई. अब, जबकि राज्य में 2024 के आम चुनावों के लिए तीन चरणों में मतदान होना है, अधिकांश लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भाजपा को पटखनी देकर कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव नतीजों के उलट शानदार प्रदर्शन कर पाएगी. विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 54 सीटें हासिल की थीं. राजनैतिक विश्लेषकों की मानें तो कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी क्योंकि भाजपा के पास अभी भी उसका एक सबसे बड़ा हथियार बरकरार है जो कि 2019 में भी कांग्रेस को पछाड़ने में मददगार साबित हुआ था, और भाजपा के तरकश का यह तीर है—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में विशाल जनसमर्थन. फिर भी, कुछ लोगों का मानना है कि पीएम जैसे ट्रंप कार्ड के बावजूद कांग्रेस छत्तीसगढ़ में चुनावी दौड़ से बाहर नहीं है.

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा इंतजामों की खास जरूरत को ध्यान में रखकर ही राज्य

में तीन चरणों में मतदान कराया जा रहा है. माओवादियों के गढ़ रहे बस्तर में 19 अप्रैल को वोट पड़े जबकि महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान मतदान होना है. मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ की शेष सात सीटों पर 7 मई को मतदान होना है और वोटों की गिनती 4 जून को होगी. कांग्रेस ने चुनावी बिसात पर मोहरे काफी सोच-समझकर लगाए हैं. पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो खासा सियासी दबदबा तो रखते ही हैं, जातीय समीकरणों के लिहाज से भी मुफीद हैं. राजनैतिक विश्लेषक और बिलासपुर हाइकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव कहते हैं, ''अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी ही भाजपा के लिए एकमात्र सबसे बड़े फैक्टर हैं. वहीं, कांग्रेस मजबूत स्थानीय उम्मीदवारों पर दांव लगाने के साथ इस रणनीति पर आगे बढ़ रही है कि कुछ सीटों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और जीत (भाजपा के लिए) पहले से तय वाली स्थिति नहीं रहेगी.''

माना जा रहा है कि कांग्रेस खासकर बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा और कोरबा जैसी सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है. लेकिन रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, दुर्ग, सरगुजा और रायगढ़ आदि सीटों पर भाजपा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है. यह पूर्वानुमान कुछ हद तक 2019 के चुनावों के प्रदर्शन पर आधारित है जिसमें कांग्रेस ने बस्तर और कोरबा सीट जीती थी और कांकेर में उसे 6,914 वोटों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था.

बस्तर में कुल मतदान 68.3 फीसद रहा, जहां वोटिंग के दिन गलती से ग्रेनेड फटने के कारण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक कांस्टेबल की मौत हो गई और नक्सलियों के लगाए आइईडी में धमाके से सीआरपीएफ का एक सहायक कमांडेंट घायल हो गया. इस साल कांग्रेस ने बस्तर में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मैदान में उतारा है. उनका मुकाबला भाजपा के नए चेहरे महेश कश्यप से है. कांकेर में कांग्रेस ने दिवंगत कांग्रेस विधायक सत्यनारायण सिंह ठाकुर के बेटे बीरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है. 2019 के चुनाव में इसी सीट पर जीत हासिल करने में नाकाम रहे बीरेश पिछले पांच वर्ष से क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्हें सत्ता विरोधी लहर का फायदा होने की उम्मीद है. संभवत: इसी से मुकाबले के लिए भाजपा ने यहां भोजराज नाग को उतारा है, जिन्हें मौजूदा पार्टी सांसद मोहन मंडावी की जगह टिकट दिया गया है. राजनांदगांव में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उतारा है. माना जा रहा है कि वे न केवल अपनी जाति यानी कुर्मी वोट बैंक साधने में सफल रहेंगे बल्कि 2018 से 2023 के बीच बतौर मुख्यमंत्री कृषि क्षेत्र के लिए की गईं विभिन्न पहल के बलबूते अन्य कृषक समुदायों का भी समर्थन हासिल करेंगे. राजनैतिक हलकों में यह भी माना जा रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री बघेल खासे लोकप्रिय रहे, फिर भी उनके नेतृत्व में पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार दरअसल भाजपा के बेहतर चुनाव प्रबंधन और कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा थी. राजनैतिक पर्यवेक्षकों का यह भी कहना है कि इस सीट से फिर उम्मीदवार बनाए गए भाजपा के मौजूदा सांसद संतोष पांडे को कुछ हद तक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है.

इसके अलावा, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची काफी गहन मंथन के बाद सारे समीकरण ध्यान में रखकर तैयार की है. पार्टी ने प्रभावशाली साहू समुदाय के दो सदस्यों को मैदान में उतारा है जबकि भाजपा ने केवल एक को टिकट दिया है. इसको भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की विपक्षी दल की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. दरअसल, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आने वाला साहू समुदाय पारंपरिक रूप से भाजपा का वोट बैंक है और माना जाता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत में इसने अहम भूमिका निभाई थी. इसी तरह राज्य की आदिवासी आबादी में लगभग 55 फीसद हिस्सेदारी वाला गोंड समुदाय राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसे भाजपा के टिकट बंटवारे में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है. यहां तक, पार्टी ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित चार सीटों कांकेर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ में गैर-गोंड आदिवासियों को मैदान में उतारा है. कांग्रेस इस फैक्टर को सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है (कांग्रेस ने सभी चार सीटों पर गोंड उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है). तो दूसरी तरफ, भाजपा अपने चुनाव अभियान में राज्य को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय देने का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है.

दलों की अपनी अपनी ताकत

भारतीय जनता पार्टी

- मोदी फैक्टर. ऐसा लगता है कि पीएम मोदी का कोई मजबूत विकल्प नहीं है, यही उन्हें भाजपा का अकेला सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना देता है
- भाजपा की चाक-चौबंद चुनावी मशीनरी और संगठन जिसने हाल में छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाई. साथ ही पार्टी के पास ज्यादा आर्थिक ताकत है
- पिछले साल के विधानसभा चुनाव में किए गए प्रमुख वादे पार्टी को बढ़त दिलाते हैं

कांग्रेस

- कहा जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणापत्र महिला और युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है
- आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के बीच कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक मौजूद है
- टिकट वितरण में बेहतर सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है

भगवा विस्तार

मोदी लहर ने भाजपा के लिए 2014 और 2019 के चुनाव में जीत पक्की की, फिर भी कांग्रेस 2018 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही

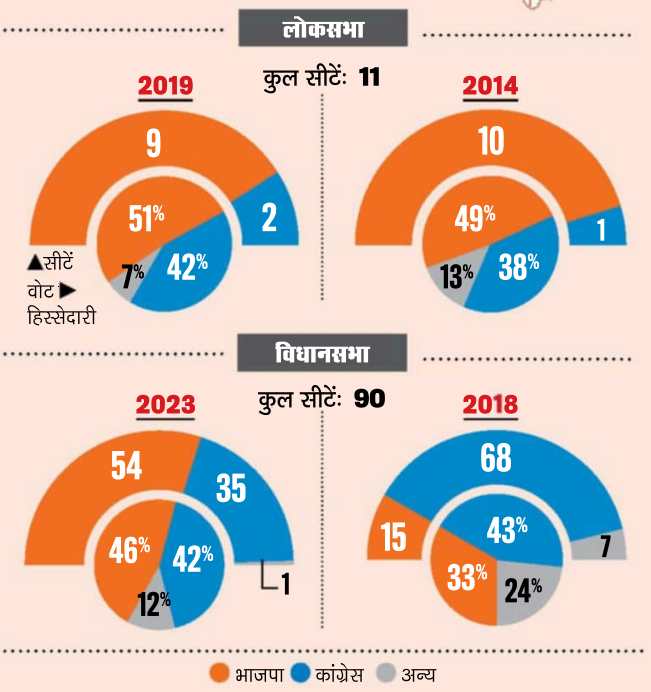

भगवा पार्टी वोट पाने के लिए ''2023 (विधानसभा चुनाव) के वादों को पूरा करने'' का हवाला देने के साथ अपने जांचे-परखे हिंदुत्व और 'ईसाई धर्मांतरण' कार्ड का भी इस्तेमाल कर रही है. जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन कथित तौर पर मुसलमानों के हाथों हिंदू यादव समुदाय के युवक की हत्या की घटना को बार-बार याद दिलाया जा रहा है, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा कहते हैं, ''भाजपा विष्णु देव साय सरकार के सत्ता संभालने के 100 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से किए वादों को पूरा करने का मुद्दा उठा रही है, जिसमें 3,100 रु. प्रति क्विंटल पर धान की खरीद, पिछले दो वर्षों के बोनस का भुगतान (धान खरीद पर), महतारी वंदन योजना का शुभारंभ (जिसमें पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रु. का भुगतान किया जाता है) आदि शामिल हैं. राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार के पिछले 10 वर्ष में काम को रेखांकित किया जा रहा है.'' उन्होंने दावा किया, ''अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो उसे प्रधानमंत्री पद के लिए किसी विश्वसनीय विकल्प के अभाव और छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.''

इस सबके बीच, कांग्रेस चुनावी रणनीति के मामले में भाजपा के ही नक्शेकदम पर चलती दिख रही है. 2023 के चुनाव से पूर्व भाजपा ने कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर प्रस्तावित महतारी वंदन योजना के लिए लोगों से फॉर्म भराने को कहा था. अब, कांग्रेस 2024 के अपने घोषणापत्र में महिलाओं के लिए घोषित एक लाख रुपए की वार्षिक योजना को लेकर यही तरकीब आजमा रही है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला के मुताबिक, ''वे सभी मुद्दे जो देश के अन्य राज्यों के लिए प्रासंगिक हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भी प्रासंगिक हैं. युवाओं को रोजगार देने में मोदी सरकार की विफलता, पर्यावरण मोर्चे पर नाकामी, महिलाओं को उनका हक न देना आदि जैसे कई मुद्दे हैं जो पार्टी इन चुनावों में उठा रही है. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो वादे किए हैं, वे पार्टी के लिए गेमचेंजर साबित होंगे, खासकर महालक्ष्मी योजना. इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति वर्ष एक लाख रुपए देने की गारंटी दी गई है.''

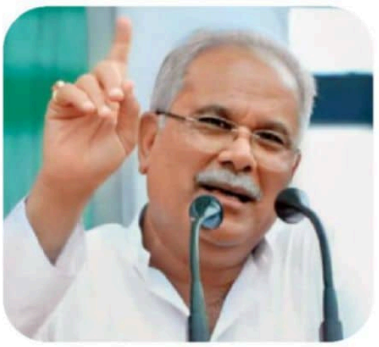

2023 का जनादेश भाजपा के रणनीतिक कौशल और कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा था. हालांकि भूपेश बघेल अब राजनांदगांव से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस का लोकप्रिय चेहरा हैं

बहरहाल, कांग्रेस के हौसले भले ही बुलंद हों, पार्टी के लिए दलबदलू एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. बिलासपुर की पूर्व मेयर वाणी राव, पूर्व राज्य महासचिव चंद्रशेखर शुक्ला, जगदलपुर की मौजूदा मेयर सफीरा साहू और बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में शुमार हैं. दूसरी तरफ, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने रायगढ़ और अंबिकापुर सीटों पर क्रमशः आदिवासी ईसाई इनोसेंट कुजूर और संजय एक्का को उतारकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि इससे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगने के आसार हैं. राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इसके पीछे शायद भाजपा और बसपा की मिलीभगत है.

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''भाजपा ने राज्य में हमेशा अपने राजनैतिक आइक्यू (बुद्धिमत्ता के स्तर) का इस्तेमाल किया है. लेकिन टिकट वितरण को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अधिक ईक्यू (भावनात्मक स्तर) दर्शाया है.'' वैसे, इसमें कोई दो-राय नहीं कि जीत के लिए दोनों के सही संतुलन की जरूरत होगी. ■

‘भोट जरूरी है मगर पेट उससे ज्यादा’

बिहार के कोसी अंचल में ऐन चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर यहां के मजदूर फसल कटाई के लिए पंजाब का रुख कर रहे. स्टेशन बिहार छोड़कर जाने वालों से अटे पड़े. पेट की आग मताधिकार पर पड़ रही भारी

पुष्यमित्र

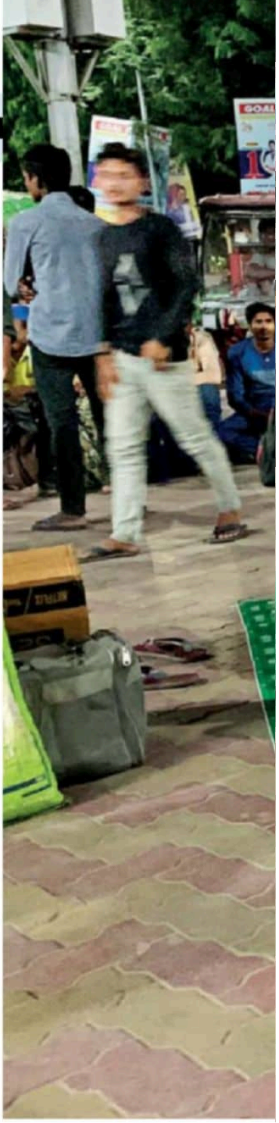

सभी फोटोः पुष्यमित्र

रात के दस बजे हैं. बिहार के कोसी अंचल के सहरसा जंक्शन पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं. स्टेशन परिसर में कोई सीढ़ियों और डिवाइडरों पर बैठा है तो कोई पन्नी बिछाकर सो गया है. इन सभी लोगों को रात तीन बजे से सुबह पौने नौ बजे के बीच चलने वाली तीन ट्रेनों, क्रमशः जनसाधारण एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और जनसेवा एक्सप्रेस पर सवार होकर दिल्ली और पंजाब की तरफ जाना है. रोजी-रोजगार के लिए यहां से हजारों किमी दूर जाने का इरादा करके यहां पहुंचे ये यात्री जिन इलाकों के रहने वाले हैं, वहां तीसरे चरण में मतदान होना है. जाहिर है कि अभी सफर को निकले ये यात्री वोटिंग के दिन तक लौटकर नहीं आएंगे. वह इनकी प्राथमिकता में नहीं है.

सहरसा के बिहरा गांव के यही कोई 27-28 साल के आनंदी यादव इसी स्टेशन परिसर में खुले आकाश के नीचे पॉलिथीन बिछाकर सपरिवार बैठे हैं. अगर वे अभी चले जाएंगे तो उनके वोट का क्या होगा? इस सवाल पर वे सकुचा जाते हैं, फिर कहने लगते हैं, ‘‘मजबूरी है, इसलिए जा रहे हैं. पंजाब में गेहूं कटनी का यही सीजन है. अभी वहां दोनों जने (पति-पत्नी) 20-25 दिन काम कर लेंगे तो 30,000-35,000 कमा कर लौट आएंगे. फिर रोपनी के टैम पर ही ऐसा चांस मिलेगा.’’

इसी मजबूरी की वजह से इन दिनों कोसी अंचल के हजारों लोग रोज ट्रेन और बसों पर लद कर मजदूरी करने पंजाब की तरफ जा रहे हैं. गेहूं की कटनी बिहार में भी हो रही है. यहां के इलाकों में भी खेतों में कहीं कटे गेहूं के गट्ठे दिखते हैं, कहीं थ्रेशर से गेहूं की मड़ाई होती दिखती है. संयोग ही है कि हर बार लोकसभा चुनाव के वक्त उत्तर भारत के इलाकों में गेहूं की फसल तैयार हो रही होती है. वोटों की फसल काटने की कोशिश में जुटे कई राजनेताओं की तस्वीर हमें गेहूं की बालियों और हंसिया के साथ मीडिया में दिखती है. मगर उत्तर बिहार के वोटरों के लिए गेहूं की तैयारी का यह मौसम मौका है एक बार में बड़ी आमदनी कर लेने का, ताकि यह पैसा साल भर किसी न किसी तरह काम आए. इसलिए भले उनका वोट न पड़े, वे मौका नहीं गंवाना चाहते.

कोसी अंचल के मतदाता आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं? यह जानने के लिए इस संवाददाता ने अगली सुबह जनसेवा एक्सप्रेस से मजदूरों के साथ यात्रा की. इसी ट्रेन पर सवार मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज के वीरेंद्र कहते हैं, ‘‘भोट भी जरूरी है, मगर पेट उससे जादा जरूरी है. इसीलिए जा रहे हैं. अभी 15 दिन कमाने का सीजन है. इस सीजन को छोड़ देंगे तो साल भर परोबलम होगा. सरकार तो कभी भी इलक्सन करवा देती है, सरकार भी नहीं सोचती कि यह कमाने-खाने का सीजन है. अभी भोटिंग नहीं करवाए.’’

रोजी-रोटी की फिक्र सहरसा जंक्शन पर देर रात प्रवासी मजदूरों की भीड़

इसी ट्रेन से लुधियाना जा रहा सहरसा के बैजनाथपुर का जत्था भी सवार है. उसी में शामिल बहादुर रजक कहते हैं, ''आप ही बताइए, हम लोग करें तो क्या करें. मजदूरी करके खाते हैं, ऊ भी छोड़ दें?'' उनके साथ जा रहे बीजो मंडल कहते हैं, ''जदी मजदूरी घर के पास मिल जाता तो हम काहे जाते. यहां गेहूं कटनी में एक दिन में 200-250 मिलेगा. वहां 15 दिन में 15,000 कमा लेंगे. घर में दूसरा लोग तो है ही, ऊ भोट डाल देगा.'' उनके पास खड़े जानकीनगर वे वरुण चौधरी बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं, ''हमारा भोट भी घर के लोग डाल देंगे. इसलिए कोई परवाह नहीं.''

मजदूरों से भरी इस ट्रेन में साफ-सफाई का हाल देखिए: शौचालय के पास गंदगी, बेसिन में कचरा और शौचालय शौच से उफन रहे हैं. ज्यादातर शौचालयों की खिड़कियां टूटी हैं. अंदर शौच कर रहा आदमी बाहर से नजर आता है. मुरलीगंज से जालंधर जा रहे कन्हैया झा कहते हैं, ''जहां से ट्रेन शुरू हुई है, वहीं से ऐसा हाल है. लेबर लोगों की ट्रेन है न, रेलवे भी इसका टेंशन नहीं लेता. गंदा है तो है, लेबर लोग बिना शिकायत किए चला ही जाएगा.''

सहरसा जंक्शन पर टिकट बुकिंग का काम देखने वाले स्टाफ के एक सज्जन अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं, ''आजकल थोड़ी कम है. 10 अप्रैल तक तो इतनी भीड़ रहती थी कि सहरसा में यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी.'' इसी अवधि में दूसरे राज्यों से मतदाताओं को उनके घर पहुंचाने वाली इलेक्शन एक्सप्रेस खाली चल रही है. सहरसा स्टेशन पर ऐसी ही ट्रेन बिल्कुल खाली दिखी.

सहरसा इस इलाके का ऐसा स्टेशन है, जहां पूरे कोसी अंचल से मजदूर ट्रेन पकड़ने आते हैं. जनसेवा एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, पुरबिया एक्सप्रेस, गरीब रथ और हमसफर एक्सप्रेस जैसी दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहां से चलती या गुजरती हैं. अररिया के जोगबनी से चलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस भी मजदूरों की ट्रेन मानी जाती है.

एक बड़े अखबार में छपी खबर के मुताबिक इन ट्रेनों में रोजाना 3,000 से ज्यादा मजदूर दिल्ली और पंजाब की तरफ जाते हैं. रेलवे के सूत्रों के हवाले से अखबार लिखता है, इन ट्रेनों में 6 से 10 अप्रैल के बीच सहरसा स्टेशन से 12,482, बनमनखी से 2,869 और पूर्णिया कोर्ट से 9,342 जनरल टिकट बिके. इन पांच दिनों में लगभग 25,000 लोगों ने दिल्ली और पंजाब की यात्रा की और रेलवे को करीब 80 लाख रु. प्राप्त हुए.

इन दिनों लोग ट्रेन से ही नहीं, बसों से भी बड़ी संख्या में दिल्ली, पंजाब और दूसरे राज्यों का सफर कर रहे हैं. सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में छोटे-छोटे शहरों से इन इलाकों के लिए कई बसें चल रही हैं. इनके अलावा पंजाब और दूसरे राज्यों से किसान बसें भेजते हैं, ताकि इन मजदूरों को लाया जा सके. ये बसें भी मजदूरों को ठूंस-ठूंसकर ले जाती हैं.

ऐन चुनाव के वक्त हो रहे इस पलायन की वजह से मतदान भी प्रभावित हो रहा है. बिहार

पांच लोकसभा सीटों का आकलन

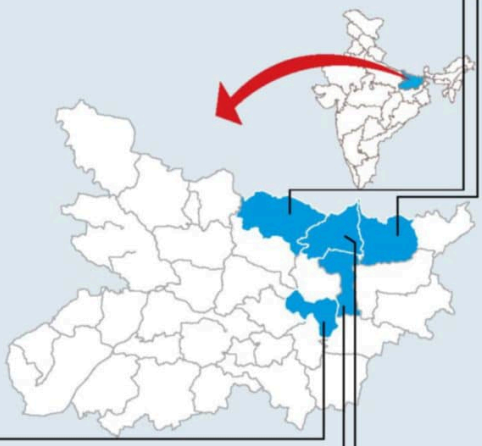

अररिया

मुख्य मुकाबला: भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह और राजद के शाहनवाज आलम के बीच

2019

भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह जीते, राजद के सरफराज आलम दूसरे नंबर पर

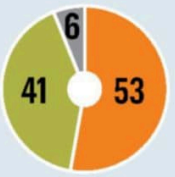

2018 (उपचुनाव)

राजद के सरफराज आलम जीते, भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह दूसरे नंबर पर

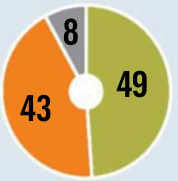

2014

राजद के तस्लीमुद्दीन जीते, भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह दूसरे, जद (यू) के विजय कुमार मंडल तीसरे स्थान पर

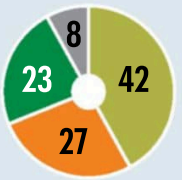

चुनावी मुद्दा सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मक्का और जूट पर आधारित उद्योग लगें

खगड़िया

मुख्य मुकाबला: 1. लोजपा(रा.): राजेश वर्मा. 2. सीपीएम: संजय कुशवाहा

2019

लोजपा के महबूब अली कैसर, 2. वीआइपी के मुकेश सहनी

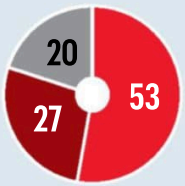

2014

लोजपा के महबूब अली कैसर 2. राजद की कृष्णा यादव

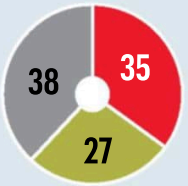

2009

जद (यू) के दिनेशचं यादव 2. राजद के रवींद्र कुमार राणा

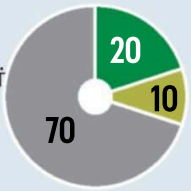

चुनावी मुद्दा एनएच 107 दू लेन का निर्माण, कोसी नदी पर डेंगराही पुल का निर्माण

मधेपुरा

मुख्य मुकाबला: जद (यू): दिनेशचंद्र यादव. 2. राजद: प्रो. कुमार चंद्रदीप

2019

जद (यू) के दिनेशचंद्र यादव जीत, 2. राजद के शरद यादव 3. जनाधिकार पार्टी के पप्पू यादव

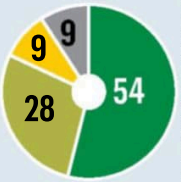

2014

राजद के पप्पू यादव, 2. जद (यू) के शरद यादव, 3. भाजपा के विजय कुमार सिंह

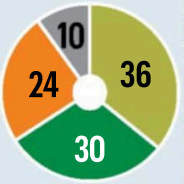

2009

जद (यू) के शरद यादव, 2. राजद के प्रो. रवींद्र चरण यादव, 3. कांग्रेस के तारानंद सदा

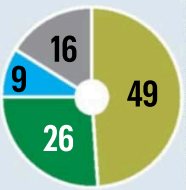

चुनावी मुद्दा एनएच 106 और 107 का निर्माण पूरा करना, सहरसा में रेल ओवरब्रिज, केंद्रीय विद्यालय

सुपौल

मुख्य मुकाबला: 1. जद (यू): दिलेश्वर कामत. 2. राजद: चंद्रहास चौपाल.

2019

1. जद (यू) के दिलेश्वर कामत, 2. कांग्रेस की रंजीत रंजन

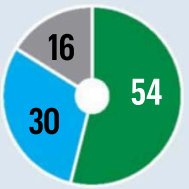

2014

1. कांग्रेस की रंजीत रंजन, 2. जद (यू) के दिलेश्वर कामत, 3. भाजपा के कामेश्वर चौपाल

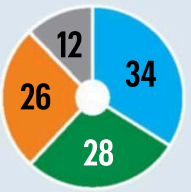

में पहले चरण के मतदान में पचास फीसद से भी कम वोट पड़े. पहले चरण वाले इलाकों में भी कई तरह का पलायन हो रहा था. 7 अप्रैल को जमुई जिले के चरकापातर गांव के वीरेंद्र यादव मिले जो सौ से अधिक गायों को लेकर दरभंगा जा रहे थे. उन्हीं के शब्दों में, ''गर्मियों में हमारे इलाके में पानी की कमी हो जाती है. इसलिए हर साल इस समय पशुओं को लेकर करीब 175 किमी दूर दरभंगा की तरफ निकल जाते हैं.'' उनके इलाके में 19 अप्रैल को मतदान होना था. ऐसे कई जत्थे इन दिनों दक्षिण से उत्तर बिहार की तरफ आते दिखते हैं. वे भी अपने यहां वोट नहीं डाल पाएंगे.

दक्षिण बिहार के इलाकों में नवंबर-दिसंबर में बड़ी संख्या में लोग ईंट भट्ठों में काम करने चले जाते हैं. वे अभी भी पथाई का काम कर रहे हैं. चुनाव में उनके भी शामिल होने की संभावना कम है. इसके बावजूद बिहार के नेता पलायन को गंभीर मसला मानते ही नहीं. मधेपुरा लोकसभा सीट से जद (यू) के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद दिनेशचंद्र यादव पलायन के सवाल पर कहते हैं, ''गेहूं कटनी का सीजन खत्म होने वाला है, मुझे उम्मीद है कि विवेकी मजदूर अब वापस लौट आएंगे. जो नहीं आएंगे, उनके लिए क्या कर सकते हैं? जितने लोग होंगे उन्हीं के मतदान से ही फैसला होगा.'' पलायन रोकने के लिए आपके पास कोई एजेंडा है? इस पर वे कहते हैं, ''ई सब

झंझारपुर

मुख्य मुकाबला: जद (यू) के रामप्रीत मंडल, वीआइपी के सुमन कुमार महासेठ और बसपा के गुलाब यादव के बीच त्रिकोणीय संघर्ष

2019

जद (यू) के रामप्रीत मंडल जीते, राजद के गुलाब यादव दूसरे नंबर पर

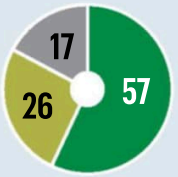

2014

भाजपा के बीरेंद्र कुमार चौधरी जीते, राजद के मंगनीलाल मंडल दूसरे और जद (यू) के देवेंद्र प्रसाद यादव तीसरे स्थान पर

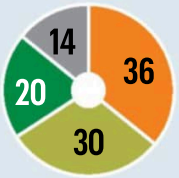

2009

जद (यू) के मंगनीलाल मंडल जीते, राजद के देवेंद्र प्रसाद यादव दूसरे और कांग्रेस के कृपानाथ पाठक तीसरे स्थान पर

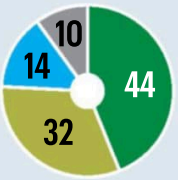

चुनावी मुद्दा केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, राजनगर और बलिराजगढ़ को पर्यटन स्थल का दर्जा

2009

जद (यू) के विश्वमोहन कुमार, कांग्रेस की रंजीत रंजन

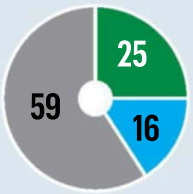

चुनावी मुद्दा कोसी-मेची लिंक परियोजना, लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन

● जद (यू) ● कांग्रेस ● भाजपा ● जनाधिकार पार्टी ● लोजपा (रा.) ● राजद ● वीआइपी

(वोट %)

ग्राफिक: असित रॉय

पार्टी ऑफिस में पूछिए, वही लोग एजेंडा और घोषणापत्र बनाते हैं. हम नहीं बनाते.''

अररिया से लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पटना साइंस कॉलेज में व्याख्याता अखिलेश कुमार कहते हैं, ''कोसी-सीमांचल में पलायन के कई कारण हैं. इनमें प्रति व्यक्ति जोत का बहुत कम होना, बाढ़, रोजगार और शिक्षा की कमी, उद्योगों का अभाव आदि प्रमुख हैं. आजादी के बाद से अब तक किसी भी नेता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. मैंने इस बार इसे चुनावी मुद्दा बनाया है.''

दाना-पानी की खातिर
जनसेवा एक्सप्रेस से पंजाब जाते बिहारी मजदूर

बिहार में पलायन को सामान्य पलायन की तरह नहीं देखा जा सकता. यहां लोग बहुत कम आय की खातिर पलायन करते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज ने फरवरी, 2020 में यूपी और बिहार में पलायन को लेकर अध्ययन किया था. उसके मुताबिक, बिहार में हर दूसरे परिवार का कोई न कोई सदस्य पलायन करता है. इनमें से 90 फीसद बाहर जाकर अकुशल मजदूरी का काम करते हैं और इनकी मासिक आमदनी 2,000-2,500 रुपए महीना भी नहीं होती. सेंटर फॉर माइग्रेशन अफेयर्स की एक स्टडी के मुताबिक, बिहार से 55 फीसद पुरुषों का पलायन रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण होता है. बाहर जाने वाले अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं. कोरोना में लॉकडाउन के वक्त बड़ी संख्या ये मजदूर पैदल ही बिहार लौटे तो पलायन की विभीषिका की असली तस्वीर सामने आई. उस वक्त राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, तकरीबन 25 लाख मजदूर बिहार लौटे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब इन मजदूरों के सामने कहा था कि आधी रोटी खाएंगे, बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे. इन मजदूरों को राज्य में रोजगार मुहैया कराने की योजना बनी पर प्रयास नाकाम रहे. बीच कोरोना में मजदूर फिर पलायन करने लगे.

राज्य में हुई जाति आधारित गणना में भी यह बात सामने आई कि राज्य के 53 लाख लोग अस्थायी तौर पर बिहार से बाहर प्रवास करते हैं. जाहिर है, इनमें काफी बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों की होगी.

कोसी सीमांचल में मजदूरों के मामलों पर काम करने वाले आशीष रंजन पूरे मसले को इस तरह समझाते हैं: ''लोकसभा चुनाव में गांव के लोगों की रुचि कम होती है क्योंकि उम्मीदवार उनके व्यक्तिगत परिचय के नहीं होते, जैसे पंचायती राज चुनाव में होते हैं. और यह सचमुच इस इलाके के मजदूरों की कमाई का मौसम है. धान की बुआई, कटनी और गेहूं की कटनी का सीजन उनकी खास कमाई का होता है. बिहार जैसे राज्यों के लिए जरूरी है कि यहां चुनाव होली, दशहरा या दीवाली, छठ के आसपास हो, जब मजदूर लौटकर आते हैं.''

पलायन के बड़े सवाल पर वे कहते हैं, ''बिहार में खेती का सेक्टर पहले से ओवरलोडेड है. मजदूरी ठीक भी हो तो यहां सबके लिए काम नहीं. यहां इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक से नहीं हुआ. उद्योग भी सर्विस सेक्टर में विकसित हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास नहीं हुआ. इसलिए रोजगार नहीं है. पलायन मजबूरी है.''

बिहार में तीसरे चरण के मतदान वाली सीटों सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और झंझारपुर में भीषण पलायन है. वैसे तो इस पूरे इलाके में घूमने पर कहीं चुनावी गहमा-गहमी नहीं दिखती. मुद्दों के नाम पर भी सन्नाटा है. ऐसे में पलायन पर बात हो भी तो कैसे.

मगर ऐन चुनाव के वक्त पलायन मतदान को भी प्रभावित कर रहा है. हाल में बिहार पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी बिहार में कम मतदान को लेकर चिंता जाहिर की थी. 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में जम्मू-कश्मीर के बाद सबसे कम वोट पड़े थे. उन्होंने हैरत जाहिर करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जननी माने जाने वाले बिहार में मतदान को लेकर इतनी उदासीनता क्यों हैं. वे इसके कारणों की पड़ताल नहीं कर पाए. सच यही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गेहूं की कटनी का मौसम बिहार के मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर करता है और पलायन कभी चुनावी मुद्दा नहीं बनता.■

● *इलेवन रूल्स फॉर लाइफ* लिखने के पीछे आपकी सोच क्या थी?

मुझे लगा कि युवाओं को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, इस मामले में उन्हें रास्ता दिखाए जाने की बहुत जरूरत है. भटकाव और तमाम आकर्षणों से भरी इस दुनिया में अपना फोकस खो देना बहुत आसान है. एक और रोमांटिक नॉवेल एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो बढ़िया रहता लेकिन उससे सीखने की वह जरूरत पूरी नहीं होती जिसकी इस समय में इस पीढ़ी को है. शायद इसीलिए मुझे इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक का ख्याल आया जो मजेदार और रोचक हो.

● जीवन में इस तरह के नियमों की जरूरत क्यों है?

हम असल में अधूरा जीवन जीते हैं. न तो अपनी सेहत को लेकर अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं, और न ही अपने करियर में पूरी तरह आगे बढ़ पाते हैं. यह सब होता है हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन की कमी से. इन 11 नियमों का पालन किया जाए तो जीवन को एक लक्ष्य और दिशा मिलती है. ये नियम मेरे लिए कारगर रहे हैं और उम्मीद है कि पाठकों के लिए भी काम के साबित होंगे.

● शुरू में किताब के परिचय में ही आपने पढ़ने का महत्व बताया है. लोगों की पढ़ने की आदत क्यों छूट रही है?

पढ़ना इसलिए छूटता जा रहा है क्योंकि वीडियो देखना पढ़ने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान और मजेदार होता है. पढ़ने से एकाग्रता और कल्पनाशीलता विकसित होती है. पढ़ना छोड़ते ही आपका दिमाग रील्स देखने का आदी हो जाएगा. किसी भी फायदेमंद आदत की तरह आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है, जैसे जिम जाने की आदत.

● और कौन-से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप?

मैं एक लव स्टोरी के बारे में सोच रहा हूं. एक सेल्फ हेल्प बुक के बाद हो सकता है मेरे पाठकों को भी मुझसे एक लव स्टोरी की उम्मीद हो, हालांकि मेरा दिल भी यही लिखने का हो रहा है. *इलेवन रूल्स फॉर लाइफ* के बाद एक रास्ता मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर काम करने का भी खुला है, जिसे लेकर मेरी व्यस्तता इस दिनों काफी ज्यादा रही है.

– अमित दीक्षित

सवाल+जवाब

अब जीने के कायदों पर किताब

अपनी नई किताब *इलेवन रूल्स फॉर लाइफ* के साथ **चेतन भगत** ने की है नॉन-फिक्शन की दुनिया में वापसी

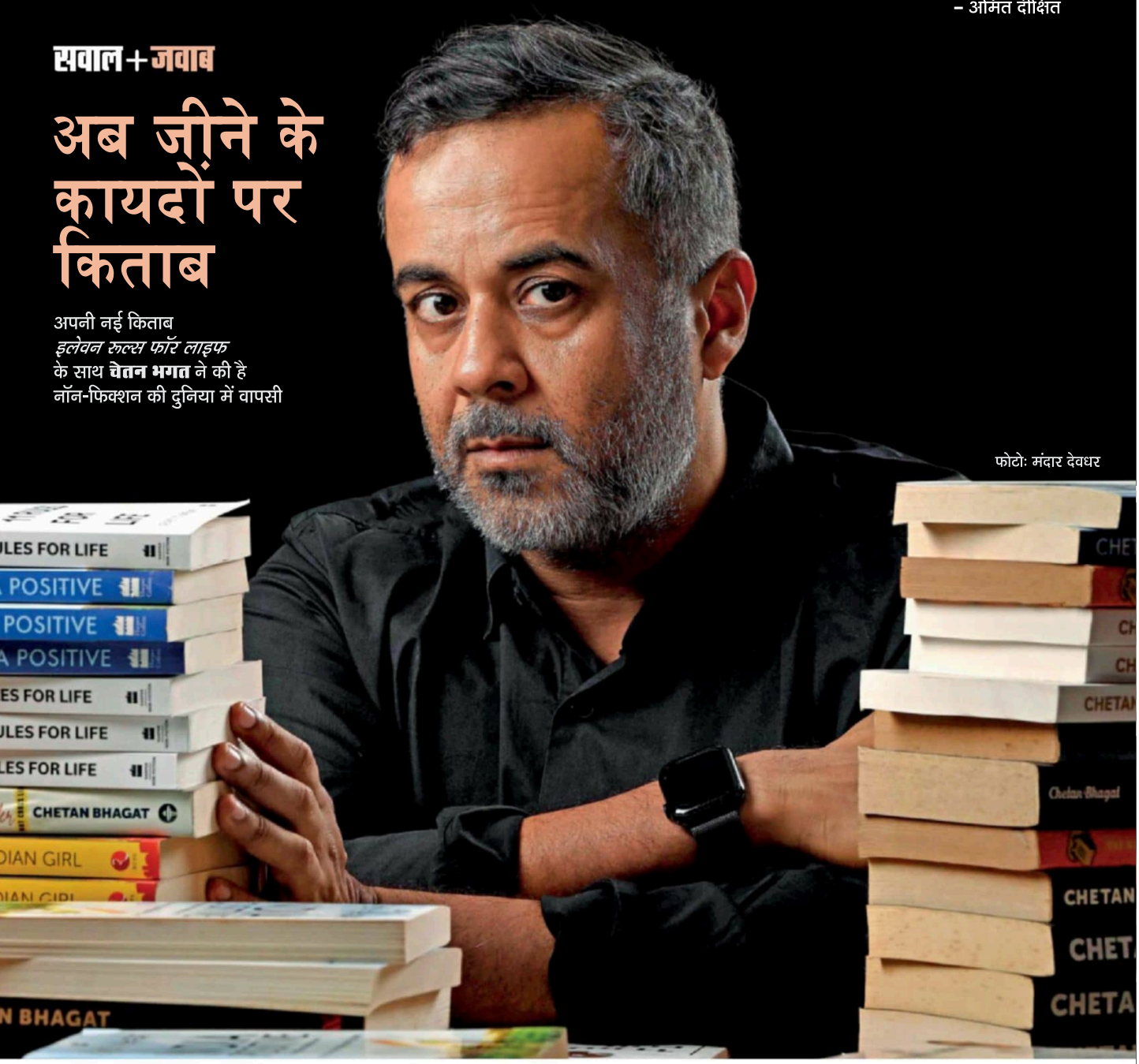

फोटोः मंदार देवधर

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से, कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

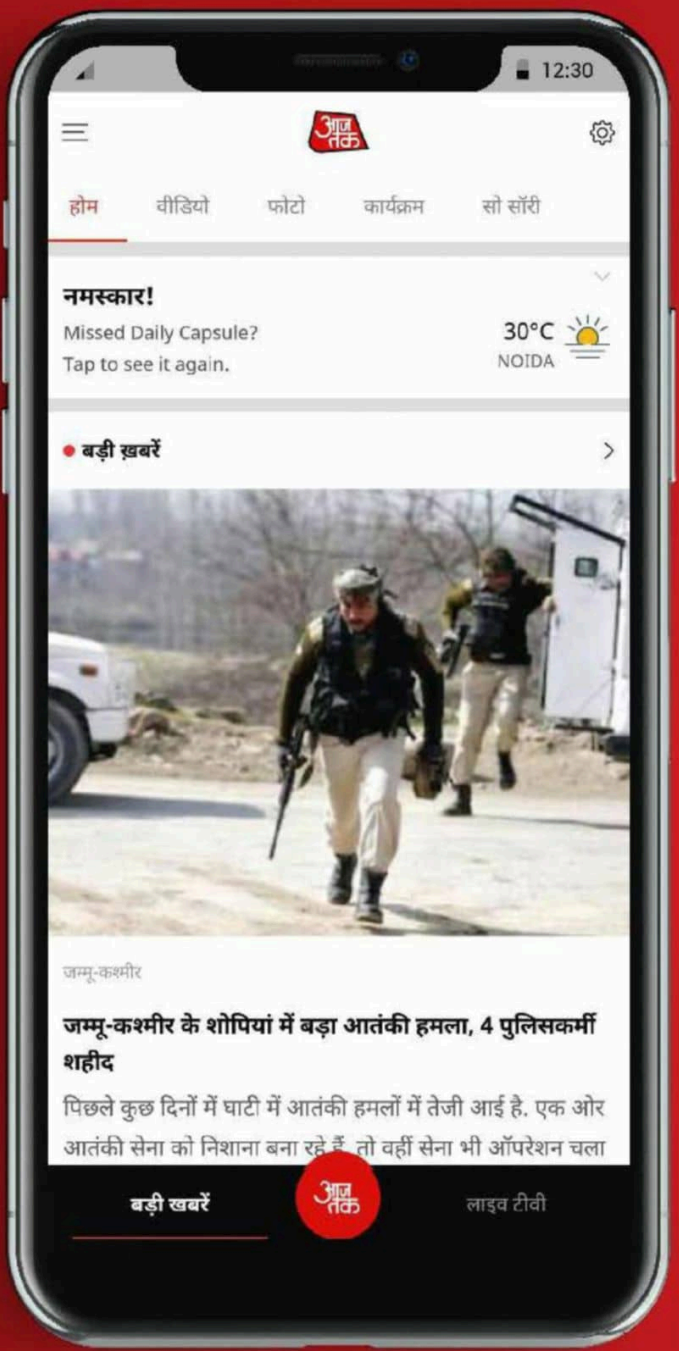

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE